

राजस्थान सुजस



1150+ रु प्रति
500 रु घरे
75-100 रु प्रति रु प्रति

चिरंजीव
25 लाख रु

चिरंजीव
पुलित पीला
10 लाख रु

सर्वपूर्ण घरे किने
किताबतें
फ्री राशन

शहरी
125 दिन का रोजगार

1000 रु प्रति
पेंशन

मनरेगा
रोजगार

2000 रु प्रति
विजली फ्री

कामधेनु
40 हजार रु

प्रतिगार
100 युनिट विजली फ्री

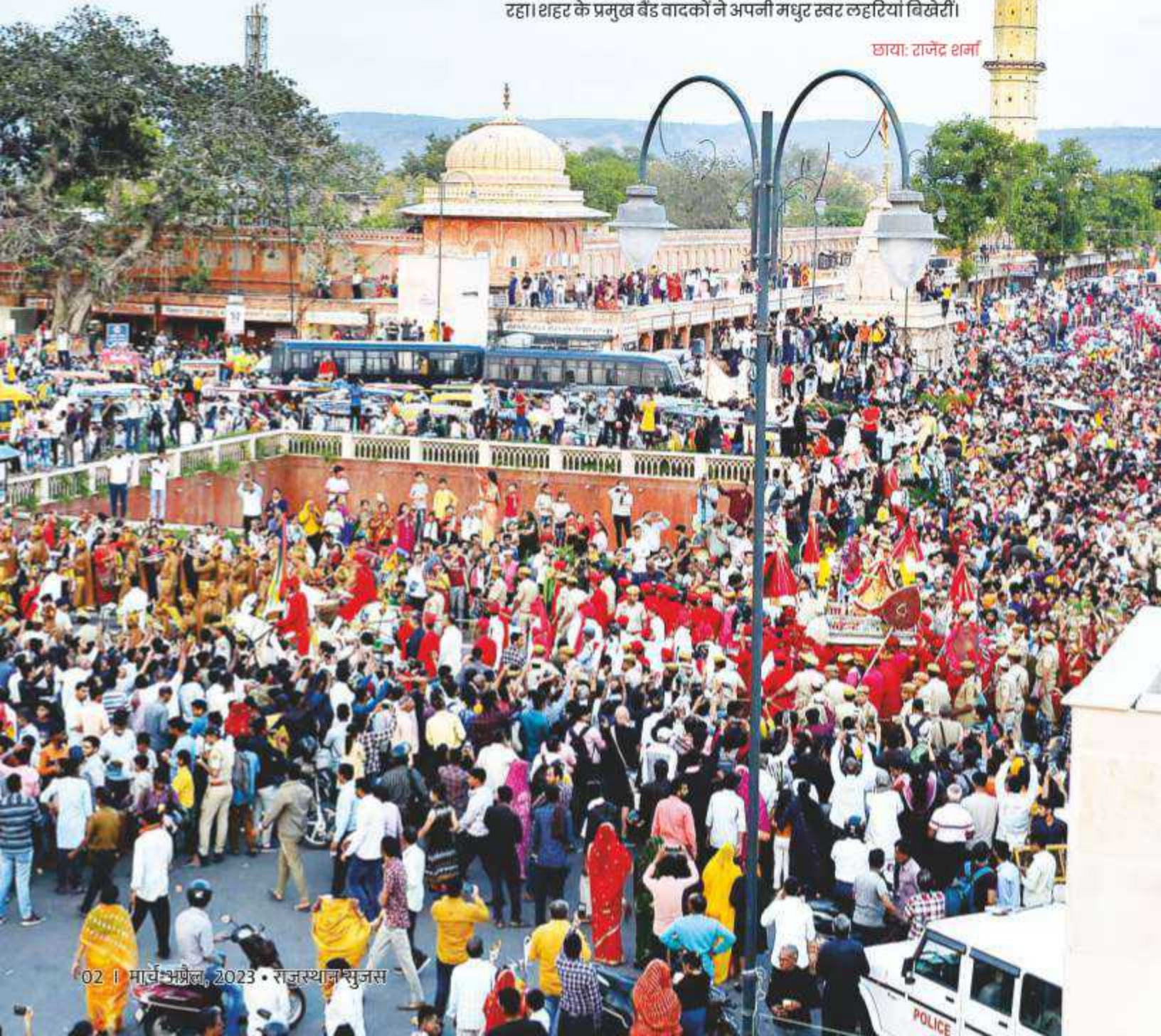
राहत आपके द्वार

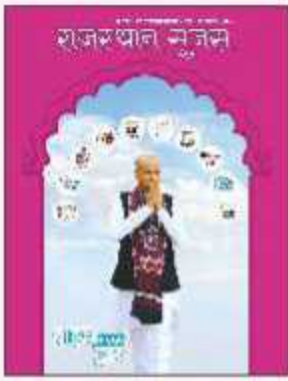


गणगौर की सवारी

चेन्नई शुकल तृतीया को जयपुर शहर में शाही लवाजमे के साथ परंपरागत गणगौर की सवारी निकली। लोक कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति से राजस्थानी लोक संस्कृति को साकार किया। गणगौर की सवारी में पारंपरिक रूप से सजे हुए रथ, घोड़े और ऊंट का लवाजमा भी रहा। शहर के प्रमुख बैंड वादकों ने अपनी मधुर स्वर लहरियां बिखेरीं।

छाया: राजेंद्र शर्मा





प्रधान सम्पादक
पुरुषोत्तम शर्मा

सम्पादक
अलका सक्सेना

सह-सम्पादक
डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा

उप-सम्पादक
**सम्मत राम चान्दोलिया
आशाराम खटीक**

सहायक सम्पादक
महेश पारीक

आवरण छाया
सूजस

राजस्थान सुजस में प्रकाशित सामग्री में व्यक्त विचार लेखकों के अपने एवं आंकड़े परिवर्तनशील हैं। आवश्यक नहीं कि शासन उनसे सहमत हो। सुजस में प्रकाशित सामग्री का विभाग किसी भी रूप में उपयोग कर सकेगा।

ग्राफिक डिजाइनिंग
प्रिन्ट 'ओ' लैण्ड

सम्पर्क
सम्पादक

राजस्थान सुजस (मासिक)
सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
सचिवालय, जयपुर-302005
मो नं. 98292-71189
94136-24352

e-mail :
editorsujas@gmail.com
publication.djpr@rajasthan.gov.in
Website :
www.djpr.rajasthan.gov.in

सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, राजस्थान का मासिक

वर्ष : 32 अंक 03-04

इस अंक में

मार्च-अप्रैल(संयुक्त)क, 2023

लोक जीवन	02
संपादकीय	04
महंगाई राहत कैंप	05
सामयिकी	11
वसंत की कूंची	32
बदली नारी की दुनिया	37
चिरंजीवी योजना	38
Women Empowerment	40
उच्छब साहित्य टो	42
राजस्थान साहित्य उत्सव	44
राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल	46
अंबेडकर जयंती	48
होलिया में उड़े रे गुलाल	50
शेखावाटी की होली	53
बीकानेर की होली	55
गौशालाएं बन रही आत्मनिर्भर	57
भरतपुर का 290वां स्थापना दिवस	58
धरोहर	59
तब और अब	60



राजस्थान सुजस के आगामी अंक के लिए मौलिक, अप्रकाशित सामग्री भिजवायें।
कृपया अपने आलेख एवं फोटोग्राफ सम्पादक को e-mail : editorsujas@gmail.com पर अथवा डाक से भेजें।

जनकल्याणकारी राज्य की आमजन तक सुगम पहुंच



वसंत की सुगंधित बयार, पल्लित बहार, अमर की गूंज, कोयल की कुहूक और मयूर के नृत्य के बीच बचत, राहत और बहत की थीम पर आधारित सर्वहितकारी बजट ने इस बार के वसंत और खुशियों की होली को विस्तारित कर और खुशनुमा बना दिया है।

संवेदनशील, पारदर्शी और जवाबदेह सुशासन के साथ राज्य सरकार द्वारा की गई एक से बढ़कर एक घोषणाओं ने प्रदेशवासियों के जन-जीवन को हर्षित एवं प्रफुल्लित कर दिया है। राज्य सरकार द्वारा आमजन को निःशुल्क शिक्षा, पानी, बिजली, राशन, स्वास्थ्य बीमा, जांच, दवा, उपचार के साथ लगभग एक करोड़ लोगों को पेंशन, नए स्कूल, कॉलेज, बुनियादी ढांचा, सस्ते गैस सिलेंडर आदि जनहितैषी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। प्रदेशवासियों को कानून बनाकर स्वास्थ्य का अधिकार देने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है।

देश के सबसे बड़े प्रदेश में 19 नए जिलों व 3 संभागों के नवनिर्माण से अब जिलों की संख्या 50 एवं संभाग 10 हो गए हैं। जिला अपेक्षाकृत छोटा होने से प्रशासन, प्रबंधन एवं कानून व्यवस्था पर निगरानी एवं नियंत्रण अधिक प्रभावी, सहज व सुगम हो जाता है। जिला मुख्यालय नजदीक होने से आमजन की समस्याओं का निराकरण भी स्थानीय स्तर पर ही संभव हो सकेगा।

राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से समाज में सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। वर्ष 2030 तक विकसित राजस्थान की परिकल्पना को साकार करता अपना राजस्थान आज कई मायनों में देश के अग्रणी राज्यों की श्रेणी में शुमार है। स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट-2022 में राज्य की रैंकिंग में जबर्दस्त सुधार हुआ है और राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर 15वें पायदान से आगे बढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।

हाल में जन उपयोगी योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार द्वारा महंगाई राहत कैंप के रूप में अभिनव पहल की गई है। इस पहल से जनकल्याणकारी योजनाएं ज्यादा प्रभावी तरीके से जरूरतमंद लोगों तक पहुंचेंगी।

उत्सवों की उल्लासपूर्ण रंगत को प्रसारित करता सुजस का यह मार्च—अप्रैल संयुक्त सुधी पाठकों के हाथ में सौंपते हुए आनंदानुभूति प्रतीत हो रही है।

अभिवादन और मंगलकामनाओं सहित!

(पुरुषोत्तम शर्मा)
प्रधान संपादक



महंगाई राहत कैंप

मिशन मोड पर हो रहे हैं आमजन के काम

2,000 स्थायी महंगाई राहत कैंप
राजकीय कार्यालयों और
सार्वजनिक स्थलों पर

11,283 ग्राम पंचायतों और
7,500 वार्डों में दो दिवसीय
शिविरों का आयोजन

आदिमयुग की कबीलाई संस्कृति से लेकर आज की आधुनिक मानव सभ्यता के विकासक्रम में शासन अलग-अलग विशिष्ट रूपों में प्रणाली के तौर पर विकसित और स्थापित होता आया है। इस विकासक्रम में लोककल्याण की भावनाओं की अवधारणा सबसे प्रबल प्रेरक की भूमिका में रही है। लोक-कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए व्यापक सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है। इनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार तथा वृद्धावस्था में पेंशन आदि की व्यवस्था शामिल है। नागरिकों को सभी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। ऐसा राज्य संपूर्ण जनता को केंद्र मानकर कार्य करता है। कल्याणकारी राज्य सरकारी संस्थाओं को स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए धन देते हैं, साथ ही व्यक्तिगत नागरिकों को प्रत्यक्ष लाभ देते हैं। इस तरह राज्य नागरिकों की आर्थिक एवं सामाजिक उन्नति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह अच्छे जीवन की न्यूनतम जरूरतों को खुद जुटा पाने में असमर्थ नागरिकों की सहायता करने जैसे सिद्धांतों पर आधारित है।

महेश पारीक
सहायक जनसंपर्क अधिकारी

प्लेटो, अरस्तु और चाणक्य ने भी लोककल्याणकारी राज्य की अवधारणा को महत्व दिया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में तो शासक-प्रशासक के कार्यों में लोगों के कल्याण को सर्वोपरि माना गया है।

20वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध बुद्धिजीवियों में से एक ब्रिटिश अर्थशास्त्री जेफ्री कॉथर ने इस बात की बहुत प्रभावशाली तरीके से पैरवी की है कि "नागरिकों के अधिकार के रूप में इन्हें स्वस्थ बनाए रखने के लिए पर्याप्त भोजन की व्यवस्था की जानी चाहिए। निवास, वस्त्र आदि के न्यूनतम जीवन-स्तर की ओर से उन्हें चिंता रहित होना चाहिए। उन्हें शिक्षा का पूर्णतया समान अवसर प्राप्त होना चाहिए और बेरोजगारी, बीमारी, वृद्धावस्था और दुख से उनकी रक्षा की जानी चाहिए।"

आर्थिक विकास के लिए लोगों के जीवन में बेहतरी और शिक्षा को जन-जन तक पहुंचाने की क्या अहमियत है यह आर्थिक शोध और व्यवहार में साबित हो



चुका है। सरकार ने जहां भी स्वास्थ्य मद में थोड़ा बहुत भी जोर दिया है वहां मृत्युदर और जन्मदर में कमी आई है। सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली पेंशन लाखों विधवाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों की कठिन जिंदगी में मददगार साबित रही है। बीसवीं सदी में तकरीबन सभी औद्योगिक देशों में भी बड़े पैमाने पर सार्वजनिक सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा का विस्तार हुआ है।

राजस्थान सरकार ने शुरू से ही जनकल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए एक से बढ़कर एक जनकल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। अब इनका सफल क्रियान्वयन राज्य सरकार का मुख्य ध्येय है और इन जन उपयोगी योजनाओं को आमजन के द्वार तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार ने महंगाई राहत कैप के रूप में अभिनव पहल की है।

राज्य की जनकल्याणकारी और महंगाई से राहत दिलाने वाली योजनाओं को लेकर राज्य सरकार शहरी वार्डों से लेकर गांवों में शिविर लगा रही है। प्रदेश में 24 अप्रैल से 30 जून तक प्रशासन गांवों/शहरों के संग अभियान के साथ-साथ महंगाई राहत कैप आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें आमजन और वंचित वर्ग को जनोपयोगी घोषणाओं के बारे में जानकारी देकर पात्रता अनुसार योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। 24 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने जयपुर के सांगानेर की ग्राम पंचायत महापुरा में महंगाई राहत कैप का शुभारंभ किया। उन्होंने महिला लाभार्थियों का पात्रता अनुसार योजनाओं में रजिस्ट्रेशन करवाकर उन्हें मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड सौंपा।

पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान तथा नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग द्वारा प्रशासन शहरों के संग अभियान आयोजित किए जा रहे हैं। प्रशासन गांवों के संग एवं प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत आयोजित होने वाले शिविरों में नामांतरण, खातेदारी, तरमीम, भू-उपयोग परिवर्तन सहित जनता से जुड़े अन्य जरूरी कार्यों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जा रहा है।

आमजन और वंचित वर्ग को महंगाई से राहत देने तथा उनकी दैनिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बजट 2023-24 में कई जनकल्याणकारी घोषणाएं की हैं। महंगाई राहत कैपों के आयोजन से इन घोषणाओं को जन-जन तक पहुंचाने तथा मिशन मोड में प्रभावी और समयबद्ध क्रियान्वयन में मदद मिलेगी।

आमजन को उनके अधिकारों, योजनाओं और उनकी पात्रता की संपूर्ण जानकारी देकर जागरूक करने के साथ उन्हें सशक्त बनाना इन कैपों का मुख्य उद्देश्य है। राज्य सरकार द्वारा संचालित 10 जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ने के लिए कैपों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। आमजन की सुविधा के लिए

किसी भी जिले का व्यक्ति अन्य जिलों के कैपों में भी जनाधार के जरिए रजिस्ट्रेशन करा सकता है। महंगाई राहत कैप के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को 10 योजनाओं में निःशुल्क रजिस्ट्रेशन के बाद मौके पर ही मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड उपलब्ध कराए जाएंगे।

11,283 ग्राम पंचायतों और 7,500 शहरी वार्डों में शिविर

ग्रामीण क्षेत्रों की 11,283 ग्राम पंचायतों में प्रशासन गांवों के संग अभियान और शहरी क्षेत्र के 7,500 वार्डों में प्रशासन शहरों के संग अभियान के दो दिवसीय शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इन शिविरों में महंगाई राहत कैप के विशेष काउंटर लगाए जा रहे हैं।

विभिन्न स्थानों पर 2,700 महंगाई राहत कैप

प्रदेश में 2,000 स्थानों पर स्थायी महंगाई राहत कैप लगाए जा रहे हैं। ये कैप राजकीय अस्पतालों, गैस एजेंसी, बस स्टैंड, प्रमुख बाजारों, शॉपिंग मॉल्स, हवाई अड्डा, रेलवे स्टेशन, जिला कलक्ट्रेट, पंचायत समिति, नगरपालिका सहित अन्य राजकीय कार्यालयों व सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जा रहे हैं। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर प्रशासन गांवों के संग अभियान के साथ एक-एक महंगाई राहत कैप लगाया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में प्रत्येक नगरपालिका स्तर पर एक, नगरपरिषद स्तर पर दो एवं नगर निगम स्तर पर चार महंगाई राहत कैप लगाए जाएंगे।

पंजीकरण पोर्टल

मुख्यमंत्री श्री गहलोत ने 23 अप्रैल को महंगाई राहत कैप के पंजीकरण पोर्टल एवं वेबसाइट का लोकार्पण किया। इनके माध्यम से आमजन का जनकल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव सुनिश्चित किया जा सकेगा तथा उन्हें योजनाओं के लाभ एवं उद्देश्य के बारे में जागरूक किया जा सकेगा। पंजीकरण पोर्टल एवं वेबसाइट पर 10 योजनाओं की विस्तृत जानकारी एवं पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेजों की सूची, कैप में पंजीकरण कराने से संबंधित उपयोगी



फोटो-वीडियो गैलरी तथा सामान्य तौर पर पूछे जाने वाले प्रश्नों की सूची उत्तर सहित उपलब्ध होगी। कैंप से संबंधित आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक जिले हेतु जारी हेल्पलाइन नंबर भी वेबसाइट पर मिल सकेंगे।

राहत कैंप में शामिल प्रमुख योजनाएं

इन शिविरों में मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना, महात्मा गांधी नरेगा, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना, पालनहार योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तथा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना सहित विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। साथ ही आमजन को मौके पर ही योजनाओं का लाभ मिल रहा है। शिविरों में जनाधार कार्ड में सम्मिलित किसी भी परिवार का वयस्क सदस्य पात्रता अनुसार पंजीकरण भी करवा सकता है।

मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना

मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के बजट में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) से जुड़े परिवारों के लिए इस वर्ष के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना लागू की है।

इन परिवारों को माह के राशन के साथ ही यह पैकेट दिया जाएगा। इस किट में 1 किलो दाल, 1 किलो चीनी, 1 किलो नमक, 100 ग्राम मिर्च पाउडर, 100 ग्राम धनिया पाउडर, 50 ग्राम हल्दी पाउडर और 1 लीटर खाद्य तेल दिया जाएगा। राशन की दुकान पर राशन की तरह ही बायोमेट्रिक तरीके से यह अन्नपूर्णा फूड किट दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना

मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (CMREGS) योजना के तहत स्थायी रूप से महात्मा गांधी नरेगा में 100 दिन का काम पूरा करने वाले सभी लाभार्थियों को राज्य सरकार की ओर से 25 दिन का एवं सहरिया, कथौड़ी एवं विशेष योग्यजन को 100 दिन का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा।

इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना

राज्य की नगरीय सीमा में रहने वाले परिवारों, विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर, असहाय और बेरोजगार परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर 2022 को शुरू की गई, जिसमें शहरी क्षेत्र में निवास करने वाले परिवारों को प्रति वर्ष 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराया गया।

1 अप्रैल 2023 से 100 दिन के स्थान पर 125 दिन के गारंटीशुदा रोजगार का लाभ दिया जाएगा। पात्र व्यक्ति (अर्द्धकुशल और अकुशल) द्वारा स्वयं, ई-मित्र या नगरीय निकाय स्थित योजना प्रकोष्ठ के माध्यम से निःशुल्क पंजीकरण करवाने के बाद रोजगार मांगने पर संबंधित नगरीय निकाय द्वारा जॉब कार्ड के आधार पर 15 दिन में रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। योजना के तहत पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, स्वच्छता और सेनेटेशन, संपत्ति विरूपण रोकने, कंवर्जेंस, हेरिटेज संरक्षण, सेवा संबंधित और अन्य कार्य करवाए जाएंगे।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

राजस्थान सरकार द्वारा मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना एवं मुख्यमंत्री लघु एवं सीमांत किसान कृषक सम्मान पेंशन योजना संचालित की जा रही हैं। इन योजनाओं में कुल लाभार्थियों की संख्या 93.40 लाख है। राज्य सरकार ने बजट 2023-24 में 75 वर्ष तक की उम्र के सभी पेंशनर्स की पेंशन बढ़ाकर कम से कम 1,000 रुपये कर दी है। पेंशन योजनाओं में मिलने वाली पेंशन राशि में प्रति वर्ष 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना

राज्य सरकार ने कृषि उपभोक्ताओं के लिए मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना शुरू की है जिसमें किसानों को 2,000 यूनिट बिजली प्रतिमाह तक उपभोग पर बिजली निःशुल्क देय होगी। इस योजना से लगभग 11 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो जाएगा।



मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा प्रदेश के नागरिकों को निःशुल्क बिजली देने के लिए अप्रैल 2022 में मुख्यमंत्री घरेलू विद्युत अनुदान योजना की शुरुआत की गई और 50 यूनिट बिजली फ्री की गई। अब वर्ष 2023-24 के बजट में मुख्यमंत्री ने घरेलू उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक उपभोग करने पर बिजली फ्री कर दी है। इससे 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले समस्त घरेलू उपभोक्ताओं का बिजली का बिल शून्य हो जाएगा।

मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना

बजट 2023-24 में पशुपालकों को दुधारू गौवंशीय पशुधन की अकाल मृत्यु के कारण संभावित नुकसान से सुरक्षा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना की घोषणा की। इस योजना में पशुपालकों को अधिकतम दो दुधारू गौवंशीय पशुओं का प्रति पशु 40 हजार रुपये का बीमा किया जाएगा। दुधारू गौवंशीय पशु का मूल्य निर्धारण दुग्ध उत्पादन के आधार पर किया जाएगा।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना

राज्य सरकार ने दुर्घटना होने पर परिवार को आर्थिक संबल प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू की है। मुख्यमंत्री ने योजना में लाभार्थी परिवार को दी जाने वाली सहायता राशि 5 लाख रुपये से बढ़ाकर अब 10 लाख रुपये तक कर दी है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

निरोगी राजस्थान के सपने को साकार करते हुए मुख्यमंत्री ने प्रदेश के हर परिवार को स्वास्थ्य के अधिकार का लाभ दिया है। राज्य

सरकार ने 1 मई, 2021 से देश की सबसे बड़ी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की, जिसमें प्रदेश के हर परिवार को 5 लाख रुपये तक के बीमा कवरेज का लाभ दिया। 1 मई 2022 को इसे 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया गया। अब बजट 2023-24 में इसे बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया है।

मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने महंगाई से प्रदेश के आमजन को राहत देते हुए वर्ष 2023-24 के बजट में 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना की घोषणा की। इस योजना का लाभ प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में रजिस्टर्ड और बीपीएल कैटेगरी के लगभग 76 लाख उपभोक्ताओं को दिया जाएगा। इस योजना के तहत हर माह अधिकतम एक सिलेंडर पर ही सब्सिडी देय है। गैस सिलेंडर लेते समय आपको ऑयल कंपनी द्वारा निर्धारित गैस सिलेंडर की पूर्ण राशि का भुगतान करना होगा। एक माह के अंदर आपके द्वारा दी गई राशि में से 500 रुपये कम करके शेष राशि सब्सिडी के रूप में जनआधार से लिंक बैंक खाते में अपने आप आ जाएगी। ●

योजनाओं का कैलेंडर

योजना	योजना प्रारंभ की तिथि	लाभ प्रारंभ की तिथि
मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर योजना	1 अप्रैल, 2023	1 अप्रैल, 2023
मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना	1 मई, 2023	1 जून 2023
मुख्यमंत्री निःशुल्क कृषि बिजली योजना	1 मई, 2023	1 जून, 2023
मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट योजना	25 मई, 2023	25 मई, 2023
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	1 मई, 2023	1 जून, 2023
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना	30 मार्च, 2023	30 मार्च, 2023
मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना	30 मार्च, 2023	30 मार्च, 2023

महंगाई राहत कैंपों में रजिस्ट्रेशन करवाने वाले सभी पात्र लाभार्थियों को निर्धारित तिथि से ही लाभ मिलेगा। योजनाओं में पात्र लाभार्थियों को लाभ देने की तिथि इस प्रकार है :

- मुख्यमंत्री ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत सभी परिवारों को 25 अतिरिक्त दिवस और कथौड़ी, सहरिया व विशेष योग्यजन को 100 अतिरिक्त दिवस का रोजगार उस दिन से मिलेगा, जिस दिन वह परिवार मनरेगा में 100 दिवस का रोजगार पूर्ण कर लेगा।
- इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत प्रत्येक वर्ष में शहरी क्षेत्र के परिवार को 125 दिवस का रोजगार मिलेगा।
- मुख्यमंत्री कामधेनु बीमा योजना के तहत लाभ प्रारंभ की तिथि राज्य सरकार के द्वारा अलग से निर्धारित की जाएगी।

जनकल्याणकारी योजनाओं से समाज में आ रहे

सकारात्मक बदलाव



लाभार्थी उत्सव में दो लाख लाभार्थियों से मुख्यमंत्री का संवाद

आज राज्य सरकार की योजनाएं पूरे देश में चर्चा का विषय हैं। जनकल्याण में राज्य में किए गए नवाचार अद्वितीय हैं। इनका लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचना चाहिए। जिस प्रकार कोरोना प्रबंधन में आमजन ने आगे बढ़कर कोई भूखा न सोए की संकल्पना को साकार करने में योगदान दिया था, इसी प्रकार अब कोई भी व्यक्ति योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे।

मुख्यमंत्री का लाभार्थियों से संवाद

30 मार्च को राजस्थान दिवस पर आयोजित लाभार्थी उत्सव के अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशभर से जुड़े लाभार्थियों से संवाद किया। राज्य के सभी जिलों से लगभग 2 लाख लाभार्थी वीसी के माध्यम से एवं प्रत्यक्ष रूप से कार्यक्रम से जुड़े। इंगरपुर के श्री मोहन पाटीदार ने बताया कि उनके छोटे भाई की दुर्घटना में मृत्यु होने पर राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत 5 लाख रुपये दिए गए, जिससे उनके परिवार को आर्थिक संबल मिला। मुख्यमंत्री ने लाभार्थी से इस योजना को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करने का आह्वान किया ताकि राज्य सरकार अधिक से अधिक शोक संतप्त परिवारों की सहायता कर सके।

बाड़मेर के दिव्यांग लाभार्थी श्री नरपत सिंह ने बताया कि उन्हें राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उनके बच्चों को पालनहार योजना का लाभ मिलने के साथ-साथ उन्हें मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना के तहत पेंशन मिल रही है। उन्होंने पालनहार योजना में मिलने वाली राशि को 1,000

अमन दीप विश्रोई
जनसंपर्क अधिकारी

से 1,500 रुपये करने एवं पेंशन राशि को 750 से 1,000 रुपये करने के लिए श्री गहलोट को धन्यवाद ज्ञापित किया। श्री गहलोट ने कहा कि राज्य के सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारियों के हित में पेंशन राशि को बढ़ाया गया है। योजना के लिए प्रावधित राशि को 9,000 करोड़ से बढ़ाकर 12,000 करोड़ किया गया है। बाड़मेर की ही लाभार्थी श्रीमती धाई देवी ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत उनके दोनों घुटनों का निशुल्क ऑपरेशन हुआ, जिसके कारण अब वह सुगमता से चल पा रही हैं। श्री गहलोट ने लाभार्थी के सफल ऑपरेशन पर खुशी व्यक्त करते हुए कहा कि चिरंजीवी योजना के तहत स्वास्थ्य बीमा राशि 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा संचालित योजना का लाभ लेना हर पात्र नागरिक का अधिकार एवं कर्तव्य है।

बाड़मेर की लाभार्थी श्रीमती विमला देवी ने बताया कि उनकी बेटा निर्मला जन्म से ही सुनने और बोलने में अक्षम थी। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना अन्तर्गत उसका सफल कॉक्लिवर इम्प्लांट हुआ। चिरंजीवी योजना के द्वारा निशुल्क इलाज मिलने से बालिका का जीवन सुगम हो पाया है। कोटा के लाभार्थी श्री गौरव वर्मा ने बताया कि वे साधारण परिवार से संबंध रखते हैं और अपनी जेईई कोचिंग की फीस भरने में असमर्थ थे, लेकिन मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अन्तर्गत उनकी निशुल्क कोचिंग संभव हो पाई है। अब

एमएनआईटी में उनका एडमिशन हो चुका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुप्रति योजना के तहत पहले 15,000 युवाओं को कोचिंग का प्रावधान था जिसे अब बढ़ाकर 30,000 कर दिया गया है। वहीं राजीव गांधी स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत अब 200 के स्थान पर 500 विद्यार्थी राज्य सरकार के खर्च पर विदेश में अध्ययन के लिए जा सकेंगे।

कोटा के लाभार्थी श्री देवकिशन ने मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि इससे दिव्यांगजनों की गतिशीलता बढ़ गई है। श्री गहलोत ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा दिव्यांगजनों के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 5,000 स्कूटी प्रतिवर्ष दिव्यांगजनों को दी जा रही हैं और आगामी समय में इनकी संख्या और बढ़ाई जाएगी। जोधपुर के लाभार्थी श्री सुमेर देवड़ा ने बताया कि मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना से उनका आर्थिक भार कम हुआ है। मुख्यमंत्री ने बताया कि अब किसानों के लिए 2,000 यूनिट तक बिजली मुफ्त कर दी गई है जिससे 14 लाख किसानों का बिजली बिल शून्य हो जाएगा। साथ ही, 100 यूनिट तक घरेलू बिजली मुफ्त कर दी गई है जिससे 1.04 करोड़ परिवारों का बिजली बिल शून्य होगा। जोधपुर की ही लाभार्थी श्रीमती राजकंवर ने बताया कि उड़ान योजना के तहत निःशुल्क सेनेटरी पैड मिलने से उनका जीवन सुगम हुआ है तथा स्वास्थ्य प्रबंधन बेहतर हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाओं के माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर समाज में व्याप्त संकोच अब समाप्त होना चाहिए। माहवारी के दौरान सेनेटरी पैड का उपयोग नहीं करने से महिलाएं गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हो जाती हैं। उड़ान योजना में 500 करोड़ की लागत से महिलाओं एवं किशोरियों को हर महीने 12 सेनेटरी पैड निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं।

धीलपुर की लाभार्थी छात्रा प्रीति पाराशर एवं रुचि भदौरिया ने बताया कि उनके परिवार निजी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों की महंगी फीस वहन नहीं कर सकते थे, लेकिन अब महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में उन्हें अंग्रेजी माध्यम में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा निःशुल्क प्राप्त हो रही है। मुख्यमंत्री ने इन छात्राओं के अंग्रेजी में बात करने पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालयों के खुलने से आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों तक निःशुल्क अंग्रेजी माध्यम शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित हुई है। वर्तमान में लगभग 2 लाख विद्यार्थी इन

स्कूलों में अध्ययन कर रहे हैं।

भीलवाड़ा के लाभार्थी श्री धीरज शकरानी ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत उनका निःशुल्क डायलिसिस एवं किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। राज्य सरकार की योजना से उनका महंगा इलाज निःशुल्क हो पाया है। आज वह स्वस्थ होकर सामान्य रूप से अपना जीवन जी पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि योजना के अंतर्गत किडनी, लीवर, बोनमैरो एवं हार्ट ट्रांसप्लांट आदि के लिए विशेष पैकेज दिए गए हैं। अब राज्य के बाहर इलाज कराने पर भी प्रदेशवासी चिरंजीवी योजना का लाभ ले सकते हैं। भीलवाड़ा की ही लाभार्थी उमा सोनी ने बताया कि इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत उन्हें रोजगार मिला है जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में महात्मा गांधी नरेगा की तर्ज पर इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत रोजगार दिवस की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 कर दी गई है और सभी लाभार्थियों का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित किया जा रहा है।

हनुमानगढ़ जिले की लाभार्थी श्रीमती सुखप्रीत कौर ने बताया कि उनकी प्रीमैच्योर डिलीवरी से हुए शिशु के आईसीयू में उपचार का 4.90 लाख रुपये का खर्च मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा वहन किया गया है। हनुमानगढ़ जिले के भरत दास ने बताया कि उनके पिता की दुर्घटना में मृत्यु होने पर मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना के तहत उन्हें 5 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मिली है।

जयपुर के लाभार्थी लक्ष्य जांगिड़ के पिता ने बताया कि उनके बेटे का ब्लड कैंसर का इलाज मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत निःशुल्क हुआ। योजना के माध्यम से हुए निःशुल्क बोनमैरो ट्रांसप्लांट से आज उनका बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है। उन्होंने बताया कि उन्होंने अपने पड़ोसी को भी चिरंजीवी योजना के बारे में जागरूक कर निःशुल्क उपचार का लाभ दिलाया। उन्होंने कहा कि पूरे देश में इस तरह की योजना लागू होनी चाहिए ताकि महंगे उपचार के अभाव में कोई भी व्यक्ति परेशान न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले महंगे उपचार के कारण लोगों की आर्थिक स्थिति चरमरा जाती थी। राज्य सरकार ने चिरंजीवी योजना के माध्यम से इस स्थिति को बदलकर यह सुनिश्चित किया है कि महंगे उपचार के अभाव में किसी मरीज को कोई दिक्कत न हो। ●





राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण

राज्य सरकार के प्रयासों से प्रदेश में विश्वस्तरीय आधारभूत ढांचे का निर्माण हुआ है। दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर और इंडिया हैबिटेड सेंटर की तर्ज पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का निर्माण लगभग 140 करोड़ रुपए की लागत से किया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 17 अप्रैल को जयपुर के झालाना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर का लोकार्पण किया। इस सेंटर में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक, व्यापारिक, अकादमिक कार्यक्रमों सहित उच्च स्तरीय बैठकों, सेमिनारों एवं सम्मेलनों का आयोजन किया जा सकेगा।

स्काॅच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट-2022 में राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की तीसरी रैंक

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश की जनता को प्रदान किए जा रहे संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन का ही परिणाम है कि राजस्थान ने विभिन्न क्षेत्रों में शानदार प्रदर्शन किया है। स्काॅच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट-2022 में राज्य की रैंकिंग में जबर्दस्त सुधार हुआ है और राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर 15वें पायदान से आगे बढ़कर तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य ने कुल 20 पुरस्कार जीते हैं, जिनमें से 8 गोल्ड एवं 12 सिल्वर कैटेगरी में हैं। रिपोर्ट के अनुसार उम्दा प्रदर्शन करने वाली राज्य की कुल 78 परियोजनाओं को स्काॅच ने ऑर्डर ऑफ मेरिट के लिए पात्र माना है, जिनमें से 8 प्रोजेक्ट अत्यधिक प्रभावशाली एवं 12 प्रभावशाली श्रेणी में हैं। इसके अतिरिक्त राज्य ने 23 विभिन्न श्रेणियों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि

अरुण कुमार जोशी
अतिरिक्त निदेशक, जनसंपर्क

स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक सुरक्षा और आवास श्रेणियों में राजस्थान देश में शीर्ष स्थान पर है। ई-गवर्नेंस और जल के क्षेत्र में सर्वाधिक सुधार हुआ है। जबकि, परिवहन श्रेणी में प्रदेश का प्रदर्शन निरंतर अच्छा रहा है।

स्काॅच ऑर्डर ऑफ मेरिट में सम्मिलित राजस्थान की 78 परियोजनाओं में से आधे से अधिक परियोजनाएं शिक्षा, ई-गवर्नेंस, सामान्य प्रशासन, पुलिस एवं सुरक्षा, कौशल विकास, सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा क्षेत्र से संबंधित हैं। कृषि, अल्पसंख्यक मामले, राजस्व और शहरी विकास की 3-3 परियोजनाओं को स्काॅच ऑर्डर ऑफ मेरिट की सूची में जगह मिली है जबकि, स्वास्थ्य श्रेणी में राज्य के 5 प्रोजेक्ट्स इस सूची में स्थान बनाने में कामयाब हुए हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि ई-गवर्नेंस में राज्य पिछले वर्ष के सातवें स्थान की तुलना में इस वर्ष दूसरे स्थान पर पहुंच गया है जबकि, जल के क्षेत्र में प्रदेश चौथे स्थान से दूसरे स्थान पर आ गया है। आवास कैटेगरी में राजस्थान की प्रथम रैंक तथा परिवहन की श्रेणी में चौथी रैंक बरकरार है। वहीं, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं सामाजिक सुरक्षा में राज्य ने पहली, महिला एवं बाल विकास में दूसरी, कृषि और कौशल विकास में तीसरी, शिक्षा क्षेत्र में पांचवीं एवं सामान्य प्रशासन, शहरी विकास व ऊर्जा श्रेणी में 6वीं रैंक पर वापसी की है। रिपोर्ट के अनुसार कई सेक्टर ऐसे हैं जिनमें पहली बार भाग लेने के बावजूद प्रदेश शीर्ष स्थानों पर काबिज होने में कामयाब रहा है। सहकारिता, ईज

ऑफ इंडिंग बिजनेस, बुनियादी ढांचा, पर्यटन एवं संस्कृति में राज्य ने दूसरा, राजस्व, आपदा प्रबंधन, खेल एवं युवा, पशुपालन एवं मत्स्य पालन में चौथा तथा पुलिस एवं सुरक्षा में सातवां स्थान प्राप्त किया है। रिपोर्ट के मुताबिक कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, सहकारिता, ईज ऑफ इंडिंग बिजनेस, शिक्षा, ई-गवर्नेंस, सामान्य प्रशासन, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, अल्पसंख्यक मामले, पुलिस एवं सुरक्षा, ऊर्जा, राजस्व, कौशल विकास, सामाजिक न्याय एवं सुरक्षा, खेल एवं युवा, पर्यटन एवं संस्कृति, शहरी विकास तथा महिला एवं बाल विकास वर्ष 2022 में विशेष प्राथमिकता वाले क्षेत्र रहे हैं।

श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 14 अप्रैल को बैशाखी पर्व के अवसर पर श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। बोर्ड सिख समुदाय के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक उन्नयन हेतु विभिन्न कार्य संपादित करेगा। बोर्ड का उद्देश्य सिख समुदाय के विभिन्न वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए योजनाएं प्रस्तावित करना और रोजगार को बढ़ावा देने के संबंध में सुझाव देना है। बोर्ड सिख समुदाय के लिए संचालित कल्याणकारी योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन पर भी सुझाव देगा। इसके साथ ही बोर्ड सिख समुदाय की कला और संस्कृति को बढ़ावा देने और समुदाय के परम्परागत व्यवसायों को आधुनिक रूप देने के लिए भी सुझाव देगा। बोर्ड सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक योजनाओं में सिख समुदाय की भागीदारी, समुदाय के लिए नवीन योजनाओं की प्रगति और इनके क्रियान्वयन में आ रही कठिनाइयों और समाधान हेतु निरंतर समीक्षा करेगा। श्री गुरु नानक देव सिख कल्याण बोर्ड का प्रशासनिक विभाग अल्पसंख्यक मामलात विभाग होगा। बोर्ड में सात गैर सरकारी सदस्य होंगे जिनमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पांच सदस्य शामिल होंगे। साथ ही, विभिन्न विभागों के प्रतिनिधि इसमें सदस्य के रूप में शामिल होंगे। बोर्ड के सचिव पद पर अल्पसंख्यक मामलात विभाग के उपनिदेशक स्तर का अधिकारी कार्य संपादित करेगा।

परीक्षार्थियों को राहत वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए 600 एवं 400 रुपये शुल्क निर्धारित

प्रदेश के युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बार-बार आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना पड़ेगा। अब वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस प्रणाली से ही आवेदक सभी परीक्षाओं में बैठ सकेंगे। राज्य सरकार ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए सामान्य वर्ग, राजस्थान के क्रीमीलेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग/अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 600 रुपये तथा शेष अन्य श्रेणी के लिए 400 रुपये का शुल्क निर्धारित कर दिया है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस प्रणाली में निर्धारित शुल्क के अनुसार परिपत्र जारी करने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान

की है। इससे राजस्थान लोक सेवा आयोग एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन के बाद कोई शुल्क नहीं देना होगा। इससे राज्य सरकार पर लगभग 200 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आएगा।

किसानों की उन्नति के लिए विभिन्न योजनाओं में 592 करोड़ रुपये स्वीकृत

कृषि और किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत 592 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने किसानों की उन्नति सुनिश्चित करने के लिए वित्तीय प्रावधान के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

श्री गहलोत के निर्णय से नैनो यूरिया के ड्रोन से छिड़काव के लिए 4.50 करोड़ रुपये की लागत आएगी, जिसके लिए 10 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में लागत के 75 प्रतिशत अथवा अधिकतम 4,500 रुपये प्रति हेक्टेयर की अनुदानित दर रखी गई है। वहीं, 5 लाख भूमिहीन श्रमिकों को हस्तचालित कृषि यंत्र खरीदने के लिए प्रति परिवार 5 हजार रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसमें राज्य सरकार 250 करोड़ रुपये व्यय करेगी।

राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में एक लाख किसानों को 250 करोड़ रुपये के कृषि यंत्र, 50 हजार पशुपालक किसानों को अनुदानित दर पर हस्त/पावर चलित चाफ कटर यंत्र उपलब्ध कराए जाएंगे। साथ ही, कृषि स्नातक बेरोजगार युवाओं को भी 1,000 ड्रोन उपलब्ध कराने के लिए 4-4 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा।

कृषक उत्पादन संगठन (एफपीओ) तथा कस्टम हायरिंग केंद्रों को भी ड्रोन उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सरकार द्वारा इन सभी योजनाओं में कृषक कल्याण कोष से 588 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 4.60 करोड़ रुपये (राज्यांश) का प्रावधान किया गया है। स्वीकृति से प्रदेश के लाखों कृषक एवं पशुपालक लाभान्वित होंगे।

23 जून से राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन

प्रदेश में एक बार फिर से राजीव गांधी ग्रामीण खेलों के साथ शहरी ओलंपिक खेलों का बिगुल बजेगा। ग्रामीण ओलंपिक की सफलता और खिलाड़ियों के उत्साह को देखते हुए अब ग्रामीण और शहरी ओलंपिक खेलों का एक साथ आयोजन होगा। इन खेलों के आयोजन में लगभग 130 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने आयोजन के लिए वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। खेलों का शुभारंभ 23 जून, 2023 से होगा। शीघ्र ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू की जाएगी। खेल दिवस 29 अगस्त, 2023 को राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं का आयोजन प्रस्तावित है। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री ने बजट 2023-24 में राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए

घोषणा की थी। ग्रामीण क्षेत्र में कबड्डी, खो-खो (महिला वर्ग), शूटिंगबॉल (पुरुष वर्ग), टेनिसबॉल क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, रस्साकशी (महिला वर्ग) खेल होंगे। शहरी क्षेत्र में कबड्डी, बास्केटबॉल, टेनिसबॉल क्रिकेट, खो-खो (महिला वर्ग), फुटबॉल (पुरुष वर्ग), वॉलीबॉल, एथलेटिक्स (100, 200 व 400 मीटर) खेलों में प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। इन खेलों के आयोजन के पीछे राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में खेलों का वातावरण तैयार कर प्रदेशवासियों को खेलों से जोड़कर मैदान तक लाना है। साथ ही, शारीरिक व मानसिक तनाव दूर कर खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करना है।

प्रदेश में 2 हजार टैक्स मित्र होंगे नियुक्त

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और मूल्य वर्धित कर (वैट) आवेदन प्रक्रियाओं में आवेदकों को सहूलियत देने के लिए राज्य सरकार प्रदेश में 2 हजार टैक्स मित्र नियुक्त करेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने नियोजन की योग्यताओं तथा शुल्क निर्धारण संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

श्री गहलोत ने सेल्फ टैक्स स्कूटनी की प्रथम स्तरीय सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित ई-टैक्स ऑफिसर सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म विकसित करने की स्वीकृति भी दी है।

टैक्स मित्र के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता वाणिज्य में स्नातक रखी है। सीए, सीएस, आईसीडीब्ल्यूए सहित अनुभवी आवेदकों को प्राथमिकता मिलेगी। आयु 21 से 40 वर्ष निर्धारित की गई है। टैक्स मित्रों द्वारा विभिन्न टैक्स संबंधी आवेदन प्रक्रियाओं के लिए शुल्क लिया जाएगा। इस शुल्क का भी निर्धारण किया गया है। इसमें जीएसटी, वैट आवेदन, संशोधन, आईटीसी, ई-वे बिल, सब्सिडी आवेदन, एमएसएमई आवेदन सहित अन्य कार्यों के लिए 50 रुपये से 400 रुपये तक का शुल्क रखा गया है।

फरार कुख्यात अपराधियों पर इनामी राशि में वृद्धि

राज्य सरकार ने प्रदेश के कुख्यात अपराधियों की गिरफ्तारी पर इनामी राशि में वृद्धि की है। अब ऐसे फरार अपराधियों पर पुलिस महानिदेशक 5 लाख रुपये तक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (अपराध) 1 लाख रुपये तक, पुलिस रेंज महानिरीक्षक 50 हजार रुपये तक और जिला पुलिस अधीक्षक 25 हजार रुपये तक की इनामी राशि की घोषणा कर सकेंगे।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 16 अप्रैल को कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक में इनामी राशि में वृद्धि के निर्देश दिए। इस निर्णय से आमजन की मदद से कुख्यात अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण हो सकेगा। गिरफ्तार करने वाले पुलिसकर्मियों को भी प्रोत्साहन मिलेगा। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2013 के बाद अब इनाम की राशि में बढ़ोतरी की गई है।

राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग के लिए 421 करोड़ रुपये की स्वीकृति

जयपुर में राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड लर्निंग (आरआईएएल) के लिए 421 करोड़ रुपये का वित्तीय प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इससे संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

इस राशि में 180 करोड़ रुपये से भवन निर्माण, 145 करोड़ रुपये से विभिन्न नवाचार एवं अनुसंधान केंद्रों/स्कूलों की स्थापना, 7 करोड़ रुपये से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न कार्य किए जाएंगे। साथ ही, भवन रख-रखाव हेतु आगामी 4 वर्षों में 20 करोड़ रुपये तथा आगामी 5 वर्षों में आरआईएएल के संचालन के लिए 69 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

31 दिसंबर 2021 तक बस्ती कच्ची बस्तियों के जारी होंगे पट्टे

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में 12 अप्रैल को मुख्यमंत्री निवास पर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित हुई। इसमें कच्ची बस्तियों में पट्टों के वितरण, राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2023, विभिन्न सेवा नियमों, गौशालाओं और छात्रावासों के लिए भूमि आवंटन सहित अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों का अनुमोदन किया गया।

प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में वर्ष 2004 में सर्वशुद्ध कच्ची बस्तियों के अतिरिक्त 31 दिसंबर 2021 तक बस्ती नई कच्ची बस्तियों के सर्वे कर नियमित किया जाएगा। मंत्रिमंडल ने ऐसे परिवारों को संबल प्रदान करने के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत पट्टे वितरित किए जाएंगे। इससे कच्ची बस्तियों का सुनियोजित विकास सुनिश्चित होगा। सड़क, नाली, विद्युत एवं पेयजल की आधारभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा सकेंगी।

मंत्रिमंडल ने बहुमंजिला भवनों में रहने वाले लोगों के लिए अहम फैसला लिया है। प्रदेश के सभी नगरीय क्षेत्रों में बने ऐसे भवनों में निवासरत लोगों को पेयजल की समस्या नहीं आएगी। मंत्रिमंडल ने जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा प्रस्तावित नीति के प्रारूप का अनुमोदन किया है। अब इन्हें पीएचईडी की योजनाओं के तहत जल कनेक्शन जारी किए जाएंगे। अभी ये टैंकरों और भू-जल पर ही निर्भर हैं। इससे भू-जल का अत्यधिक दोहन होने के साथ कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ रहा है। इस नीति से जल संरक्षण, वर्षा जल संचयन, अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण एवं पुनः उपयोग प्रणाली को प्रोत्साहन मिलेगा।

मंत्रिमंडल ने राज्य के विभिन्न नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्य के लिए जारी की गई भूमि आवंटन नीति-2015 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से अब विभिन्न समाजों के विद्यार्थियों हेतु छात्रावास निर्माण के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटन हो सकेगा। उल्लेखनीय है कि विभिन्न समाजों के विद्यार्थियों को छोटे गांवों से बड़े शहरों में अध्ययन के उद्देश्य से आना पड़ता है। ऐसे विद्यार्थियों के लिए अस्थायी आवासों की आवश्यकता कस्बों, नगरों एवं महानगरों में रहती है। इस स्वीकृति से अब विभिन्न समाजों के छात्रावासों का निर्माण हो सकेगा और ऐसे विद्यार्थियों को आवास की सुविधा प्राप्त हो सकेगी।

राज्य में विद्यमान 133 अप्रचलित और अनावश्यक विधियां निरस्त की जाएंगी। मंत्रिमंडल ने कानूनों की समीक्षा के बाद ऐसी विधियों को निरस्त करने के लिए राजस्थान विधियां निरसन विधेयक 2023 का अनुमोदन किया है। यह विधेयक राजस्थान विधानसभा में रखा जाएगा। गौरतलब है कि इनमें 33 मूल अधिनियम (विनियोग अधिनियमों सहित) और 100 संशोधित अधिनियमों (केंद्रीय अधिनियमों में किए गए राज्य संशोधनों सहित) विधियां शामिल हैं। इनमें से कई विधियों का प्रयोजन पूर्ण हो चुका है तथा कई मूल अधिनियम भी अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं।

डिग्गी, फार्म पौंड एवं पाइप लाइन के लिए किसानों को अनुदान

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में सूक्ष्म सिंचाई व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु डिग्गी, फार्म पौंड एवं सिंचाई पाइप लाइन आदि कार्यों के लिए लगभग 463 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। यह स्वीकृति राजस्थान सूक्ष्म सिंचाई योजना के अंतर्गत दी गई है।

आगामी 2 वर्षों में फार्म पौंड निर्माण के लिए 30 हजार किसानों को लाभान्वित करने के लक्ष्य को बढ़ाकर 50 हजार किया गया है। इस पर कुल 261.75 करोड़ रुपये खर्च होंगे। योजना में अनुसूचित जाति-जनजाति के गैर लघु-सीमांत कृषकों को भी अब लघु-सीमांत किसानों के समान 10 प्रतिशत अतिरिक्त अनुदान मिलेगा। किसानों को प्रोत्साहित करने एवं संबल प्रदान करने के लिए प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौंड निर्माण हेतु अनुदान सीमा को भी 90 हजार से बढ़ाकर 1.20 लाख रुपये किया गया है।

आगामी 2 वर्षों में 40 हजार किसानों को 16 हजार किमी सिंचाई पाइपलाइन के लिए अनुदान दिया जाएगा। इस पर वर्ष 2023-24 में 43.20 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। वहीं, 5,000 डिग्गियों के निर्माण पर वर्ष 2023-24 में 158 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

संरक्षित खेती के लिए एक हजार करोड़ रुपये का अनुदान

राजस्थान में संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए दो वर्षों में 60 हजार किसानों को 1 हजार करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा। यह राशि ग्रीन हाउस, शेडनेट हाउस, लो टनल, प्लास्टिक मल्टिचिंग के लिए दी जाएगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अनुदान के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

श्री गहलोत की स्वीकृति से किसानों को संबल मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 30 हजार किसानों को 501 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसमें कृषक कल्याण कोष से 444.43 करोड़ रुपये वहन होंगे। साथ ही राष्ट्रीय बागवानी मिशन/राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से 56 करोड़ (राज्यांश 22.75 करोड़) रुपये वहन किए जाएंगे।

वित्तीय वर्ष 2024-25 में भी 30 हजार किसानों को 500 करोड़ रुपये का अनुदान मिलेगा। इसमें अधिसूचित जनजाति क्षेत्र के किसानों और समस्त लघु/सीमांत किसानों को 25 प्रतिशत अतिरिक्त सब्सिडी भी मिलेगी।

प्रदेश में खुलेंगे नए पुलिस कार्यालय, थाने एवं चौकियां

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में नए पुलिस कार्यालयों, थानों एवं चौकियों को खोलने की मंजूरी दी है। उन्होंने कार्यालयों के लिए 1,369 पदों के सृजन और आवश्यक संसाधनों के लिए लगभग 201 करोड़ रुपये की स्वीकृति भी दी है।

वैर (भरतपुर), परबतसर (नागौर), खैरवाड़ा (उदयपुर), एडीएफ (धौलपुर) एवं लालसोट (दौसा) में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जाएंगे।

इसी प्रकार अरनोद (प्रतापगढ़), तालेड़ा (बूंदी), पहाड़ी (भरतपुर), गंगाशहर (बीकानेर), रामसर (बाड़मेर), बौली (सवाईमाधोपुर), खंडेला (सीकर), अजीतगढ़ (सीकर), सिवाना (बाड़मेर) एवं आहोर (जालौर) में उप पुलिस अधीक्षक कार्यालय खोले जाएंगे।

वैशाली नगर (अलवर), मुक्ता प्रसाद नगर (बीकानेर), श्रीनाथ जी (राजसमंद), गोकुलपुरा (सीकर) एवं सदर पुलिस थाना बयाना (भरतपुर) में नवीन शहरी पुलिस थाने खुलेंगे। इसी प्रकार बासदयाल (अलवर), हदां (बीकानेर), राहुवास (दौसा), तनोट (जैसलमेर) एवं गोठड़ा (झुंझुनू) में नवीन ग्रामीण थाने खुलेंगे।

डीडवाना (नागौर), नावां (नागौर) एवं कोटपूतली (जयपुर) में महिला पुलिस थाने खुलेंगे।

प्रदेश की 10 पुलिस चौकी पुलिस थानों में क्रमोन्नत की गई है। इनमें अंगाई (धौलपुर), मोर (टोंक), सुलताना (झुंझुनू), बबाई (झुंझुनू), जनूथर (भरतपुर), निम्बी जोधा (नागौर), बडू (नागौर), डाबला (सीकर), कैलाशनगर (सिरोही) एवं जाजोद (सीकर) पुलिस चौकी क्रमोन्नत हुई है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में 38 नवीन पुलिस चौकियां भी खोली जाएंगी। इन पुलिस कार्यालयों, थानों एवं चौकियों के सृजन से प्रदेश में कानून व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी।

राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय का होगा गठन

प्रदेश में आर्थिक अपराधों की रोकथाम और राजस्व के स्रोतों पर अधिक मजबूती से निगरानी रखने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्व आसूचना एवं आर्थिक अपराध निदेशालय के गठन का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने निदेशालय के गठन संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राज्य स्तर पर निदेशालय का नोडल व प्रशासनिक विभाग वित्त (राजस्व) विभाग होगा।

निदेशालय द्वारा आर्थिक अपराधों के नियंत्रण, अनुसंधान, जांच व अभियोजन के कार्य किए जाएंगे। इसमें भूमि पर अवैध कब्जा करने, रियल एस्टेट में धोखाधड़ी या अनियमितता करने, बैंक, बीमा या जमा पूंजी संबंधी कार्य में

धोखाधड़ी या अनियमितता करने, झूठा दिवालियापन घोषित करने, फर्जी कंपनियों का गठन करने, सरकारी साख समितियों के कार्य में धोखाधड़ी करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा।

इसके साथ ही राज्य में राजस्व रिसाव की विभिन्न स्रोतों से सूचना प्राप्त कर उनका विश्लेषण एवं अन्वेषण किया जाएगा। राजस्व के समस्त स्रोतों पर निगरानी रखने तथा कर अपवंचना को रोकने संबंधी कार्य भी किए जाएंगे।

उल्लेखनीय है कि राज्य में राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय पहले से ही संचालित है। वहीं, बजट 2022-23 में आर्थिक अपराध निदेशालय की घोषणा की गई थी। अब दोनों का सम्मिलन करने से मानव संसाधन तथा अपराधों की जांच में भी विश्लेषणात्मक क्षमता का समुचित उपयोग हो सकेगा।

महिला निधि से ऋण पर मिलेगा 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने महिला निधि के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को उपलब्ध कराए जाने वाले ऋण पर 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिए जाने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। श्री गहलोत ने इस हेतु वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 12 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की है। प्रस्ताव के अनुसार, स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को 2 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होने वाले 1 लाख रुपये तक के ऋण पर 8 प्रतिशत ब्याज अनुदान दिया जाएगा। श्री गहलोत के इस निर्णय से समूह की महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक उन्नति मिलेगी। श्री गहलोत द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में की गई घोषणा की अनुपालना में यह स्वीकृति दी गई है। उल्लेखनीय है कि श्री गहलोत ने राज्य के स्वयं सहायता समूहों के वित्तीय प्रबंधन के लिए 26 अगस्त, 2022 को महिला समानता दिवस के अवसर पर 'राजस्थान महिला निधि' की शुरुआत की थी। निधि के माध्यम से महिलाओं को सुगमता से रोजमर्रा की आवश्यकता एवं स्वरोजगार हेतु सुलभ व पर्याप्त मात्रा में ऋण उपलब्ध हो रहा है।

पुलिस थानों में लगेगे पैरा-लीगल वॉलन्टियर्स

लापता बच्चों एवं उनके विरुद्ध अपराधों के संबंध में विधिक सहायता के लिए राज्य सरकार प्रदेश के पुलिस थानों में पैरा लीगल वॉलन्टियर्स नियुक्त करेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने वॉलन्टियर्स लगाए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। राज्य के जिला मुख्यालयों के 66 पुलिस थानों तथा ग्रामीण क्षेत्र के 99 पुलिस थानों में एक-एक (कुल-165) वॉलन्टियर्स लगाए जाएंगे। वॉलन्टियर्स को प्रतिमाह 15 हजार रुपये तक पारिश्रमिक मिलेगा। यह स्वीकृति 31 मार्च 2024 तक के लिए दी गई है।

किसानों को मिलेंगे निःशुल्क बीज

राज्य सरकार 15 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश के 1.25 लाख से अधिक किसानों को उच्च गुणवत्तापूर्ण 35 हजार क्विंटल बीज निःशुल्क उपलब्ध कराएगी। इससे लगभग 5.89 लाख क्विंटल बीज का उत्पादन होगा और किसानों को संबल मिलेगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बीज वितरण और उत्पादन से संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। योजना में गेहूँ, जौ, चना, ज्वार, सोयाबीन, मूंगफली, मूंग, मोठ एवं उड़द की फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाएंगे। इससे 10 वर्ष से कम अवधि की उन्नत किस्मों की फसलों के बीजों का उत्पादन होगा। इस निर्णय से प्रदेश में उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन में वृद्धि होगी और कृषि उत्पादकता बढ़ेगी। 15 करोड़ रुपये की राशि कृषक कल्याण कोष से वहन की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन के अंतर्गत बीज उत्पादन बढ़ाने तथा लघु एवं सीमांत कृषकों को निःशुल्क बीज उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री बीज स्वावलम्बन योजना की शुरुआत की गई थी।

सभी ग्राम पंचायतों में हाइब्रिड नेपियर घास की लगाई जाएगी प्रदर्शनी

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 'राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन' (आरएसपीडीएम) के अंतर्गत प्रदेश की समस्त ग्राम पंचायतों में हाइब्रिड नेपियर घास (बहुवर्षीय चारा फसल) की प्रदर्शनी लगाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

राजस्थान बीज उत्पादन एवं वितरण मिशन के अंतर्गत हाइब्रिड नेपियर घास की प्रदर्शनी प्रत्येक ग्राम पंचायत में 0.2 हेक्टेयर भूमि में प्रगतिशील किसानों, विभाग के फार्म, कृषि प्रशिक्षण केंद्र (एटीसी) एवं प्रमुख गौशालाओं में लगाई जाएगी। इसके लिए 'कृषक कल्याण कोष' से 23 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

हाइब्रिड नेपियर घास एक बहुवर्षीय चारा फसल है। इसे हर प्रकार की जलवायु एवं मिट्टी में उगाया जा सकता है। किसानों और पशुपालकों के लिए यह एक बेहतर पशु चारा विकल्प है।

आरटीई के तहत अब 12वीं कक्षा तक के छात्रों को भी निःशुल्क शिक्षा

अब निजी विद्यालयों में 12वीं कक्षा तक के छात्रों को भी निःशुल्क शिक्षा मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के तहत अध्ययनरत विद्यार्थियों की फीस पुनर्भरण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है। इस पर 46 करोड़ रुपये का व्यय होगा। आरटीई के माध्यम से कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए ही निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। श्री गहलोत द्वारा गत बजट में राज्य सरकार के खर्चे पर छात्राओं के लिए कक्षा 9 से 12वीं तक निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा जारी रखने का प्रावधान किया था। इसी क्रम में अब छात्रों को भी कक्षा 1 से 12 तक आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने पर निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी।

विशेष योग्यजन से विवाह पर अब 5 लाख रुपये की सहायता राशि

प्रदेश में विशेष योग्यजन से विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए सुखद दाम्पत्य जीवन योजना के तहत अब 5 लाख रुपये की सहायता राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राशि में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें 80 प्रतिशत या इससे अधिक दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन को जीवनसाथी बनाने पर आर्थिक सहायता को 50 हजार से बढ़ाकर 5 लाख रुपए किया गया है। श्री गहलोत के इस निर्णय से विशेष योग्यजनों को सम्मान मिलेगा।

प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद में स्थापित होंगे नवीन मेडिकल कॉलेज

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद में नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापित करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। प्रतापगढ़, जालोर और राजसमंद में राजमैस के अधीन नवीन मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज का निर्माण 250 करोड़ रुपये की लागत से होगा। साथ ही, इन कॉलेजों में आवश्यक उपकरण, फर्नीचर एवं पुस्तकों के लिए 75 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

उज्वला एवं बीपीएल गैस कनेक्शनधारियों को मिलेगा 500 रुपये में सिलेंडर

प्रदेश के बीपीएल एवं उज्वला योजना में शामिल परिवारों को अब 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 'मुख्यमंत्री गैस सिलेंडर' योजना के तहत 750 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। श्री गहलोत की इस स्वीकृति से राज्य के 73 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 1 अप्रैल, 2023 से सस्ती दर पर प्रतिमाह एक सिलेंडर मिल सकेगा। इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा उज्वला योजना के कनेक्शनधारी परिवारों को प्रति गैस सिलेंडर 410 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, बीपीएल गैस कनेक्शनधारकों को प्रति गैस सिलेंडर 610 रुपये की सब्सिडी देय होगी। लाभार्थी द्वारा स्वयं सिलेंडर खरीदे जाने पर उसके जनआधार से लिंक खाते में सब्सिडी की राशि हस्तांतरित की जाएगी। 1 अप्रैल, 2023 के बाद रजिस्ट्रेशन करवाने वाले लाभार्थियों को भी इस योजना का लाभ देय होगा।

एसओजी में स्पेशल टास्क फोर्स (एंटी चीटिंग) का होगा गठन

राज्य सरकार द्वारा प्रतियोगी परीक्षाओं सहित सार्वजनिक परीक्षाओं में पेपरलीक प्रकरण रोकने और नकल माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। अब राज्य सरकार द्वारा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) में स्पेशल टास्क फोर्स (एंटी चीटिंग) का गठन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने ऐसे प्रकरणों में लिफ्ट दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई हेतु इस आशय के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस निर्णय से चीटिंग से संबंधित प्रकरणों में प्रभावी जांच कर अपराधियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने में सहायता मिलेगी। श्री गहलोत ने इस टास्क फोर्स के संचालन के लिए 39 नवीन पदों के सृजन तथा आवश्यक संसाधनों हेतु वित्तीय प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी है। यह टास्क फोर्स आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित होगी। इसके माध्यम से पेपरलीक के प्रकरणों में दोषी अभ्यर्थियों एवं संस्थानों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान विधानसभा में राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्यापय) विधेयक, 2022 पारित करा चुकी है। इसमें परीक्षार्थियों को कारावास, सार्वजनिक परीक्षाओं से डिबार तथा दोषियों की संपत्ति ध्वस्त जैसे कड़े प्रावधान किए गए हैं।

जोधपुर में स्थापित होगी सूचना आयोग की बैंच

सूचना के अधिकार (आरटीआई) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अब जोधपुर में सूचना आयोग की बैंच स्थापित होगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने बैंच की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। उन्होंने कार्यालय के संचालन के लिए 12 नवीन पदों तथा आवश्यक वित्तीय प्रावधान को भी स्वीकृति दी है। इन नवीन पदों में एक पद सूचना आयुक्त का है, जिसकी नियमानुसार नियुक्ति की जाएगी।

आंगनबाड़ी मानदेय कर्मियों एवं शिशुपालना गृह कार्यकर्ताओं के मानदेय में वृद्धि

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में समेकित बाल विकास सेवाएं विभाग (ICDS) के आंगनबाड़ी केंद्रों एवं शिशुपालना गृह पर कार्यरत मानदेय कर्मियों को दिए जाने वाले मानदेय के राज्यांश में 15 प्रतिशत की वृद्धि करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है।

आईसीडीएस विभाग के आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत मानदेय कर्मियों-आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका एवं शिशुपालना गृह कार्यकर्ताओं के मानदेय में 15 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। वर्तमान में इन कर्मिकों को मानदेय का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार द्वारा 60:40 के अनुपात में किया जा रहा है। यह वृद्धि इन कर्मिकों को राज्य सरकार द्वारा दिये जा रहे कुल मानदेय का 15 प्रतिशत होगी। इससे राज्य सरकार पर प्रतिवर्ष 70 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा।

प्रतापगढ़ में पीपलखूंटा हाइलेवल कैनाल के लिए 2000 करोड़ रुपये स्वीकृत

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने प्रतापगढ़ जिले में पीपलखूंटा हाइलेवल कैनाल के निर्माण के लिए 2,000 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। इस योजना से जिले के 5,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध हो सकेगी।

पीपलखूंट हाइलेवल कैनाल के तहत माही बेसिन के अधिशेष जल से प्रतापगढ़ जिले के अनकमांड क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस योजना से जिले की पीपलखूंट तहसील के पीपलखूंट, राजड़ी चौकी, टामटिया, नालचौकी, नालदा, केलामेला, बोरी, महुड़ीखेड़ा, मोरवानिया, ठेचला, सोबनिया, जेथलिया आदि गांव लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री की इस स्वीकृति से 3.72 टीएमसी अतिरिक्त सिंचाई जल उपलब्ध होने से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा तथा क्षेत्र का विकास सुनिश्चित हो सकेगा।

जयपुर में स्थापित होगी बिहेवियरल लैब

जयपुर स्थित हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान में बिहेवियरल लैब की स्थापना होगी। इसके लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 1.22 करोड़ रुपये के वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह एचसीएम रीपा के पटेल भवन में स्थापित की जाएगी। यह देश में अत्याधुनिक तकनीक से बनाई जा रही पहली बिहेवियरल लैब होगी। करीब 2,665.04 वर्गफीट एरिया में स्थापित होने वाली लैब का प्रबंधन एवं संचालन आईआईएम उदयपुर द्वारा किया जाएगा। आईआईएम उदयपुर की फैकल्टी प्रायोगिक विधियों पर प्रशिक्षण प्रदान करेगी। यहां पीएचडी स्तर के सर्टिफिकेट कोर्स संचालित होंगे।

पन्नाधाय, अमरा जी भगत और केसरी सिंह बारहठ का बनेगा पेनोरमा

राज्य में स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारहठ, महाबलिदानी पन्नाधाय और लोकदेवता अमरा जी भगत के पेनोरमा का निर्माण होगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इन पेनोरमा के निर्माण के लिए 12 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। ये पेनोरमा भावी पीढ़ी के लिए प्रेरणास्रोत साबित होंगे।

श्री गहलोत की स्वीकृति से चित्तौड़गढ़ जिले में पन्नाधाय के पैतृक स्थल पांडोल में 4 करोड़ रुपये की लागत से पन्नाधाय पेनोरमा बनेगा। पेनोरमा में पन्नाधाय के कृतित्व एवं व्यक्तित्व को विभिन्न माध्यमों से दर्शाया जाएगा। आमजन को उनके बलिदान, त्याग, साहस एवं स्वाभिमान की जानकारी मिलेगी।

चित्तौड़गढ़ जिले में लोकदेवता अमरा जी भगत (अनगढ़ बावजी) का पेनोरमा भी 4 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होगा। यहां सामाजिक सरोकार के कार्यों के बारे में जानकारी मिलेगी। भीलवाड़ा के शाहपुरा में स्वतंत्रता सेनानी श्री केसरी सिंह बारहठ के पेनोरमा का निर्माण होगा। इसमें 4 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इन पेनोरमा से युवा वर्ग अपने अधिकारों के प्रति शिक्षित और जागृत होगा।

इन तीनों ही पेनोरमा में मुख्य भवन, सभागार, हॉल, पुस्तकालय, प्रतिमा, छतरी, शिलालेख, स्कल्पचर्स, ऑडियो-वीडियो सिस्टम जैसे विभिन्न कार्य होंगे। तीनों जगह निर्माण कार्य पर्यटन विकास कोष से कराए जाएंगे।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन अब न्यूनतम एक हजार रुपये प्रतिमाह

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए सामाजिक सुरक्षा के तहत दी जाने वाली मासिक पेंशन राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। वर्तमान में देय 500-750 रुपये प्रतिमाह पेंशन राशि अब न्यूनतम 1 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेगी। वृद्धावस्था, एकलनारी, विशेष योग्यजन, लघु एवं सीमांत कृषक पेंशन में पात्र आवेदकों को बढ़ी हुई पेंशन राशि मई से मिलेगी, जो कि एक जून 2023 को देय होगी।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं में पेंशन दरों में वृद्धि से अब राज्य सरकार पर प्रतिमाह 185 करोड़ रुपये और प्रतिवर्ष 2222.70 करोड़ रुपये का अतिरिक्त भार आएगा। अभी प्रतिमाह लगभग 700 करोड़ रुपये व्यय होते हैं।

स्टार्टअप को बिना टेंडर मिल सकेंगे 25 लाख रुपये तक के कार्य

अब प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा स्टार्टअप से बिना टेंडर खरीद (Procurement) की सीमा को 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दिया गया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता (आरटीपीपी) नियम 2013 में संशोधन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

राजस्थान स्टार्टअप पॉलिसी, 2022 में स्टार्टअप को एक वित्तीय वर्ष में दिए जाने वाले कायदेशों (वर्क ऑर्डर) की संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 6 किया गया है। इसके अलावा महिला, विशेष योग्यजन, ट्रांसजेंडर, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के स्टार्टअप को एक कायदेश अतिरिक्त मिल सकेगा। अब तक स्टार्टअप को अधिकतम 3 कायदेश ही मिलते थे।

900 ग्राम पंचायतों में खुलेंगे पशु चिकित्सा उप केंद्र

प्रदेश की 900 ग्राम पंचायतों में पशु चिकित्सा उप केंद्र खुलेंगे। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने उप केंद्र खोलने और संचालन के लिए नवीन पद सृजन की स्वीकृति प्रदान की है।

इससे प्रत्येक उप केंद्र में एक पशुधन सहायक और एक जलधारी का नवीन पद (कुल 1,800 पद) सृजित होगा। श्री गहलोत के इस निर्णय से पशुपालकों को पशुओं से संबंधित बीमारियों की जांच तथा उपचार की बेहतर सुविधाएं स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री द्वारा 2023-24 के बजट में नवगठित 1,200 ग्राम पंचायतों और पशु चिकित्सा संस्था विहीन पुरानी 1,439 ग्राम पंचायतों में उप केंद्र खोले जाने के लिए घोषणा की गई थी। इस घोषणा की क्रियान्विति में अब वर्ष 2023-24 में 900, वर्ष 2024-25 में 900 और वर्ष 2025-26 में 839 पशु चिकित्सा उप केंद्र खोले जाएंगे।

अंतरजातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि अब 10 लाख रुपये

डॉ. सविता बेन अंबेडकर योजना के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह पर प्रोत्साहन राशि अब 10 लाख रुपये मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राशि

बढ़ाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। अभी तक यह राशि 5 लाख रुपये मिलती रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित डॉ. सविता बेन अंबेडकर अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत अंतरजातीय विवाह के उपरांत 10 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस राशि में से 5 लाख रुपये 8 वर्ष के लिए फिक्स्ड डिपोजिट कराए जाएंगे। शेष 5 लाख रुपये संयुक्त बैंक खाते में जमा कराए जाएंगे।

बाइमेर के गुड़ामालानी में क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना

बाइमेर जिले के ग्राम गुड़ामालानी में भारतीय बाजरा अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद के क्षेत्रीय बाजरा अनुसंधान स्टेशन की स्थापना होगी। इसके लिए मंत्रिमंडल ने भूमि आवंटन के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है। संस्थान के लिए 40 हेक्टेयर (98.8) एकड़ भूमि टोकन मनी आवंटन करने का निर्णय लिया गया।

अभ्यर्थियों की एमबीबीएस की सरकारी सीटों पर ट्यूशन फीस होगी माफ

कैबिनेट बैठक में राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों, झालावाड़ मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल सोसायटी तथा राजमेस के द्वारा संचालित चिकित्सा महाविद्यालयों के एमबीबीएस पाठ्यक्रम में एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस एवं महिला विद्यार्थियों की तर्ज पर एमबीसी और ओबीसी वर्ग के नॉन क्रीमीलेयर अभ्यर्थियों की सरकारी सीटों पर ट्यूशन फीस माफ करने का निर्णय लिया गया है। एमबीसी और ओबीसी वर्ग के नॉन-क्रीमी लेयर अभ्यर्थियों को सत्र 2022-23 से ट्यूशन फीस में छूट का लाभ मिल सकेगा। फीस संरचना में एकरूपता आने से विद्यार्थियों को प्रवेश के समय काउंसलिंग संबंधी निर्णय लेने में सुविधा होगी।

छितराई बसावट के बावजूद जल कनेक्शन देने में राज्य तीसरे स्थान पर

विषम भौगोलिक परिस्थितियों और छितराई बसावट के बावजूद राज्य सरकार जल जीवन मिशन के कार्यों को पूरा करने में कोई कमी नहीं रख रही है। मिशन में प्रतिदिन जल कनेक्शन देने में राजस्थान देश में तीसरे स्थान पर है। राज्य में फरवरी, 2023 में औसतन 7,142 कनेक्शन प्रतिदिन दिए गए तथा मार्च, 2023 में औसतन 8,000 कनेक्शन प्रतिदिन देने का लक्ष्य रखा गया है। विभाग द्वारा मई, 2022 की तुलना में फरवरी, 2023 में औसतन प्रतिदिन 6 गुना अधिक कनेक्शन दिए गए हैं। अभी तक लगभग 36.28 लाख कनेक्शन जारी किए जा चुके हैं। राजस्थान की इस प्रगति को केंद्र सरकार द्वारा भी सराहा गया है। आमजन को सुलभ पेयजल उपलब्धता के लिए जल जीवन मिशन में अभी तक 13 हजार करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। इसमें राजस्थान देश के अग्रणी राज्यों में चौथे स्थान पर है।

सामूहिक विवाह योजना में बढ़ाया अनुदान

राज्य सरकार ने सामूहिक विवाह सम्मेलनों को प्रोत्साहन देने के लिए अनुदान राशि को बढ़ाया है। सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अब प्रति जोड़ा 25 हजार रुपये दिए जाएंगे। इसमें नववधू को 21 हजार रुपये और संस्था को 4 हजार

रुपए का अनुदान मिलेगा। यह राशि 1 अप्रैल, 2023 से संपन्न विवाह सम्मेलनों को देय होगी। अभी यह राशि क्रमशः 15 हजार और 3 हजार रुपये अर्थात् कुल 18 हजार रुपये दी जा रही है। बजट 2023-24 में अनुदान राशि बढ़ाने संबंधित घोषणा की गई है।

पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त कार्मिकों के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने सेवानिवृत्त कार्मिकों के सेवा में पुनर्नियोजित होने पर मिलने वाले मासिक समेकित पारिश्रमिक की दरों में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

उक्त प्रस्ताव के अनुसार, राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम-2017 की पे-मैट्रिक्स के पे-लेवल के प्रथम सेल की 50 प्रतिशत राशि तथा उस पर विद्यमान महंगाई भत्ते 38 प्रतिशत की राशि को जोड़कर 100 के गुणक में समेकित पारिश्रमिक राशि निर्धारित की गई है। इससे मासिक समेकित पारिश्रमिक राशि की दरें लगभग दोगुनी हो गई हैं।

रोडवेज की साधारण बसों के किराए में महिलाओं को 50 प्रतिशत छूट

राजस्थान रोडवेज की बसों में अब महिलाओं को सिर्फ 50 प्रतिशत किराया ही देना होगा। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने महिलाओं को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की साधारण बसों में राज्य की सीमा में किराए की छूट सीमा में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। राजस्थान रोडवेज की साधारण बसों में छूट 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 50 प्रतिशत की गई है।

यह छूट 1 अप्रैल, 2023 से लागू की गई है। साथ ही, निगम की साधारण बसों के अतिरिक्त शेष श्रेणी की बसों में महिलाओं को 30 प्रतिशत छूट यथावत रहेगी। इस निर्णय से राज्य सरकार पर लगभग 3.50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त वार्षिक वित्तीय भार आएगा।

पालनहार योजना के अंतर्गत मिलने वाली सहायता राशि

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने पालनहार योजना के अंतर्गत अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के लाभार्थियों को दी जाने वाली सहायता राशि में वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। श्री गहलोत के इस संवेदनशील निर्णय से प्रदेश के 6.5 लाख से अधिक बच्चे लाभान्वित होंगे।

प्रस्ताव के अनुसार, अनाथ श्रेणी के अतिरिक्त अन्य श्रेणी के 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रतिमाह मिलने वाली 500 रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर 750 रुपये तथा 6 से 18 वर्ष आयु वर्ग को मिलने वाली 1,000 रुपये की सहायता राशि को बढ़ाकर 1,500 रुपये कर दिया गया है। सहायता राशि में यह वृद्धि 1 जुलाई, 2023 से प्रभावी होगी। ●



वित्त और विनियोग विधेयक चर्चा पर मुख्यमंत्री की घोषणाएं

वर्ष 2023-24 हेतु 10 फरवरी, 2023 को प्रस्तुत बजट तथा 16 फरवरी, 2023 को बजट बहस के जवाब में की गई घोषणाओं के माध्यम से जहां राज्य सरकार ने अल्प आय वर्ग के साथ ही मध्यम वर्ग को भी महंगाई से राहत देने का प्रयास किया, वहीं युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तथा प्रदेश के चहुंमुखी विकास के लिए आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने का कार्य भी किया है। इसी क्रम में 17 मार्च, 2023 को नवीन घोषणाएं सदन के समक्ष प्रस्तुत की गईं जो इस प्रकार हैं:

शिक्षा एवं युवा विकास

- ❖ वर्ष 2022-23 के बजट में जयपुर में JLN मार्ग पर 'Education Hub' बनाने की घोषणा की गई थी। इसी कड़ी में, आगामी वर्ष राजस्थान विश्वविद्यालय, कॉमर्स कॉलेज एवं राजस्थान कॉलेज के upgradation हेतु 50 करोड़ रुपये के कार्य हाथ में लिए जाएंगे।
- ❖ मौजूदा राज्य सरकार द्वारा कोरोना काल के दौरान शिक्षा में हुए नुकसान की भरपाई के लिए इस वर्ष कक्षा VIII तक के विद्यार्थियों के लिए Bridge Courses चलाये गए थे। इनकी सफलता को देखते हुए आगामी वर्ष भी 75 करोड़ रुपये व्यय कर Bridge Courses चलाए जाएंगे। इससे लगभग 70 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे।
- ❖ स्कूल शिक्षा की सुविधा सुलभ कराने की दृष्टि से 500 प्राथमिक विद्यालयों का उच्च प्राथमिक विद्यालयों में तथा 500 उच्च प्राथमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया जाएगा। साथ ही, 400 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि संकाय/विषय प्रारंभ किए जाएंगे।
- ❖ विशाला-बाड़मेर, भुसावर-भरतपुर, तालचिड़ी-दौसा, फलसुंड -जैसलमेर, बिसाउ (मंडावा)-झुंझुनू, कुचामनसिटी, खजवाना, रियाबड़ी -नागौर एवं सूरौठ (हिंडौन सिटी)-करीली में राजकीय महाविद्यालय खोले जाएंगे।
- ❖ शाहबाद (किशनगंज)-बारां, समदड़ी-बाड़मेर, बज्जू (कोलायत) -बीकानेर, छारेडा-दौसा, आमेर-जयपुर, झालामंड (लूणी), जैसला (घंटियाली)-जोधपुर एवं बर-पाली में राजकीय कन्या महाविद्यालय खोले जाएंगे।

- ❖ नारेड़ा (दूदू)-जयपुर में शास्त्री संस्कृत महाविद्यालय एवं नावां-नागौर, दौसा एवं चित्तौड़गढ़ में विधि महाविद्यालय खोले जाएंगे।
- ❖ प्रदेश में शिक्षण सुविधा विस्तार हेतु विभिन्न विद्यालय, छात्रावास, आईटीआई खोले जाने, विद्यालयों/महाविद्यालयों के क्रमोन्नयन, नवीन विषय/संकाय प्रारंभ करने के साथ-साथ अन्य सुविधाओं का विस्तार किया जायेगा।
- ❖ प्रदेश के पंजीकृत मदरसों में अध्ययन-अध्यापन सुविधाओं का विस्तार करने की दृष्टि से-

- I. शिक्षा विभाग की तर्ज पर प्रति विद्यार्थी 2 सेट निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस पर लगभग 15 करोड़ रुपये का व्यय कर 2 लाख से अधिक विद्यार्थियों को लाभान्वित किया जाएगा।
 - II. शिक्षा अनुदेशक (मदरसा पैराटीचर्स) के 6 हजार 843 पदों पर भर्ती की जाएगी।
- ❖ राज्य के युवाओं/विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास में एनसीसी की महती भूमिका को ध्यान में रखते हुए एनसीसी ग्रुप मुख्यालय, जोधपुर में प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना की जाएगी। इस पर 15 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

खेल

- ❖ युवाओं का खेलों की ओर रुझान बढ़ाने तथा खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलम्पिक्स का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रकार पंचायत से राज्य स्तर तक होने वाली खेल गतिविधियों को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए संभाग स्तर पर खेल प्रबंधक तथा जिला स्तर पर सहायक खेल प्रबंधक के नवीन पदों का सृजन किया जाएगा।
- ❖ चूरू व पाली में 10 करोड़ रुपये की लागत से स्पोर्ट्स स्कूल स्थापित किये जाएंगे।
- ❖ खेल प्रतिभाओं को समुचित प्रोत्साहन देने के लिए उठाये गए कदमों की कड़ी में खेल अकादमी, स्टेडियम, इनडोर हॉल आदि के निर्माण/विकास कार्य करवाये जाएंगे।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य

- ❖ चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को वृहद् रूप देते हुए कॉकलियर इम्प्लान्ट के replacement एवं Type-I diabetes mellitus (T1DM) से प्रभावित रोगियों हेतु Insulin Pumps के पैकेज को आवश्यकतानुसार शामिल किया जाएगा।
- ❖ प्रदेश के राजकीय चिकित्सा संस्थानों के माध्यम से मुख्यमंत्री निशुल्क निरोगी राजस्थान (दवा) योजना के अंतर्गत विभिन्न दवाइयों की उपलब्धता को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने की दिशा में एक और कदम उठाते हुए Rajasthan Drugs and Pharmaceutical Limited (RDPL) कंपनी को राजकीय कंपनी (State PSU) के रूप में पुनर्जीवित किया जाएगा।
- ❖ प्रदेश में चिकित्सा सेवाओं के विस्तार एवं आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने की दृष्टि से उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप जिला चिकित्सालय, जिला चिकित्सालय, ट्रोमा सेंटर, ब्लड बैंक आदि खोले/क्रमोन्नत किए जाने के साथ-साथ अन्य सुविधायें विकसित की जाएंगी।
- ❖ सवाई मानसिंह चिकित्सालय/महाविद्यालय, जयपुर में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार हेतु:
 - I. 'Stroke Intervention Lab' स्थापित की जाएगी।
 - II. दवा वितरण केंद्र एवं सैपल कलेक्शन हेतु 15 करोड़ रुपये की लागत से बहुमंजिला भवन का निर्माण करवाया जाएगा।
 - III. बढ़ते रोगीभार एवं आमजन की सुविधा के दृष्टिगत सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर में 75 करोड़ रुपये की लागत से पार्किंग सुविधा विकसित की जाएगी।

सड़क सुरक्षा

- ❖ सड़क सुरक्षा की दृष्टि से राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त वाहन चालन प्रशिक्षण केंद्रों/स्कूलों के निर्धारित प्रशिक्षण वाहनों को मोटर वाहन कर से मुक्त किया जाएगा।

सामाजिक सुरक्षा

- ❖ विशेष योग्यजन की आवश्यकताओं के दृष्टिगत प्रतिष्ठित NGOs के माध्यम से प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर मानसिक विमर्दित महिलाओं हेतु पुनर्वास गृह संचालित करने तथा प्रत्येक जिले में राजकीय मानसिक विमर्दित, मूक, बधिर, नेत्रहीन श्रेणी के विशेष योग्यजन विद्यालय खोले जाएंगे।
- ❖ 80 प्रतिशत से अधिक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के पक्ष में निष्पादित सभी प्रकार के विलेखों पर स्टाम्प ड्यूटी निशुल्क की जाएगी। साथ ही, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के पक्ष में अचल संपत्ति के दस्तावेजों पर भी स्टाम्प ड्यूटी निशुल्क की जाएगी।
- ❖ प्रदेश में महिलाओं को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराने के लिए आगामी वर्ष प्रथम चरण के रूप में नगरीय क्षेत्रों के बाजारों एवं Public Places पर महिलाओं के लिए सुलभ संस्था के माध्यम से 500 स्थानों पर टॉयलेट बनाए जाने के साथ ही 5 हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामीण कस्बों में भी महिलाओं के लिए टॉयलेट एवं स्नानागार कॉम्प्लेक्स का निर्माण किया जाएगा। इन पर लगभग 100 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- ❖ 1 नवंबर, 1962 से विभिन्न युद्धों एवं आपरेशनों में पदकों से अलंकृत प्रदेश के शूरवीरों को देय सुविधाओं में विसंगतियों को दूर किए जाने के साथ ही तटरक्षक (Coast Guard) मेडल से अलंकृत सैनिकों के लिए भी आवश्यक प्रावधान किए

जाएंगे। साथ ही, नगी (श्रीकरणपुर)-श्रीगंगानगर में भारत-पाक सीमा पर स्थित वार मेमोरियल सेंटर में विकास कार्य करवाए जाएंगे।

- ❖ इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत प्राप्त ऑनलाइन आवेदनों को ध्यान में रखते हुए पात्रता की अधिकतम आय सीमा को 40 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की जाएगी तथा इस योजना की अवधि को 31 मार्च, 2024 तक बढ़ाया जाएगा।

आधारभूत सुविधाएं

- ❖ प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क, पुल व ROB आदि के निर्माण एवं उन्नयन कार्य 2 हजार 600 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से करवाए जाएंगे।
- ❖ विधायकगण द्वारा वर्ष 2011 के बाद घोषित राजस्व गांवों को सड़क से जोड़ने की मांग को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2023-24 के बजट में 500 से अधिक आबादी वाले राजस्व गांवों को डामर सड़कों से जोड़ने की घोषणा की गई थी। आदिवासी एवं मरुस्थलीय क्षेत्रों की परिस्थिति को देखते हुए इन क्षेत्रों के 250 से अधिक आबादी वाले राजस्व गांवों को चरणबद्ध रूप से जोड़ा जाएगा।
- ❖ आमजन की सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राज्य सरकार के अधीन संचालित विभिन्न टोल सड़कों पर Toll Collection हेतु फास्टैग (FASTag) सुविधा लागू की जाएगी। इस हेतु 48 करोड़ रुपये का व्यय होगा।
- ❖ किशनगढ़-अजमेर की हवाई पट्टी (Air Strip) के विस्तार में पहाड़ी क्षेत्र के कारण उत्पन्न बाधा को दूर कर Commercial Airport के रूप में स्थापित करने हेतु DPR बनाई जाएगी।
- ❖ आमजन को और अधिक राहत पहुंचाने के उद्देश्य से आगामी वर्ष माह में अप्रैल से प्रशासन गांवों के संग तथा प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया जाएगा। इसी अभियान में शिविरों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के पात्र लाभान्वितों (beneficiaries) के Registration का कार्य भी किया जाएगा, जिससे कोई भी पात्र व्यक्ति/परिवार योजनाओं का लाभ लेने से वंचित नहीं रह जाए। इसी के साथ इन अभियानों में विभिन्न विभागों से संबंधित पूर्व में किए जाने वाले कार्यों के साथ ही अधिक राहत दी जाएगी, जो इस प्रकार है:
 - I. राजस्व शिविरों में राजस्व लोक अदालतों का आयोजन भी किया जाएगा।
 - II. नगरीय क्षेत्रों के परिधि नियंत्रण क्षेत्रों में स्थित ग्राम की आबादी के 500 मीटर की परिधि में कृषि भूमि का अकृषि (आवासीय) उपयोग होकर 31 दिसंबर, 2013 से पूर्व भूखंड पर निर्माण हो चुका हो, ऐसी स्थिति में 30 सितंबर, 2023 तक की अवधि के दौरान 300 वर्ग मीटर तक के आवासीय भूखंडों के लिए प्रीमियम दर 5 रुपये प्रति वर्ग मीटर निर्धारित की जाएगी। इस प्रीमियम दर के अनुसार 10 वर्ष की लीज राशि एकमुश्त जमा कराने पर फ्री-होल्ड पट्टे जारी किए जाएंगे।
 - III. साथ ही, इस अवधि में नगरपालिका सीमा में कृषि भूमि पर ऐसे भूखंड, जो पुरानी आबादी क्षेत्र के पास 2 मई, 2012 से पूर्व कृषि भूमि का अकृषि उपयोग होकर बिखरे हुए निर्मित भूखंड के रूप में विद्यमान हैं, उनको फ्री-होल्ड पट्टे दिये जाने हेतु 300 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखंड पर 501 रुपये एकमुश्त तथा उक्तानुसार निर्धारित प्रीमियम राशि के बराबर 10 वर्ष की एकमुश्त लीज राशि ली जाकर पट्टा दिया जाएगा।
 - IV. राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 'स्वामित्व योजना' के तहत ग्राम पंचायत की आबादी भूमि में आवासीय भूमिधारकों को नियमानुसार पट्टे दिए जा रहे हैं।

इस क्रम में, 30 जून, 2023 तक की अवधि हेतु राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157 के अधीन ली जाने वाली दरों में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।

❖ प्रदेश के सुनियोजित विकास हेतु 189 शहरों के लिए मास्टर प्लान बनाये जा चुके हैं। इसी कड़ी में नवगठित 44 नगरपालिकाओं तथा इस बजट में घोषित नगरीय निकायों के मास्टर प्लान भी तैयार किए जाएंगे। साथ ही, निकाय सीमाओं की समीक्षा कर विस्तार किया जाएगा।

❖ सरकारी/सामुदायिक परिसंपत्तियों/भूमियों को अतिक्रमण से सुरक्षित रखने के लिए MLA LAD योजना में बाउंड्रीवाल के साथ-साथ तारबंदी को भी अनुमत किया जाएगा।

❖ अमृत 2.0 योजना के तहत राज्य के 29 शहरों में सीवरेज के कार्य कराये जाएंगे। इस हेतु 4 हजार 700 करोड़ रुपये की परियोजनाओं के कार्य हाथ में लिये जाएंगे।

❖ जयपुर हेरिटेज क्षेत्र की पुरानी एवं जीर्ण-शीर्ण सीवरेज लाइनों को बदलने का कार्य करवाया जाएगा। इन पर 296 करोड़ रुपये व्यय होंगे।

❖ प्रदेश में सीवरेज व ड्रेनेज संबंधी विभिन्न कार्य करवाये जाएंगे।

❖ डोल तालाब-बारों का सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्यों हेतु 50 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे। साथ ही, श्री गलता पीठ-जयपुर में वर्षा जल संचयन कर कानोता बांध तक ले जाने एवं कियारा बांध की मरम्मत, पुनर्निर्माण हेतु डीपीआर बनाई जाएगी।

पेयजल

❖ आने वाले गर्मी के मौसम में आमजन को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में आवश्यकतानुसार 40 हैंडपंप एवं 10 ट्यूबवेल तक लगवाए जाएंगे।

❖ जल जीवन मिशन के अंतर्गत जाखम बांध से उदयपुर, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ एवं राजसमंद जिलों के 8 कस्बों व 1 हजार 473 गांवों के लगभग 3 लाख परिवारों हेतु 4 हजार 674 करोड़ रुपये व्यय कर घर-घर जल कनेक्शन उपलब्ध कराए जाएंगे।

❖ प्रदेश में पेयजल सुविधा के विस्तार हेतु विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे।

उद्योग

❖ वर्तमान समय में Retail के साथ-साथ e-Commerce का भी प्रचलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। अतः इन Sectors के विकास की दृष्टि से Rajasthan Retail Policy तथा Rajasthan e-Commerce Policy लाई जाएगी।

❖ प्रदेश में विशेष योग्यजन, एकल महिला एवं अन्य वंचित वर्ग को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए Retail Sectors में प्रतिष्ठित Private Partners के माध्यम से एक हजार Franchisees खोली जाएंगी। इस हेतु चयनित व्यक्तियों को Training कराने के साथ ही प्रति Franchisee एक लाख रुपये का अनुदान दिया जाएगा।

❖ राज्य में खनिज बजरी के अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं आमजन को सस्ती बजरी उपलब्ध कराने के लिए चयनित स्थानों पर नदियों में 100 हेक्टेयर आकार तक के प्लॉट बनाकर पिट माउथ पर न्यूनतम विक्रय मूल्य पर बजरी उपलब्ध कराने वाले निविदादाताओं को खनन पट्टे आवंटित किए जाएंगे।

❖ बाड़मेर स्थित Petro-Zone के औद्योगिक विकास को समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने हेतु इसे RIPS-2022 के अंतर्गत Area Category-2 से परिवर्तित कर Area Category-3 में सम्मिलित किया जाएगा।

❖ RIPS-2022 के अंतर्गत नवीन निवेश हेतु चूंकि 50 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश की आवश्यकता है। तदनुसार किसी उद्यम के 50 करोड़ रुपये के अतिरिक्त निवेश की स्थिति में भी योजनान्तर्गत विस्तार हेतु परिणाम दिया जाएगा।

❖ कोटा, जोधपुर, भरतपुर व बीकानेर संभाग में कृषि व बुनकरों को प्रशिक्षित करने के लिए शुरू किये गये Training Centres में खादी ग्रामोद्योग संबंधी प्रशिक्षण भी प्रारंभ किया जाएगा।

❖ प्रदेश में Ease of Doing Business (EoDB) की दिशा में एक और कदम उठाते हुए अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NoC) की प्रक्रिया के सरलीकरण के साथ-साथ शुल्क को Rational करते हुए Automated स्वीकृति जारी की जाएगी। साथ ही, सिनेमा लाइसेंस एवं नवीनीकरण (Renewal) प्रक्रिया का आधुनिक आवश्यकताओं के अनुरूप सरलीकरण किया जाएगा।

ऊर्जा

❖ प्रदेश में 31 मार्च, 2019 के बाद 'प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर' (सौभाग्य) योजना समाप्त होने के उपरांत लगभग 2 लाख परिवार (Households) धरेलू विद्युत कनेक्शन से वंचित रह गए थे। आगामी 2 वर्षों में इन सभी वंचित 2 लाख परिवारों को लगभग एक हजार करोड़ रुपये की लागत से धरेलू कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएंगे।

❖ कृषि श्रेणी के नियमित अथवा कटे हुए तथा गैर कृषि श्रेणी के अंतर्गत कटे हुए विद्युत कनेक्शनों हेतु 31 दिसंबर, 2022 तक देय विलंब राशि व ब्याज में चरणबद्ध छूट की अवधि 30 सितंबर, 2023 तक बढ़ाई जाएगी। इससे 22 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित होंगे।

❖ ऊर्जा तंत्र के आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न श्रेणी के जीएसएस स्थापित करने के साथ-साथ विद्युत कार्यालय खोले जाएंगे।

वन एवं पर्यावरण

❖ वन क्षेत्रों में विभिन्न गतिविधियों, पौधारोपण तथा वन्य जीवों की देखभाल से संबंधित कार्य हाथ में लिये जाएंगे, जो इस प्रकार हैं:

- I. युवाओं को वन क्षेत्रों में हाइकिंग, ट्रेकिंग, कैम्पिंग एवं अन्य रोमांचकारी गतिविधियों से जोड़ने के लिए तारागढ़-अजमेर, चूहड़सिद्ध-अलवर, रामगढ़ क्रेटर-बारों, ब्रज चौरासी क्षेत्र -भरतपुर, हमीरगढ़ व मंगरोप-भीलवाड़ा, हथिनी औदी व मेनाल वाटरफाल क्षेत्र-चित्तौड़गढ़, मेढा व गोलमेन-दौसा, दमोह -धौलपुर, बुचारा व कचरावाला-जयपुर, मातरमाता-सिरोही, बोलेश्वर-सीकर, धूणीमाता व कमलेश्वर महादेव-प्रतापगढ़ तथा नाल सांडील-उदयपुर में लगभग 10 करोड़ रुपये की लागत से कार्य करवाए जाएंगे।
- II. राज्य में पक्षियों के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु 50 पक्षी घर (Birds Shelter Home) बनाए जाएंगे।
- III. बीकानेर एवं अजमेर में बायोलॉजिकल पार्क, जयपुर जंतुआलय (Zoo) को पक्षी विहार, बीकानेर जंतुआलय (Zoo) को पक्षी विहार एवं रेस्क्यू सेंटर के रूप में 20 करोड़ रुपये व्यय कर विकसित किया जाएगा। साथ ही, वन्य जीवों को समय पर रेस्क्यू करने व एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, बेहतर निरीक्षण, वन सुरक्षा एवं वाहन उपलब्ध कराये जाने हेतु 50 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
- IV. गोडवाड देसूरी-पाली में लेपर्ड कंजर्वेशन रिजर्व विकसित किया जाएगा।

साथ ही, संरक्षित वन क्षेत्र वाडा खेड़ा- सिरौही में विकास एवं सुदृढीकरण के कार्य करवाए जाएंगे।

- V. नर्सरियों में सुधार एवं नवीन नर्सरियों की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये व्यय किये जाएंगे।

पर्यटन, कला एवं संस्कृति

❖ जयपुर स्थित गोविंद देवजी के मंदिर में संपूर्ण प्रदेशवासियों की असीम आस्था है। इसके दृष्टिगत गोविंद देवजी मंदिर का महाकाल, उज्जैन की तर्ज पर वृहद् विकास किया जाएगा। प्रथम चरण में आगामी वर्ष इस हेतु 100 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित है। साथ ही, तीर्थराज पुष्कर के समग्र विकास हेतु पुष्कर विकास प्राधिकरण (Pushkar Development Authority) का गठन किया जाएगा।

❖ प्रदेश में आने वाले पर्यटकों की सुविधा के लिए Rajasthan Smart Tourist Pass प्रारंभ किया जाएगा। इस Pass के द्वारा सिटी ट्रांसपोर्ट एवं रोडवेज की बसों में यात्रा के साथ-साथ समस्त पर्यटन स्थलों व स्मारकों में प्रवेश की सुविधा hassle free उपलब्ध हो सकेगी।

❖ पर्यटन को बढ़ावा दिये जाने की दृष्टि से Tour Operators Associations (IATO/ RATO) से मान्यता प्राप्त Tour Operators द्वारा संचालित वातानुकूलित पर्यटक लम्बरी कौचों को मोटर वाहन कर से मुक्त किया जाएगा।

❖ सांवलिया सेठ-चित्तौड़गढ़ में जलझूलनी एकादशी मेले को भी 50 प्रतिशत बस किराया छूट योजना में सम्मिलित किया जाएगा।

❖ बेणेश्वर धाम-डूंगरपुर के समग्र विकास की कार्ययोजना तैयार करते हुए आगामी वर्ष 100 करोड़ रुपये के विकास कार्य करवाए जाएंगे।

❖ धार्मिक पर्यटन विकास की दृष्टि से विभिन्न पर्यटक स्थलों के जीर्णोद्धार एवं उन्नयन संबंधी कार्य करवाये जाएंगे, ये कार्य हैं:

- I. खाटूश्यामजी-सीकर में श्रद्धालुओं के मंदिर तक पहुंचने के लिए लगभग 32 करोड़ रुपये की लागत से Dedicated Corridor का निर्माण करवाया जाएगा।
- II. रोजदा (जालसू)-जयपुर में स्थित श्री गोपाल जी मंदिर, ढीपरी चंबल (खातौली)-कोटा स्थित ठाकुर जी महाराज मंदिर, पीपल्दा समेल (सुल्तानपुर)-कोटा स्थित प्राचीन शिव मंदिर तथा ककरावदा (इटावा)-कोटा स्थित प्राचीन श्री चमलेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य करवाए जाएंगे।
- III. ज्वाला माता मंदिर जोबनेर-जयपुर में यात्रियों हेतु विश्राम स्थल का निर्माण करवाया जाएगा।
- IV. श्री चारभुजा मंदिर-राजसमंद, टॉडगढ़-अजमेर व बिग्गा जी धाम (डूंगरगढ़)-बीकानेर में विभिन्न विकास कार्य करवाए जाएंगे।
- V. लोहागढ़ किला एवं सुजानगंगा नहर-भरतपुर के जीर्णोद्धार, संरक्षण एवं विकास कार्य हेतु डीपीआर बनवायी जाएगी।
- VI. विभिन्न धार्मिक स्थल ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह शरीफ -अजमेर, नाकोड़ा जैन मंदिर-बाड़मेर, जैन मंदिर (रणकपुर) -पाली, गुरुद्वारा-हनुमानगढ़, बुड़ड़ा जोहड़-श्रीगंगानगर के विकास कार्यों हेतु कार्ययोजना तैयार की जाएगी।



VII. जयपुर स्थित ईदगाह में वक्फ बोर्ड के माध्यम से विकास कार्य करवाए जाएंगे।

❖ प्रदेशवासियों की विभिन्न मंदिरों में अगाध आस्था को देखते हुए त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर-बांसवाड़ा, करणी माता-बीकानेर, कैलादेवी, गोवर्धन पर्वत-भरतपुर, सालासर-चूरू, सांवलिया सेठ-चित्तौड़गढ़, मेहंदीपुर बालाजी-करोली, खोले के हनुमानजी, शाकंभरी माता (सांभर)- जयपुर, रामदेवरा, तनोट माता मंदिर-जैसलमेर, श्रीनाथजी (नाथद्वारा)- राजसमंद, वीर तेजाजी-नागौर, खाटूश्यामजी-सीकर, एकलिंगजी-उदयपुर सहित अन्य महत्वपूर्ण मंदिरों में पेनोरमा/आधारभूत सुविधाओं का समग्र विकास किए जाने हेतु 10 करोड़ रुपये की लागत से डीपीआर बनाई जाएगी।

❖ अजमेर में पृथ्वीराज, बीकानेर में राव बीकाजी, आसींद-भीलवाड़ा में बगड़ावत सवाईभोज, शाहपुरा-भीलवाड़ा में केसरी सिंह बारहठ, चित्तौड़गढ़ में पन्नाथाय, दौलतपुरा-चित्तौड़गढ़ में अमरा जी भगत, जयपुर में महात्मा ज्योतिबा फुले व शिवदासपुरा-जयपुर में स्वामी आत्माराम जी लक्ष्य, जोधपुर में महर्षि नवल स्वामी, जालौर में वीरमदेव-कान्हड़ देव चौहान, गोगुंदा-उदयपुर में राणा पूजा, पोकरण-जैसलमेर में इंदिरा महाशक्ति भारत एवं करोली में कैलादेवी के पेनोरमा बनवाए जाएंगे।

❖ देवस्थान विभाग के अधीन 593 मंदिरों में पोशाक, रंग-रोगन एवं मरम्मत आदि कार्य करवाये जाएंगे। साथ ही, राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार मंदिरों के अंशकालीन पुजारियों के मानदेय में वृद्धि कर एक समान 5 हजार रुपये प्रतिमाह किया जाएगा।

❖ लोक कला मंडल, उदयपुर के उन्नयन की डीपीआर बनाई जाएगी। साथ ही, कला एवं मार्बल नगरी किशनगढ़-अजमेर में Art Gallery तथा साइंस पार्क नवलगढ़-झुंझुनूं में display infrastructure विकसित किया जाएगा।

❖ मौलाना अबुल कलाम आजाद, अरबी फारसी शोध संस्थान, टोंक में Publication cum Museum Block का निर्माण किया जाएगा।

कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र

❖ Site Specific Nutrient Management एवं फलदार पौधों की जल मांग की सटीक जानकारी के लिए 10 हजार किसानों को New Generation Technology-Auto Sensors एवं फर्टिगेशन के प्रयोग के लिए अनुदान दिया जाएगा।

❖ इसके अतिरिक्त 10 हजार किसानों को उठी हुई क्यारी बनाने हेतु Ridge Bed Planter यंत्र भी अनुदानित दर पर उपलब्ध करवाये जाएंगे। इस हेतु 50 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।

❖ प्रदेश में कृषकों की आय बढ़ाने एवं Non-Agriculture Season में आय के

विकल्प प्रदान करने के लिए ट्रैक्टरों के व्यावसायिक पंजीयन पर लगने वाले एकबारीय शुल्क को 6 हजार से घटाकर 500 रुपये किया जाना प्रस्तावित है। साथ ही, नियमित फिटनेस सर्टिफिकेट फीस, इंस्पेक्शन फीस व ग्रीन टैक्स को 2 हजार 300 रुपये से घटाकर 200 रुपये किया जाएगा।

- ❖ कृषि मंडियों में देय कृषक कल्याण शुल्क पर मौजूदा 50 प्रतिशत की छूट को 31 मार्च, 2024 तक के लिए बढ़ाया जाएगा। साथ ही, समस्त कृषि मंडियों में व्यापारियों की सुविधा के लिए व्यापार भवन हेतु डीएलसी की 25 प्रतिशत दर पर भूमि उपलब्ध करवाई जाएगी।

- ❖ गंगापूर-भीलवाड़ा एवं गोगुंदा-उदयपुर में कृषि महाविद्यालय खोले जाएंगे।
- ❖ चाँधन-जैसलमेर एवं मारवाड़ जंक्शन-पाली में मिनी फूड पार्क विकसित किए जाएंगे।

- ❖ बेगू-चितौड़गढ़ में सब्जी-फूल मंडी तथा सावर-अजमेर, मंडेला (पिलानी)-झुंझुनू, साहडोली (रामगढ़)-अलवर, बागौर (मांडल) -भीलवाड़ा व जमवारामगढ़-जयपुर में कृषि उपज मंडी खोली जाएंगी। साथ ही, गौण कृषि उपज मंडी लोहावट-जोधपुर को कृषि उपज मंडी में क्रमोन्नत किया जाएगा।

- ❖ प्रदेश में पंजीकृत 3 हजार 636 गौशालाओं में पेयजल हेतु आवश्यकतानुसार श्री फेज ट्यूबवैल स्थापित किए जाएंगे। इस हेतु आगामी वर्ष लगभग 75 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

- ❖ पशुपालकों को बेहतर पशु चिकित्सा उपलब्ध करवाने तथा दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन देने की दृष्टि से पशु चिकित्सा संस्थान/केंद्र खोले जाने के साथ अन्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

- ❖ आगामी 3 वर्षों में धौलपुर Community Lift Irrigation Scheme के अंतर्गत धौलपुर, राजाखेड़ा व सेपऊ के 28 हजार 800 हेक्टेयर नहरी क्षेत्र को सूक्ष्म सिंचाई के तहत शामिल किया जाएगा। इससे 15 हजार किसान लाभान्वित होंगे।

- ❖ राज्य सरकार द्वारा 16 फरवरी, 2023 को प्रदेश में 100 एनिकटों के निर्माण/जीर्णोद्धार व 100 नहरी तंत्रों के जीर्णोद्धार हेतु 400 करोड़ रुपये के कार्य प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई थी। इस क्रम में विधायकों एवं प्रदेश के किसानों की ओर से कार्य की महत्ता को देखते हुए और अधिक प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। अतः एनिकटों के निर्माण/जीर्णोद्धार व नहरी तंत्र के जीर्णोद्धार हेतु निर्धारित की गई 400 करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर 800 करोड़ रुपये किया गया है।

- ❖ प्रदेश में सिंचाई संबंधी विभिन्न विकास के कार्य करवाए जाएंगे।

- ❖ बारां जिले की परवन वृहद् सिंचाई परियोजना में अटरू के 17, अंता के 10 व मांगरोल 10 वंचित गांवों को शामिल करने हेतु डीपीआर बनायी जाएगी। साथ ही, सरदारशहर-चूरू के 58 वंचित गांवों के रकबों को चौधरी कुंभाराम आर्य लिफ्ट कैनाल योजना में शामिल किया जाएगा।

- ❖ बांधों एवं नहरों के सुचारू संचालन हेतु गेज रीडर, ऑपरेटर ग्रेड-III आदि 3 हजार कार्मिकों की भर्ती की जाएगी।

कानून व्यवस्था

- ❖ प्रदेश में आपराधिक गैंग्स की गतिविधियों तथा पड़ोसी राज्यों से अपराधियों के आवागमन पर नियंत्रण की दृष्टि से 'राजस्थान संगठित अपराध का नियंत्रण कानून' लाया जा रहा है। इसी क्रम में क्षेत्र में प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने की दृष्टि से 3 अतिरिक्त कमांडो प्लाटून स्वीकृत की गई हैं।

- ❖ राजस्थान पुलिस अकादमी-जयपुर में Centre of Cyber Crime Investigation स्थापित किए जाने के साथ-साथ सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक का भी निर्माण करवाया जाएगा। इन पर 19 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

- ❖ राज्य में शहरों एवं कस्बों में सड़कों पर बढ़ते वाहनों के दबाव की स्थिति में सुगम यातायात व्यवस्था कायम किए जाने हेतु Traffic Police को सुदृढ़ करने की दृष्टि से 500 पुलिस कांस्टेबल, हैड कांस्टेबल एवं उपनिरीक्षक स्तर के पद सृजित किए जाएंगे।

- ❖ प्रदेश की कानून व्यवस्था तथा न्याय प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ करने हेतु पुलिस कार्यालय एवं न्यायालय खोले जाने के साथ-साथ विभिन्न सुविधाएं विकसित की जाएंगी।

सुशासन

- ❖ आमजन को पारदर्शी एवं त्वरित सेवाएं उपलब्ध करवाने तथा कार्यालयों में होने वाली Work Processing को IT के माध्यम से Online करने में आज प्रदेश संपूर्ण देश में अग्रणी स्थान रखता है। विभिन्न विभागों से संबंधित IT Softwares का लाभ दूरस्थ क्षेत्रों में निवास करने वाले प्रदेशवासियों को मिल सके, इस हेतु राज्य सरकार ने ग्राम विकास अधिकारी/पटवारी, तहसीलदार/विकास अधिकारी से लेकर जिला प्रमुख/कलक्टर आदि तक Tablet देने का निर्णय किया। अब इसी क्रम में, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों, न्यायिक अधिकारियों तथा जिला स्तरीय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों को राजकीय कार्यों एवं दायित्वों के बेहतर निष्पादन हेतु Laptop/Tablet दिए जाएंगे।

- ❖ प्रदेश के इस विकसित आईटी तंत्र का लाभ घर बैठे प्राप्त करने हेतु संबल प्रदान करने की दृष्टि से गत बजट में चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को Smart Phone मय Internet Connectivity उपलब्ध करवाने हेतु मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना की घोषणा की गई थी। इस निर्णय के बाद अंतरराष्ट्रीय स्तर पर Smart Phone/Automobiles में प्रयोग किये जाने वाले Chipset की Crisis उत्पन्न हो गई थी। इस कारण Smart Phone की उपलब्धता की समस्या के साथ ही कीमतों में भी वृद्धि हो गई। फिर भी इस कार्य को अब चरणबद्ध रूप से पूर्ण किया जाएगा। प्रथम चरण के रूप में आगामी वर्ष बहन-बेटियों के पावन पर्व 'राखी' से चिरंजीवी परिवारों की सरकारी विद्यालयों में 10वीं से 12वीं कक्षा में अध्ययनरत छात्राओं, सरकारी उच्च शिक्षण संस्थाओं (महाविद्यालय/ ITI/ Polytechnic) में अध्ययनरत छात्राओं तथा विधवा/एकल नारी पेंशन प्राप्त कर रही महिलाओं को इस योजनांतर्गत ये Smart Phone उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस प्रकार प्रारंभिक चरण में लगभग 40 लाख लाभान्वितों को ये Smart Phone प्राप्त हो सकेंगे।

- ❖ प्रदेश में कुशल वित्तीय व बजटीय प्रबंधन के साथ-साथ कर प्रणाली के सरलीकरण हेतु Integrated Financial Management System (IFMS 3.0) तथा Integrated Tax Management System (ITMS) लागू करने के साथ ही, सरकारी खरीद प्रक्रिया हेतु नवीन राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम/नियम (RTPP Act/Rules) तथा वित्तीय लेखांकन व सार्वजनिक निर्माण संबंधी Integrated Rajasthan Financial Accounting Rules बनाए जाएंगे।

- ❖ राज्य सरकार द्वारा IFMS के माध्यम से प्रक्रियाओं का सरलीकरण करते हुए कार्मिकों एवं पेंशनर्स को भी अपने GPF खाते पर पूरा नियंत्रण, पेंशन स्वीकृति के लिए Service Book की बाध्यता समाप्त करना एवं Salary/Pension का Auto Payment जैसे नवाचार कर राहत दी गई है। इसके उपरांत भी वर्तमान में कार्मिकों को

रिटायरमेंट के समस्त पेंशन परिलाभ प्राप्त होने में महीनों लग जाते हैं। अब कार्मिकों को और अधिक राहत देने की दृष्टि से मई, 2023 से रिटायरमेंट के दिन ही समस्त पेंशन परिलाभों की स्वीकृति जारी कर दी जाएगी।

- राज्य सरकार ने राजकीय कार्मिकों को सेवानिवृत्ति उपरांत सुरक्षा उपलब्ध करवाने की दृष्टि से सभी के लिए OPS लागू करने का प्रावधान किया। प्रदेश में 80 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर्स को पेंशन राशि में वृद्धि का लाभ प्राप्त होता है। आयु बढ़ने के साथ ही अतिरिक्त वित्तीय सुरक्षा की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अब 75 वर्ष से अधिक (80 वर्ष की आयु तक) आयु के पेंशनर्स को पेंशन राशि में बेसिक पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त Allowance उपलब्ध करवाए जाएंगे।

- राज्य के कार्मिकों को उनके द्वारा 7वें वेतनमान में वेतन निर्धारण हेतु दिये गये विकल्प के कारण वेतन में हो रही हानि को देखते हुए इन नियमों में पुनः विकल्प दिया जाएगा। इससे उनके वेतन में वृद्धि हो सकेगी।

- कार्मिक अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए प्रतिमाह मिलने वाले वेतन पर निर्भर रहते हैं। आकस्मिक आवश्यकता होने पर भी कार्मिकों को वेतन लाभ मिल सके, इसके लिए अनुपातिक आधार पर माह के बीच में भी अग्रिम वेतन आहरण (Advance Salary Withdrawal) की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी।

- राजकीय कार्मिकों को खेलों के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने की दृष्टि से अंतरराष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में वृद्धि प्रदर्शन करने वाले कार्मिकों को Special Allowance/ Increment दिया जाएगा।

- कार्मिकों द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए स्वयं की दक्षता में वृद्धि सतत रूप से किया जाना अत्यावश्यक है। इस दृष्टि से प्रदेश के Apex Capacity Building Institute -हरिश्चन्द्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान (HCM-RIPA) के उन्नयन के साथ ही संस्थान के अंतर्गत Civil Services Officers Institute की स्थापना के लिए 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।

- राज्य के कार्मिकों की सुविधा के दृष्टिगत Rajasthan Civil Services Appellate Tribunal की स्थायी पीठ, जोधपुर में भी खोली जाएगी।

प्रशासनिक सुदृढीकरण

- प्रदेश में प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार एवं सुदृढीकरण हेतु प्रशासनिक इकाइयां/कार्यालय खोले व क्रमोन्नत किए जाएंगे।

- गत 4 वर्षों में प्रदेश की आधारभूत संरचना को सुदृढ कर, आमजन व जरूरतमंदों को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराते हुए तथा सामाजिक क्षेत्र में विकास के साथ-साथ आजीविका के संसाधन उपलब्ध करा, प्रदेश में खुशहाली लाकर राजस्थान को देश का मॉडल राज्य बनाने का प्रयास किया है। प्रदेश में संवेदनशील, जवाबदेही एवं पारदर्शी प्रशासन देना राज्य सरकार की प्रतिबद्धता है। सरकार द्वारा जनघोषणाओं एवं बजट घोषणाओं के माध्यम से एक के बाद एक लोक कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, ऐसी स्थिति में राज्य सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ ढाणी-ढाणी, मगरे-मगरे में बसे जरूरतमंद परिवारों तक भी पहुंचे, इसके लिए जिला स्तर पर पूर्ण संवेदनशीलता के साथ कार्य करना आवश्यक है।

राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य होने के कारण कई जिले ऐसे हैं, जहां जिला मुख्यालय की दूरस्थ कोने से दूरी 100 किलोमीटर से भी अधिक है और इस कारण आमजन को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके साथ ही कई जिलों की जनसंख्या भी अत्यधिक होने के कारण प्रशासन का हर परिवार



तक पहुंचना कठिन हो जाता है। जिला अपेक्षाकृत छोटा होने से प्रशासन प्रबंधन व कानून व्यवस्था पर निगरानी/नियंत्रण सहज व सुगम हो जाता है। देश के विभिन्न राज्य नए जिले बनाने में राजस्थान से आगे रहे हैं। वहां पर जिलों की संख्या दोगुनी-तीन गुनी हो गई है। हाल में भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान से छोटे राज्य पश्चिम बंगाल ने भी 7 नए जिलों की घोषणा की है।

इसी कारण प्रदेश से भी कई स्थानों से नए जिले बनाने की मांग प्राप्त हुई। इन प्रस्तावों के विस्तृत अध्ययन के लिए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था, जिसकी अंतरिम रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। इस विषय में प्राप्त समस्त प्रस्तावों व प्रदेश की वर्तमान प्रशासनिक इकाइयों की संरचना का विस्तृत अध्ययन एवं विवेचना के उपरांत अब, प्रदेश में नए जिले बनाए जाएंगे, जो इस प्रकार हैं :

1. अनूपगढ़	2. बालोतरा	3. व्यावर
4. डीग	5. डीडवाना-कुचामन	6. दूदू
7. गंगपुरसिटी	8. जयपुर उत्तर	9. जयपुर दक्षिण
10. जोधपुर पूर्व	11. जोधपुर पश्चिम	12. केकड़ी
13. कोटपूतली-बहरोड़	14. खैरथल	15. नीम का थाना
16. फलौदी	17. सलूंबर	18. सांचौर
19. शाहपुरा		

इस प्रकार 19 नए जिले बनाने के कारण प्रदेश में कुल 50 जिले हो जाएंगे। इन सभी का प्रदेश मुख्यालय से संपर्क संभागीय मुख्यालयों के माध्यम से होता है। अतः इस प्रबंध को सुदृढ करने की दृष्टि से प्रदेश में 3 नए संभाग - बांसवाड़ा, पाली एवं सीकर बनाए जाएंगे। इन नवीन प्रशासनिक इकाइयों (जिलों एवं संभागीय मुख्यालयों) को अविंलंब धरातल पर उतारने के लिए सुदृढ आधारभूत ढांचा एवं मानव संसाधन उपलब्ध कराने हेतु प्रथम चरण में 2 हजार करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा। ●

राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल का बदल गया स्वरूप

प्रश्न सूची में शामिल सभी प्रश्नों के जवाब पेश हो रहे हैं सदन में



विधायिका लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जनहित से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164 (2) के तहत राज्य का मंत्रिमंडल विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संसदीय प्रश्न विधायिका द्वारा कार्यपालिका के कृत्यों पर निरंतर निगरानी रखने का सबसे उत्तम साधन है। विधायकों द्वारा पूछे जाने वाले प्रश्नों के माध्यम से एक ओर जहां जनता की शिकायतों, समस्याओं और आकांक्षाओं का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर सरकार के क्रियाकलापों, कार्यक्रमों एवं विभिन्न मामलों में उसकी नीतियों तथा प्रशासन चलाने के ढंग की जानकारी होती रहती है।

प्रश्नों से प्रभावी नियंत्रण

प्रश्न राज्यकर्मियों पर प्रभावी नियंत्रण रखने में तो कारगर होते ही हैं, साथ ही कार्यपालिका का ध्यान इस ओर भी आकर्षित करते हैं कि उसकी नीतियों को किस प्रकार क्रियान्वित किया जा रहा है। प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण क्षेत्रों की ओर ध्यान आकर्षित कर कार्यपालिका की यथासंभव सहायता करते हैं।

प्रश्न का अर्थ विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा मंत्री से किसी विशिष्ट विषय पर स्पष्टीकरण की मांग है। प्रश्न पूछने का प्रमुख उद्देश्य किसी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करना है।

प्रश्नकाल महत्वपूर्ण

प्रश्नों के महत्व को दृष्टिगत रखकर ही सदन की कार्यसूची में प्रतिदिन प्रथम एक घंटे का समय अल्प सूचना प्रश्नों सहित तारांकित प्रश्नों के पूछने और उत्तर देने के लिए होता है। प्रश्न को पूछने और उसका उत्तर देने में साधारणतः पांच मिनट से

डॉ. लोकेश चन्द्र शर्मा

उप निदेशक (जनसंपर्क) राजस्थान विधानसभा, जयपुर

अधिक नहीं लगने चाहिए और यह प्रयास किया जाना चाहिए कि प्रत्येक दिन कम से कम बारह प्रश्नों पर विचार-विमर्श किया जाए, लेकिन विधानसभाओं में पांच से आठ प्रश्नों पर ही पूरे प्रश्न काल में चर्चा हो पाती है। पूरी प्रश्न सूची पर चर्चा नहीं होने से महत्वपूर्ण समस्याओं पर सदन में चर्चा नहीं होती है।

जानकारी प्राप्त करने का अधिकार

लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद के सदस्यों को महत्वपूर्ण, सार्वजनिक तथा जनहित के विषयों पर प्रश्न पूछकर सरकार से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। सदस्य तारांकित तथा अतारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्नकाल में प्रश्न का क्रम आने पर प्रश्नकर्ता सदस्य तथा अन्य सदस्य भी पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। प्रश्न पूछने वाले सदस्यों के कौशल और सजगता पर यह निर्भर करता है कि वे संबंधित मंत्री से अपने प्रश्न का उत्तर निकलवा लें अथवा सरकार को कटघरे में खड़ा कर दें। अत्यन्त ही महत्वपूर्ण प्रश्न अध्यक्ष अल्पसूचित प्रश्न के रूप में स्वीकार करते हैं।

विधानमंडल जनता के प्रति जवाबदेह

प्रतिदिन बैठक शुरू होते ही एक घंटे का समय प्रश्नकाल के लिए निर्धारित रहता है। सरकार विधानमंडलों के प्रति जवाबदेह होती है तथा

विधानमंडल जनता के प्रति जवाबदेह होते हैं। न्यायालय में जिस प्रकार गवाह से वकील जिरह करके सत्य उगलवाने की कोशिश करता है, उसी प्रकार से सदन में सदस्य मंत्री पर पूरक प्रश्नों की बौछार कर सत्य निकलवाने की कोशिश करते हैं। किसी भी सदन में प्रश्नकाल सर्वाधिक रोचक और जीवंत होता है। इसमें सदस्यों की भारी उपस्थिति रहती है, प्रेस दीर्घा और दर्शक दीर्घा भी खचाखच भरी रहती है।

राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल

राजस्थान विधानसभा में भी सदन के आरंभ में प्रतिदिन प्रश्नकाल होता है। यह प्रश्नकाल एक घंटे का होता है। विधानसभा का यह 60 मिनट का समय महत्वपूर्ण होता है। इस दौरान लगभग सभी विधायकगण, मंत्रिमंडल के सदस्य सदन में होते हैं और अधिकारी दीर्घा में अधिकारीगण भी मौजूद होते हैं।

पंद्रहवीं विधानसभा के प्रश्नकाल में नई पहल

पंद्रहवीं विधानसभा के अष्टम सत्र में सदन के प्रश्नकाल का माहौल बदला हुआ है। प्रश्नकाल के एक-एक पल पर महत्वपूर्ण चर्चा हो रही है। अनावश्यक पूरक प्रश्नों को रोका जा रहा है। प्रश्न के जवाब को मंत्रीगण के सदन में पढ़ने की परंपरा को समाप्त किया जा रहा है। विधायक तारांकित प्रश्नों के जवाब को सदन में पढ़ने की बजाय संबंधित मंत्रीगण से सीधे ही पूरक प्रश्न करके विभाग की जानकारी ले रहे हैं।

विधायकों के मददगार बने डॉ. जोशी

ये सभी बदलाव संभव हुए हैं विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी की सोच, उनकी पहल और सदन को संचालित करने की उनकी प्रभावी मॉनिटरिंग व्यवस्था से। डॉ. जोशी ने प्रश्नकाल में सार्थक चर्चा कराने और अनावश्यक बहस को रोकने की बेहतर व्यवस्था कर सदन का माहौल बदल दिया है। डॉ. जोशी आगे बढ़कर विधायकगण की भी मदद करते हैं। प्रश्नों को घुमा-फिरा कर पूछने की बजाय डॉ. जोशी सीधा सटिक विश्लेषण कर देते हैं। यही नहीं, संबंधित विभाग के मंत्रीगण के जवाब का भी वे सरलीकरण कर सदन को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। इससे अब सदन में प्रश्न सूची में शामिल सभी प्रश्नों के जवाब सदन में प्रस्तुत होने लगे हैं।

डॉ. सी.पी. जोशी का प्रभावी संचालन

विधानसभा में तारांकित प्रश्नों की सूची में शामिल प्रश्नों के जवाब सदन में

प्रत्यक्ष रूप से प्रस्तुत होते हैं। इस दौरान विधायकगण उन प्रश्नों से संबंधित पूरक प्रश्न भी पूछ सकते हैं। प्रश्नकाल के दौरान अनेक बार व्यवधान की स्थिति पैदा हो जाती है। विधायकगण के पूरक प्रश्न का जवाब भी मंत्रीगण स्पष्ट तौर पर नहीं दे पाने पर सदन में अवरोध आ जाता है। इस कार्य में अध्यक्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। उनकी व्यवस्था प्रधान होती है। डॉ. जोशी मंत्रीगण से जवाब दिलाने में इंटरवेंशन कर सदन का प्रभावी संचालन कर रहे हैं।

देरी से आने वाले विधायकगणों को भी मौका

राजस्थान विधानसभा में सदन संचालन की बेहतर व्यवस्था के लिए अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी की पहल से सदन में नई व्यवस्थाएं बन रही हैं जो भविष्य के लिए विधानसभा प्रक्रिया की सुदृढ़ परंपराएं बनेंगी। विधानसभा अध्यक्ष डॉ. जोशी सदन में देरी से आने वाले विधायकगण को भी प्रश्न पूछने का मौका दे रहे हैं।

अध्यक्ष पूछ रहे हैं प्रश्न

यही नहीं प्रश्नकाल में सदन में मौजूद नहीं होने वाले पक्ष और प्रतिपक्ष के विधायकों के प्रश्न भी अध्यक्ष स्वयं पूछ रहे हैं और उससे संबंधित पूरक प्रश्न करके भी अध्यक्ष ने सदन में नई व्यवस्था दे दी है। सदन के लिए यह महत्वपूर्ण व्यवस्था है। अब प्रश्न सूची में शामिल सभी प्रश्नों के जवाब सदन में प्रस्तुत होने लगे हैं।

प्रश्न सूची के सभी प्रश्नों पर चर्चा

राजस्थान विधानसभा के प्रश्नकाल में अब प्रश्न सूची में शामिल 18 से 20 प्रश्नों के जवाब सदन में प्रस्तुत हो रहे हैं। पंद्रहवीं राजस्थान विधानसभा का अष्टम सत्र प्रश्नकाल में प्रश्नों के जवाब दिलाने में अब तक की विधानसभाओं के सभी सत्रों में विशिष्ट बन गया है। राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव श्री महावीर प्रसाद शर्मा भी प्रश्नकाल की नई व्यवस्थाओं के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।

राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. सी.पी. जोशी की प्रश्नकाल में की गई नई पहल की चर्चा देशभर के विभिन्न राज्यों के विधानसभाओं में भी हो रही है। डॉ. जोशी की प्रश्नकाल की नई व्यवस्थाओं से प्रतिदिन प्रश्न सूची के सभी प्रश्नों के जवाब सदन में आने से विधानसभा में नया माहौल बना है। विधानसभा की वर्तमान की ये व्यवस्थाएं भविष्य में सुदृढ़ परंपराएं बन सकेंगी। ●



विधानसभा अध्यक्ष डॉ. सी. पी. जोशी के सदन संचालन की चर्चा देश की सभी राज्य विधानसभाओं में है।

साकार हुई डिजिटल राजस्थान की संकल्पना

- ▶ 12,500 से अधिक जॉब ऑफर दिए गए आईटी मेगा जॉब फेयर में
- ▶ 58,000 से अधिक लोग हुए विभिन्न आयोजनों में सम्मिलित



मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की 'डिजिटल राजस्थान' की संकल्पना को साकार रूप में प्रदर्शित करने वाले राजस्थान आईटी दिवस-2023 फेस्ट का आयोजन 19 से 21 मार्च, 2023 को हुआ। तीन दिन तक आयोजित हुए इस फेस्ट में मुख्यमंत्री शुरुआती दो दिन युवाओं के बीच रहे और उनका उत्साह बढ़ाया। श्री अशोक गहलोत आईटी के बजट में लगातार बढ़ोतरी करते रहे हैं तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से करोड़ों प्रदेशवासियों को जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित करने के अपने संकल्प के साथ राजस्थान को मॉडल स्टेट बना रहे हैं। इसी यात्रा की झलक दिखाने वाले राजस्थान आईटी दिवस-2023 फेस्ट में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। इस अवसर पर आईटी मेगा जॉब फेयर में 12,500 से अधिक जॉब ऑफर दिए गए। 58 हजार से अधिक लोग विभिन्न आयोजनों में शामिल हुए। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा आयोजित किए गए राजस्थान आईटी डे 2023 फेस्ट के दौरान मेगा आईटी जॉब फेयर, हेकार्थॉन, टेकरश, स्मार्ट विलेज, विभिन्न टॉक शो, फिल्म फेस्टिवल का प्रदर्शन एवं मनोरंजन कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

डॉ. आशीष खण्डेलवाल
सहायक निदेशक, जनसंपर्क

राज्य सरकार आमजन को संवेदनशील, पारदर्शी एवं जवाबदेह सुशासन देने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इसमें सूचना प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका है। पूर्व प्रधानमंत्री स्व. राजीव गांधी ने आईटी के माध्यम से देश को 21वीं सदी से जोड़ने का स्वप्न देखा था। आज राज्य सरकार द्वारा आईटी के बजट में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है तथा सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से करोड़ों प्रदेशवासियों को जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़कर लाभान्वित किया जा रहा है। राज्य सरकार की नीतियों से प्रदेश आज आईटी के क्षेत्र में अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। राज्य सरकार सभी योजनाओं को आईटी आधारित बनाने की संकल्पना को आगे बढ़ा रही है। आईटी दिवस पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों से देश के उज्वल भविष्य के लिए नई पीढ़ी तैयार हो रही है। आईटी के प्रयोग से राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन एवं अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सुनिश्चित की जा रही है।

मेगा आईटी जॉब फेयर में दिए 12,500 से अधिक जॉब लैटर

राजस्थान व कॉमर्स कॉलेज में दो दिन तक आयोजित हुए मेगा आईटी जॉब फेयर में लगभग 18,500 से अधिक अभ्यर्थियों ने भाग लिया। विभिन्न कंपनियों द्वारा युवाओं को उनके अनुभव और शैक्षणिक योग्यता के आधार पर हजारों अभ्यर्थियों का इंटरव्यू लिया गया और 12,500 से अधिक जॉब ऑफर प्रदान किए गए। गौरतलब है कि दिये गये जॉब में 36 लाख रुपये का अधिकतम वार्षिक पैकेज ऑफ शोर टेक्नोलेज द्वारा श्री पंकज कुमार को ऑफर किया गया। जॉब फेयर में 430 से अधिक कम्पनियों ने हिस्सा लिया।

हेकाथॉन में 60 से अधिक देशों के 1 लाख प्रतिभागी

इस अवसर पर आयोजित हुए हेकाथॉन में 60 से अधिक देशों के 1 लाख प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने हेकाथॉन में भाग लेने वाले प्रतिभागियों से संवाद कर उन्हें प्रोत्साहित किया। उन्होंने प्रतिभागियों के प्रोजेक्ट और भविष्य की संभावनाओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि हेकाथॉन के नवाचार गुड गवर्नेंस में मददगार साबित होंगे। छत्तीस घंटे के नॉन-स्टॉप कोडिंग मैराथन हेकाथॉन के माध्यम से प्रतिभाशाली कोडर्स, डेवलपर्स और डिजाइनरों द्वारा अभिनव समाधान विकसित करने, रोमांचक पुरस्कारों के लिए प्रतिस्पर्धा करने एवं 60 लाख रुपये की परियोजनाओं पर राजस्थान सरकार के साथ काम करने के लिये प्रतिस्पर्धा की गई। प्रथम पुरस्कार के रूप में गाजियाबाद से विशाल मिश्रा, उज्वल कसेरा, आकाश कुमार यादव, तनिष्क श्रीवास्तव, श्रीशुंद लाहिरी की टीम कृषक को 25 लाख रुपए का वर्क ऑर्डर दिया गया। प्रथम पुरस्कार के रूप में 25 लाख रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 20 लाख रुपए एवं तृतीय पुरस्कार के रूप में 15 लाख रुपए के कार्यदिश राजस्थान सरकार द्वारा दिये जायेंगे। इस प्रतिस्पर्धा में 5,500 पंजीकृत प्रतिभागियों में से 3,000 प्रतिभागियों ने ऑन प्रिमाइसिस हेकाथॉन में भाग लिया जिनमें से महिला प्रतिभागियों की भागेदारी लगभग 35 प्रतिशत रही। इसके अलावा एक आनलाइन हेकाथॉन का भी आयोजन किया गया। ऑनलाइन हेकाथॉन के विजेता इश्विन खत्री, चौतन्य रॉय, शनील खत्री, मनीष शंभू और मोहित कड़वे की टीम रही।

राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब का शिलान्यास

इस दौरान मुख्यमंत्री ने 200 करोड़ रुपये की लागत से तैयार होने वाले राजीव गांधी नॉलेज सर्विस एंड इनोवेशन हब, जोधपुर का वीसी के माध्यम से शिलान्यास किया। यह संस्थान स्टार्टअप्स और सर्विस प्रोफेशनल्स को विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ-साथ नवोन्मेषी विचारों को धरातल पर उतारने के लिए आधारभूत ढांचा प्रदान करेगा। यह संस्थान प्लग एंड प्ले मॉडल पर आधारित होगा। यहां डब्ल्यू-हब के नाम से महिला इनोवेटर्स के लिए अलग स्पेस उपलब्ध करवाया जाएगा। इससे राज्य में स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन मिलेगा तथा प्रदेश में आर्थिक विकास के नए आयाम स्थापित होंगे।

मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ

श्री गहलोत ने इस अवसर पर मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजना का शुभारंभ किया। इस योजना के तहत राज्य सरकार आवागमन में असमर्थ लाभार्थियों को चिन्हित कर उनसे संपर्क करेगी। चिन्हित व्यक्तियों के पास सेवा प्रदायक को

भेजकर सरकारी सेवाओं का लाभ दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आश्रित सेवा के प्रथम चरण में दिव्यांगजन, वृद्धजन, एकल नारी, विधवा महिलाएं, पालनहार को मुख्यमंत्री आश्रित सेवा योजनाओं का लाभ प्रदान किया जाएगा। इन लोगों को जनकल्याणकारी योजनाओं से घर बैठे जोड़ा जा सकेगा।

जन आधार ई-वॉलेट लॉन्च

श्री गहलोत ने इस अवसर पर जन आधार ई-वॉलेट लॉन्च किया। इसके माध्यम से राज्य सरकार द्वारा लाभार्थियों को दिए जा रहे नकद राशि तथा गैर-नकद राशि के वाउचर्स मिल सकेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राजस्थान डिजिटल यात्रा रिपोर्ट का विमोचन भी किया।

उत्कृष्ट कार्यों का सम्मान

इस दौरान आईटी नवाचारों के माध्यम से विभिन्न प्रशासनिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले राज्य के अधिकारियों को मुख्यमंत्री द्वारा ई-गवर्नेंस राजस्थान अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। श्रीगंगानगर कलक्टर श्रीमती रुक्मिणी रियार सिहाग, चित्तौड़गढ़ कलक्टर श्री अरविंद कुमार पोसवाल, बीकानेर पुलिस अधीक्षक श्रीमती तेजस्विनी गौतम, आरजीएचएस परियोजना निदेशक श्रीमती शिप्रा विक्रम तथा जयपुर जिला परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री जसमीत सिंह संधू को ए-वन एवं ए-टू श्रेणियों में ई-गवर्नेंस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। साथ ही, 20 अधिकारियों-कर्मचारियों को बी-वन एवं बी-टू श्रेणियों में ई-गवर्नेंस अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। श्री गहलोत ने निजी क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी में उत्कृष्ट कार्य करने वाले स्टार्ट-अप्स एवं उद्यमियों को राजीव गांधी इनोवेशन चैलेंज सम्मान प्रदान किया। इन पुरस्कार विजेताओं को 6.10 करोड़ रुपए की पुरस्कार राशि दी गई। इनमें अजेयता शाह, निखिल बाहेती, शिवराम चौधरी, अनुज आहूजा एवं टीकमचंद जैन को प्रथम पुरस्कार मिला। पूरनसिंह राजपूत को द्वितीय, हिमीश अग्रवाल, ध्रुव दत्ता, प्राची गौड़, सारिका गुप्ता एवं अयाज को तृतीय पुरस्कार मिला। साथ ही, मुख्यमंत्री ने जॉब फेयर में उत्कृष्ट पैकेज प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को ऑफर लैटर प्रदान किए। इनमें राकेश सागर, टी पवन कुमार, सुमित पहाड़ी, निखिल एवं जेठाराम भाटी ने विभिन्न कंपनियों से क्रमशः 33 लाख, 30 लाख, 18 लाख, 9 लाख एवं 5 लाख रुपए के वार्षिक पैकेज प्राप्त किए।

राजस्थान आईटी डे कार्निवल एंड रन

इससे पूर्व फेस्ट के पहले दिन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने राजस्थान आईटी डे के अवसर पर आयोजित कार्निवल एंड रन को पत्तैंग ऑफ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में राजस्थान अग्रणी राज्य बनकर उभरा है। भविष्य में प्रशासनिक कार्यों में आईटी का अहम योगदान होगा। उन्होंने कहा कि 'आईटी डे' जैसे आयोजनों से युवाओं को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नई तकनीकों के बारे में जानने का अवसर मिलता है। राज्य सरकार सूचना प्रौद्योगिकी से आमजन को सुशासन देने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। इस दौरान उन्होंने आईटी डे में भाग ले रहे प्रतिभागियों से मिलकर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने कहा कि आईटी दिवस के आयोजन से प्रौद्योगिकी के लिए सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है। युवाओं में इस आयोजन को लेकर विशेष उत्साह है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ई-गवर्नेंस की दिशा में निरंतर आगे



बढ़ रही है। इसी क्रम में सभी जिलों में विभागीय अधिकारियों को लैपटॉप-टेबलेट दिए जाने का प्रावधान किया गया है।

स्मार्ट विलेज का अवलोकन

राजस्थान आईटी डे 2023 फेस्ट की कड़ी में जवाहर कला केंद्र में स्मार्ट विलेज स्थापित किया गया। मुख्यमंत्री ने इस दौरान जवाहर कला केंद्र में बनाए गए 'स्मार्ट विलेज' का अवलोकन किया। उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र की आदर्श रूपरेखा, कृषि यंत्र, स्प्रिंकलर सिस्टम, जीआईएस, वाटरशेड, डिजिटल ट्रांजेक्शन, ई-मित्र, ई-मित्र प्लस मशीन सहित स्मार्ट विलेज की अवधारणा को पूरा करने की तकनीक एवं अन्य सुविधाओं वाली स्टॉल्स का अवलोकन किया। उन्होंने स्मार्ट विलेज में संचालित इंदिरा रसोई में जाकर लाभार्थियों से संवाद किया। लाभार्थियों ने इंदिरा रसोई में मिल रहे भोजन की गुणवत्ता की सराहना की। श्री गहलोत ने कस्टम हायरिंग केन्द्रों द्वारा किसानों को दिए जाने वाले ड्रोन द्वारा कीटनाशक छिड़काव एवं जैविक खाद उत्पादन प्रक्रिया के डेमो तथा सेनेटरी पैड बनाने वाले स्टार्ट-अप के स्टॉल का भी अवलोकन किया।



पैनल चर्चा एवं सेशन

फेस्ट के दौरान विभिन्न पैनल चर्चा एवं टॉक शो का आयोजन हुआ। महिला शक्ति के विषय पर एक पैनल चर्चा हुई जिसमें प्रबुद्ध महिला अतिथिगण जैसे मुग्धा कालरा (ब्रॉडकास्ट पत्रकार), अजैता शाह (संस्थापक, फ्रंटियर मार्केट्स), पूजा बजाज (सोशियो-सिविक चेंजमेकर), खुशबू बाकलीवाल (चेयरपर्सन, जीतो लेडीज) ने अपने विचार प्रस्तुत किये। स्टार्ट-अप गपशप में अनुभव दुबे (संस्थापक चाय सुट्टा बार), संजोत कीर (संस्थापक, योर फूड लेब) एवं नीयू (यूट्यूबर) द्वारा स्टार्ट-अप विषय पर चर्चा की गई। मशहूर लेखक चेतन भगत के साथ भी एक टॉक सेशन का आयोजन किया गया। आई-स्टार्ट करियर हैकथॉन में अनुभव दुबे (संस्थापक चाय सुट्टा बार), पूजा बजाज (सोशियो-सिविक चेंजमेकर), सुरेश कुमार (इसरो वैज्ञानिक), डॉ अंशुल ढींगरा एवं दिलराज सिंह रावत (यूट्यूबर) ने अपने विचार एवं अनुभव साझा किये।

आई स्टार्ट यूथ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में विभिन्न प्रेरणादायी फिल्मों जैसे सिंधुस्तान, एन इंजिनियर्ड ड्रीम एवं किलर का प्रदर्शन किया गया।

इसी फेस्ट के दौरान आर-कैट राजस्थान में तकनीकी परितंत्र को मजबूत करने के लिए राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय (आरटीयू), मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय (एमएलएसयू), मणिपाल विश्वविद्यालय जयपुर (एमयूजे) और विवेकानंद ग्लोबल विश्वविद्यालय (वीजीयू) के साथ शैक्षिक एमओयू एवं एम्पल, माइक्रोसॉफ्ट और ईसी काउंसिल के साथ औद्योगिक एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये। इन एमओयू का उद्देश्य छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, क्लाउड कंप्यूटिंग और मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाले उन्नत प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रमों तक पहुंच प्रदान करना है।

तीन दिनों तक चले आईटी डे फेस्ट में सभी वर्ग के नागरिकों खासतौर पर युवा वर्ग की अभूतपूर्व भागीदारी रही। इस फेस्ट में आगन्तुकों की संख्या 58 हजार से भी अधिक रही। ●

फोटो फीचर



वासंती हवा में खिली
स्मृष्टि स्यारी



छाया : पिकी फलवारीया, सविता चौहान

वसंत की कूची फिरी कानन में

भारत की संस्कृति की तरह ही यहां ऋतुओं में भी विविधता है। यहां रहने वाले लोगों को छह ऋतुओं वर्षा, ग्रीष्म, शरद, हेमंत, शिशिर और वसंत का सुख मिलता है। वसंत को ऋतुराज की उपाधि दी गई है क्योंकि इस ऋतु में धरती की उर्वरा शक्ति अन्य ऋतुओं की अपेक्षा बढ़ जाती है। वसंत ऋतु का वर्णन भगवद्गीता में मिलता है, जहां भगवान कृष्ण कहते हैं कि ऋतुओं में मैं वसंत हूं। श्रीकृष्ण सारे देवताओं और परम शक्तियों में सबसे ऊपर हैं, इसी प्रकार वसंत ऋतु भी सभी ऋतुओं में श्रेष्ठ है।

फाल्गुन माह में जब शिशिर ऋतु का अंत होता है तो शीत के प्रकोप से मुक्ति मिलती है, इस वक्त सर्दी का ह्रास होना शुरू हो जाता है। जिस सर्दी के कारण वृक्ष और पुष्प मुरझा गए होते हैं, उस सर्दी की विदाई के साथ ही वसंत दरवाजे पर दस्तक देता है। वसंत अपने आगमन की सूचना पल्लवित पुष्पों और सुहानी सुबहों के हाथों भिजवाता है। वृक्षों पर नए पत्ते आते हैं और सरसों के खेत पीली चूनर ओढ़ लेते हैं। दक्षिण पवन की शीतलता सुख का अनुभव देती है। तापमान इतना सुहावना कि न सर्दी होती है और न गर्मी। प्रकृति अपने सबसे सुंदरतम रूप में वसंत के समय ही दिखाई देती है। इस ऋतु में पलाश के फूल, हरियाली से ढकी धरती, रंग-बिरंगे सुगंधित पुष्प, कोयल की कूक, आम की खुशबू, जल से भरे सरोवर सकारात्मक ऊर्जा देते हैं। वसंत कवियों का भी सबसे पसंदीदा मौसम है। हिंदी काव्य के नामचीन कवियों ने अपनी कलम से वसंत के सौंदर्य को उकेरा है। भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखते हैं-

सखि आयो वसंत रितून को कंत, चहूँ दिसि फूलि रही सरसों।

बर शीतल मंद सुगंध समीर सतावन हार भयो गर सों।।

अब सुंदर सांवरो नंद किसोर कहै "हरिचंद" गयो घर सों।

परसों को बिताय दियो बरसों तरसों कब पांय पिया परसों।।

रामधारी सिंह दिनकर वसंत ऋतु के प्रभाव से इतने उत्साहित हो जाते हैं कि कविता लिखने के लिए वे प्रेरणा मांगते हैं। दिनकर लिखते हैं-

प्रातः जगाता शिशु-वसन्त को नव गुलाब दे-दे ताली।

तितली बनी देव की कविता वन-वन उड़ती मतवाली।

आलोक आनंद
सहायक निदेशक, जनसम्पर्क

सुंदरता को जगी देखकर,
जी करता मैं भी कुछ गाऊं,
मैं भी आज प्रकृति-पूजन में,
निज कविता के दीप जलाऊं।

वसंत अखिल प्रकृति सौंदर्य से परिपूरित है। जैसे रजनी के अवसान पर उषा का आगमन होता है, वैसे ही शीत के नाश से वसंत का सूर्य उदित होता है। वसंत की सुबह बिखरी हुई ओस ऐसी प्रतीत होती है मानो हरे मखमल पर थवल मोती जड़े हों। वसंत, उत्सव और उत्साह की ऋतु है। भारत भूमि का रंगीन उत्सव होली इस ऋतु में मनाया जाता है। वसंत, होली और राधा-कृष्ण को लेकर सूरदास ने बहुत सुंदर भजनों की रचना की है, वे कहते हैं-

विविध सुमन बन फूले डार। उन्मत्त मधुकर भ्रमत अपार ॥
नव पल्लव बन शोभा एक । बिहरत हरि संग सखी अनेक ॥
कुहू कुहू कोकिला सुनाई । सुनि सुनि नारि परम हरपाई ॥
बार बार सो हरिहिं सुनावति । ऋतु बसंत आयी समुझावति ॥
फागु-चरित-रस साध हमारै । खेलहिं सब मिलि संग तुम्हारै ॥
सुनि सुनि सूर स्याम मुसुकाने । ऋतु वसंत आयी हरपाने ॥





वसंत के दौरान भारत में रंगपंचमी मनाई जाती है। वसंत और रंगपंचमी का गहरा संबंध है। प्राचीन समय में वसंतोत्सव मनाया जाता था जो कई दिन तक चलता था। होली को वसंतोत्सव का पहला दिन और रंगपंचमी को इसका अंतिम दिन माना जाता है। जयपुर स्थित भगवान गोविन्ददेव जी के मंदिर में होली के दौरान फूलों की होली खेली जाती है। गोविन्ददेव जी मंदिर में पुष्प फाग से इस उत्सव को मनाया जाता है। इस दौरान राधाकृष्ण की लीलाओं का मनोहर चित्रण किया जाता है। वसंत के दौरान वसंत पंचमी का त्योहार भी मनाया जाता है। इस उत्सव को श्रीपंचमी और ऋषिपंचमी भी कहा जाता है। इस दिन विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। यह दिन विद्यार्थियों के लिए विशेष होता है।

वसंत का वर्णन हमें कालिदास के मुख से भी सुनने को मिलता है। "ऋतुसंहार" में कालिदास ने वसंत का मनोहारी वर्णन किया है। कालीदास कहते हैं-

**दुमा सपुष्पाः सलिलं स्पन्दम,
स्त्रीय सकामाः पवनः सुगंधीः।
सुखाः प्रदोषाः दिवसाश्च रम्याः,
सर्वं प्रिये चारुतरं वसंते।।**

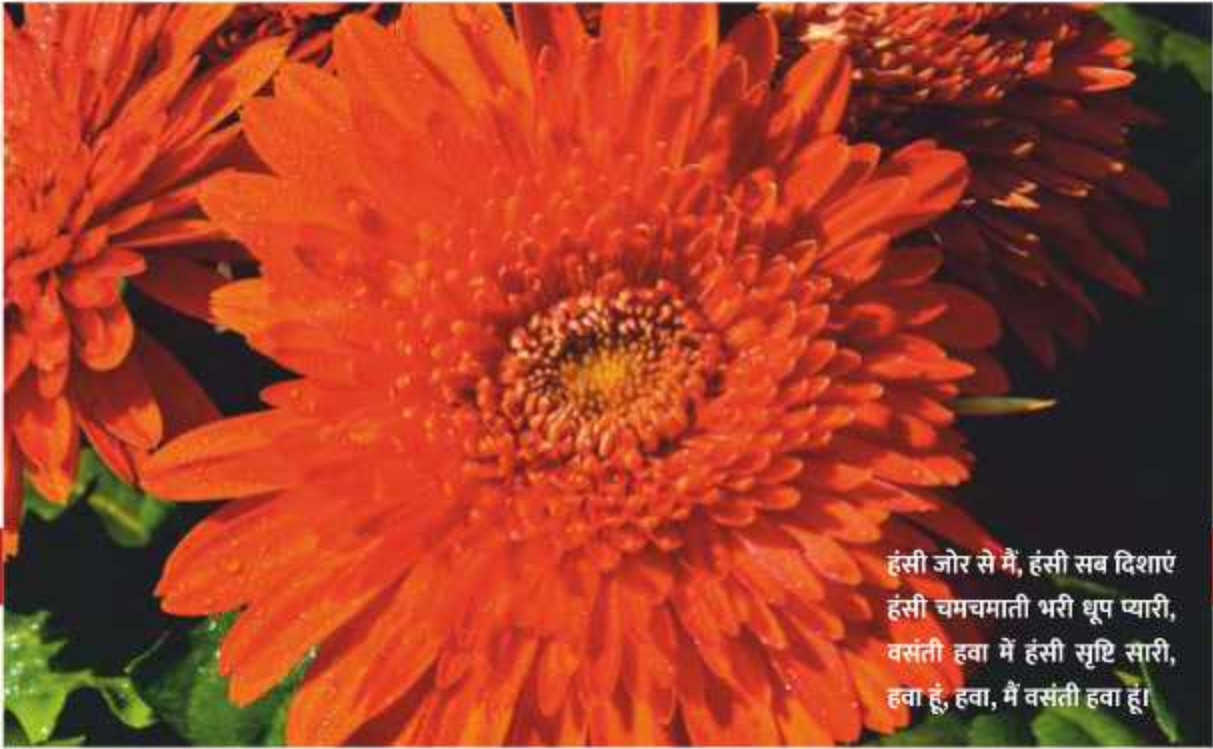
वसंत सुखकर और प्रीतिकर है। यह उत्सव मनाने की ऋतु है। वसंत का ही असर है कि दुनिया विविध रंगों में रंगकर फाग के गीत गाती है। सूर्यकांत त्रिपाठी "निराला" की इस कविता के बिना वसंत का जिक्र अधूरा रहेगा-

**सखि, वसंत आया
रंग गई पग-पग धन्य धरा
हंसी के तार के होते हैं ये बहार के दिन
अलि की गूंज चली दुम कुंजों
आज प्रथम गाई पिक पंचम
फूटे हैं आमों में वीर
वरद हुई शारदा जी हमारी
कूची तुम्हारी फिरी कानन में**



उल्लास बांटता ऋतुराज

वसंत में छिपा है संभावनाओं का उद्घोष और सृजन के आयोजन-प्रयोजन



छाया: सविता चौहान

हंसी जोर से मैं, हंसी सब दिशाएं
हंसी चमचमाती भरी धूप प्यारी,
वसंती हवा में हंसी सृष्टि सारी,
हवा हूं, हवा, मैं वसंती हवा हूं।

के दारनाथ अग्रवाल की उपरोक्त कविता में वासंती बयार की उमंग पूरे उन्माद से ध्वनित होती है। वह अनोखी है, बावली है और जिधर चाहती है, उधर घूमती है:

नदी, रेत, निर्जन, हरे खेत, पोखर, झुलाती चली मैं,
झुमाती चली मैं, हवा मैं हवा हूं,
वसंती हवा हूं।

वसंत ऋतु ऐसी ही है, जिसमें छिपा है संभावनाओं का उद्घोष और सृजन के आयोजन-प्रयोजन। इसी की वजह से हवा में गमक है, पेड़ नए पत्ते पहन रहे हैं, वसंत के रंग चारों दिशाओं में घूम रहे हैं। इन रंगों में जीवन का उत्सव भी है, तो सपनों का राग भी। तभी तो महाकवि कालिदास कहते हैं:

विनोद भारद्वाज
वरिष्ठ पत्रकार

“आम की मंजरी ही जिसका बाण है, पलाश का सुंदर पुष्प जिसका धनुष है, भंवरो की पत्तियां जिसके धनुष की प्रत्यंचा है। कलंक विहीन श्वेत चंद्रमा जिसका छत्र है, मलयगिरि से आया पवन जिसका मतवाला हाथी है, शरीर रहित होकर भी, अनंग-विदेह होकर भी, जिसने सम्पूर्ण विश्व को अपने वश में कर लिया है, ऐसा देव अपने सखा वसंत के साथ आप सबका कल्याण करे।”

इस बार शेखावटी के जिस इलाके में वसंत का स्वागत करने और सुबह इसकी गुनगुनी धूप का आनंद लेने का अवसर मिला है, वहां दूर-दूर तक धरती पर फैली उदासी के बीच भी धरती पर चंदोबे सरीखी सरसों की पीली और हरियाली



छाया: सविता चौहान

रंगत किसी उत्सव की तरह दिखलाई दे रही थी। खेजड़ी के छंगे हुए वृक्ष अपनी नग्न टहनियों के कारण चित्रलिखित पिंजर से लग रहे थे।

ये वृक्ष अलंकार विहीन अवश्य हैं, लेकिन मानव आकृतियों का अद्भुत संसार रचते, मरुभूमि के पशु-पक्षियों के लिए अन्नपूर्णा के वरदान से कम नहीं हैं।

यह सच है कि वसंत में भी मरु का रंग उतना हरा नहीं होता, जो मन के भीतर तक हरापन ले आए, मगर वसंत की उस हवा का क्या कीजे, जो बेरोक-टोक कहीं भी चली आती है और यहां के रहन-सहन में इतने विविध रंग घोल देती है, जो दुर्लभ ही हैं।

रघुवीर सहाय कहते हैं, “वही आदर्श मौसम और मन में कुछ टूटता सा, अनुभव से जानता हूँ कि यह वसंत है।”

अनुभव से वसंत का जानना एक बात है, लेकिन जिनके खिलने से ही वसंत की आहट आ जाती है, ऐसे पलाश की दग्ध लालिमा जब प्रस्फुटित होती है, तो ईर्ष्या होती है।

शायद इस ऋतु की प्रकृति ही है कि इसके साथ बहुत कुछ नया घटित होता है। कभी-कभी लगता है कि वसंत भागता-भागता चलता है, समय व काल की तरह हर बरस उल्लास बांटता। तभी तो आश्चर्य होता है कि इस मौसम में अपने आपमें सिमटी लताओं को क्या हो जाता है? इन्हें पल्लवित होने का संदेश कहां से मिलता है? सृजन का यह उत्सव यहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि चारों ओर फैला होता है। लगता है कि इस ऋतु में लोकवत्सल प्रकृति सभी को कुछ न कुछ बांट रही होती है। शायद इसीलिए हर मन में यह अपेक्षा जागती है कि उमंग और उल्लास से भरे वसंत उत्सव का हिस्सा बनें और अपने भीतर नए रंगों की ऊर्जा भर लें।

ध्यान से देखें तो वसंत अपने आप में जाग्रत है, समृद्ध और भरा-पूरा पूरा है। उसके पास कर्म भी उत्सव के रूप में मौजूद है। खेतों में धान पक गए हैं। सुनहरी बालियों से लदे पौधे अब खेतों का मोह छोड़ने को तैयार हैं। खेतों में हरियाली सरसों

पर पीताभ चादर बिछ गई है। ऐसा वसंत यदि कवि को प्रेरणा देता है तो कृषक को भी कम प्रिय नहीं होता है।

वसंत का आना हमारे जीवन में निष्प्रयोजन नहीं है। इसमें नवजीवन की प्रेरणाएं हैं। नव-सृजन का उद्दास है। यह ऋतु परिवर्तन मानव के अंतरमन को समृद्ध बनाने के लिए है।

पूर्णिमा की रात्रि है, चंद्रमा अमृत रस बरसा रहा है। तारों से भरा आकाश नदियों के जल पर प्रतिबिंबित हो रहा है। आम्रवन में कहीं कोयल बोल रही है तो फूलों पर भंवरो की गुंजन सुनाई पड़ रही है।

इस प्रकार के वर्णन हिंदी क्षेत्र की अनेक आंचलिक भाषाओं में आते हैं, परंतु संस्कृत साहित्य में वसंत की उपस्थिति न केवल असाधारण रूप से विद्यमान है, हम इसे काव्य परंपरा का एक विशेष हिस्सा मान सकते हैं।

कालिदास के लिए आम्रमंजरी वसंत का प्रतीक है और वसंत मंगल का प्रतीक... वे कहते हैं कि लता चाहे अशोक की हो, नवज्योत्सना की हो या मालती की, वह जब तक आम पर नहीं चढ़ती तब तक व्यर्थ है।

वह अपनी इस प्रिय ऋतु को बड़े आत्मविश्वास के साथ सर्वप्रिय कह देते हैं...
“सर्वप्रिय चारुतरं वसंते”

यह सर्वप्रिय ऋतु आ गई है। अग्रभाग में कुछ-कुछ लाल और अन्यत्र हरित पांडुर वर्णी आम्रमंजरी देव का बाण बनने को तैयार है। लाल-लाल किसलय इस बाण का पुच्छ है और इस पर बैठे भंवरे मानो देव के हस्ताक्षर।

कालिदास नहीं चाहते कि यह ऋतु यूँ ही बीत जाए। बुलबुले जैसा क्षणिक, रघुहीन और एकाकी जीवन जीकर समाप्त हो जाए। इसीलिए वह प्रार्थना कर रहे हैं:

‘हे चारुवसंत आओ आकर अपने अभिन्न देव के साथ ऋतु को सार्थक करो। यह सत्य मन और जीवन से कभी दूर न हो।’

वसंत को फूलों की ऋतु भी कहा गया है। मेघदूत में सौंदर्य प्रसाधन के रूप में



वासंती परंपराएं

वासंती परंपराएं आह्वान कर रही हैं सरस्वती का... कौन है यह सरस्वती? जीवन को सींचने वाला जल या जीवन को महकाने वाला ज्ञान?

सामवेद कहता है, “सप्त मातृ शक्तियों में से एक है जल। प्राणि मात्र के अस्तित्व की अनिवार्यता, जो गतिशील है, प्रवाहमान है। जल कहता है रुको मत, बहो। जहां रुके, वहीं सड़े। इसलिए चलते रहो।”

शायद इसी जीवनदायिनी निधि को मनुष्य ने मां कहकर पुकारा होगा। सरसधारा सुरसती या सरस्वती इस परंपरा की पहली कड़ी है।

आम्रमंजरी सरस्वती का पूजन करते हुए कितनी मुग्ध है :

सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने,

विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते...

वसंत पंचमी को ही कहते हैं श्री पंचमी। इसी दिन फाग के राग की शुरुआत भी होती है। फागुन का अर्थ ही है मधुमास। वह ऋतु जिसमें हर ओर माधुर्य ही माधुर्य हो। सौंदर्य ही सौंदर्य हो। वृक्ष नए पत्तों से सज गए हों। कलियां चटक रही हों, कोयल गा रही हो, हवा बह रही हो।

सरस्वती पूजन वसंत की शुचिता का प्रतीक है और लोकमन के आह्लाद से मुखरित वसंत की महक और फाल्गुनी बहक के स्वर इसका लालित्य हैं। होरी, फाग, धमार और रसिया में घुली वसंत की मिठास को कैसे आंका जा सकता है!

होली वसंत के उल्लास का साक्ष्य है। प्रतीक है मानव मन की निर्मल ऊर्जा का, अन्याय के दमन का, मन के मैल और बासीपन से मुक्ति की कामना का।

नए अनाज का स्वागत करता असम का पर्व बीहू और तमिलनाडु का पोंगल। आसमान को बधाई देती रंगीन पतंगों का उत्सव... मानों सरहदों के आर-पार उड़ रही हों मनुष्य की कामनाएं।

इतिहास में भी वसंत के उल्लास की परंपराएं मिलती हैं। मेसापोटामिया की पुरातन सभ्यता में वसंत से जुड़े पर्व अकितु का उल्लेख मिलता है।

ईरान में वसंत का पहला दिन 'नोरूज' के नाम से मनाया जाता है। नोरूज यानी नया दिन।

वसंत के साथ इंग्लैंड में बिखरता है मेडे, ईस्टर और गुड फ्राइडे का आनंद और चीन मनाता है अपना नववर्ष।

फूलों का विशेष वर्णन मिलता है। कालिदास के नायक-नायिकाएं बिना पुष्प शृंगार अधूरे हैं। मेघदूत में अलकानगरी की स्त्रियों के हाथ में कमल हैं, कानों में शिरीष पुष्प, बालों में नीप या कदंब। उनका शृंगार अनंत है।

बाणभट्ट की 'कादंबरी' और 'हर्षचरित्र' भी बिना फूलों के अधूरे हैं। कहते हैं वसंत उतना वसंत नहीं, जितना फूलों में है। सौंदर्य, सुगंध और शुचिता, फूल इन तीनों ही रूपों में हमसे जुड़े हैं।

मीलों में बिखरे गुलाब, बेला, डहलिया, गैदा, रातरानी, सूरजमुखी, पारिजात... और वासंती आमंत्रण सी बिछी हुई सरसों... इन सबके बीच यहां-वहां घूमते हुए मोर... झूमते हुए ठीक वैसे ही पंख... नीले, सुनहरे, चमकदार, कोमल... वासंती राग में खोया-खोया कालिंदी का किनारा।

गौर से महसूस करें तो वसंत जीवन के दरवाजे पर किसी दरवेश के सूफी नृत्य की तरह है। मात्र मौसम का बदलना भर नहीं है वसंत, यह तो मन का मौसम है, जो समय की पाबंदियों से परे चंचल हवा के महकते हुए झोंकों की तरह आता है।

राग वसंत। खुशी और उल्लास का राग। वह देखो! मालकौंस की ठंडी रागिनी चीरकर खिलने लगा धरती का रंग, तन पर उतरने लगी फागुनी धूप। मनमोर पीले जादू से महकने लगा। एक तितली लपेट लाई उत्सवों का आसमान अपने रंगीन परो में। धरती की नयनकोर में कांपता हुआ मधुमय क्षण बीत न जाए...

शिशिर की ठंडी रातों के बाद यह कौन आया है वासंती हवा की गंध लिए? कौन है जो लिख रहा है सुगंधों का वैभव?

आखिर कौन है वह, जो सिखा रहा है मधुकरों को गुनगुनाना?

कौन है जो भर रहा है हर दिशा में मधु? क्या यह तुम हो?

हां, तुम ही हो वसंत!

पतझड़ था झाड़ खड़े थे, सूखे से फुलवारी में

किसलय दल कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में



बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है
आंधी चलती है तो दिन-रात बदल देती है।
जब-जब गरजती है नारी शक्ति दुनिया में
तब-तब इतिहास बदल देती है।

महिलाएं किसी भी समाज के विकास एवं तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उनके बिना विकसित तथा समृद्ध समाज की कल्पना भी नहीं की जा सकती। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का मानना था, 'अगर आप एक पुरुष को शिक्षित कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक पुरुष को शिक्षित कर रहे हैं, पर अगर आप एक महिला को शिक्षित कर रहे हैं तो आप आने वाली पूरी पीढ़ी को शिक्षित कर रहे हैं।' इतिहास में अहिल्याबाई होल्कर, मदर टेरेसा, इला भट्ट, महादेवी वर्मा, राजकुमारी अमृत कौर, अरुणा आसफ अली, सुचेता कृपलानी और कस्तूरबा गांधी, इंदिरा गांधी से लेकर कल्पना चावला, सानिया मिर्जा, सुष्मिता सेन, ऐश्वर्या राय, मैरी कॉम, मीराबाई चानू और अवनि लेखरा तक, जब-जब भी मौका मिला, भारतीय महिलाओं ने भारत का परचम हर क्षेत्र में शान से लहराया है।

महिलाएं परिवार बनाती हैं, परिवार समाज बनाता है और समाज ही देश बनाता है। इसका सीधा अर्थ यही है कि महिला का योगदान हर क्षेत्र में है। महिला की क्षमता को नजरअंदाज करके समाज की कल्पना करना व्यर्थ है। शिक्षा और महिला सशक्तीकरण के बिना परिवार, समाज और देश का विकास नहीं हो सकता। अपनी सहनशीलता, धैर्य और जीवट के दम पर नारी हर मुसीबत पर भारी है, बस जरूरत है तो उसके सपनों को आजादी देने की। भारत की महिलाओं ने तमाम बंधनों के बावजूद अपने प्रयासों से न सिर्फ स्थापित मान्यताओं का विरोध किया है, बल्कि अपने लिए एक नया रास्ता भी बनाया है।

राजस्थान में भी आधी आबादी के उन्नयन एवं खुशहाली के लिए महिला सशक्तीकरण के रूप में राज्य सरकार निरंतर खुशहाल, स्वस्थ व आत्मनिर्भर बनाने के लिए कृतसंकल्प है। इसी का परिणाम है कि आज महिलाएं कई ऐसे क्षेत्रों में अपना स्थान बना रही हैं, जो कभी केवल पुरुषों के लिए आरक्षित माने जाते थे। इतिहास में झांके तो कुछ महिलाओं ने तो ऐसे क्षेत्रों में मुकाम बनाया और अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनीं।

जिनकी जिद ने बदली नारी की दुनिया

चंद्रशेखर पारीक, सहायक जनसंपर्क अधिकारी
अंजली सिंह

आनंदीबाई गोपालराव जोशी : आनंदीबाई गोपालराव जोशी वर्ष 1887 में पहली भारतीय महिला चिकित्सक बनीं। वह पहली भारतीय महिला थीं, जिन्हें पश्चिमी चिकित्सा में प्रशिक्षित किया गया था। साथ ही, संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा करने वाली भी वे पहली भारतीय महिला थीं।

आरती साहा : आरती साहा वर्ष 1959 में इंग्लिश चैनल में तैरने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला बनीं। वे 1960 में पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली महिला खिलाड़ी भी बनीं।

रीता फारिया पॉवेल : रीता फारिया पॉवेल एक भारतीय मॉडल, डॉक्टर और ब्यूटी व्वीन हैं। उन्होंने मिस वर्ल्ड 1966 जीता और खिताब जीतने वाली पहली एशियाई महिला बनीं। वे डॉक्टर के रूप में अर्हता प्राप्त करने वाली पहली मिस वर्ल्ड विजेता भी बनीं।

इंदिरा गांधी : इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनीं। इंदिरा गांधी को 1999 में बीबीसी के सर्वेक्षण में 'वुमन ऑफ द मिलेनियम' के रूप में नामित किया गया था। उन्हें भारत रत्न पुरस्कार से भी नवाजा गया।

मदर टेरेसा : मदर टेरेसा 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनीं। मदर टेरेसा ने कई मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की, जो एक रोमन कैथोलिक धार्मिक मंडली थी। उन्होंने अपना जीवन सामाजिक कार्यों में लगा दिया।

शिला डार्वे : शिला डार्वे देश की पहली महिला ऑटो रिक्शा चालक बनीं, जब उन्होंने पहली बार वर्ष 1988 में 'पुरुष-प्रधान' क्षेत्र में कदम रखा।

मिताली राज : मिताली राज टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक (214 नाबाद वेलिंगटन, 2004 में न्यूजीलैंड के खिलाफ) बनाने वाली पहली महिला थीं। वे दुनिया में इस मुकाम को हासिल करने वाली पहली महिला थीं।

प्रतिभा पाटिल : प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति बनीं और जुलाई, 2007 से जुलाई, 2012 तक राष्ट्रपति पद पर आसीन रहीं।

अरुणिमा सिन्हा : अरुणिमा सिन्हा माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग महिला हैं। वे एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली दिव्यांग भारतीय भी हैं। वे एक राष्ट्रीय स्तर की वॉलीबॉल खिलाड़ी थी, लेकिन 2011 में उन्हें चलती ट्रेन से धक्का दे दिया गया था। इस हादसे के बाद उनका एक पैर घुटने के नीचे से काटना पड़ा।

रोशनी शर्मा : रोशनी शर्मा कन्याकुमारी से कश्मीर तक मोटरसाइकिल चलाने वाली पहली भारतीय महिला बनीं।

ऐसी अनगिनत जानी व अनजानी महिलाएं, जिन्होंने लीक से हटकर अपनी जिद, शक्ति और जिजीविषा से अपनी विशिष्ट पहचान बनाई। इन नारियों में से कोई बस-मेट्रो चला रही हैं, तो कोई लड़ाकू विमान की पायलट हैं। किसी ने स्वयं सहायता समूह के जरिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विशिष्ट योगदान दिया है तो कुछ खेलों के जरिए देश का परचम बुलंद कर रही हैं। ●



अमूल्य मानव जीवन हेतु राज्य सरकार का अनुपम प्रयास चिरंजीवी योजना

नीतू शर्मा

शोधार्थी, राजस्थान विश्वविद्यालय

आशाराम खटीक

जनसंर्क अधिकारी, प्रकाशन

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना के बजट में बढ़ोतरी

इस योजना के आरंभ से पहले अनेक लोग धन के अभाव में इलाज न करवा पाने के चलते जिन्दगी और मौत से जूझते हुए बहुत बार दम तोड़ देते थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गरीब के मर्ज के मर्म को समझते हुए संवेदनशीलता के साथ इस योजना का उद्भव किया। इस योजना के लागू होने के बाद प्रतिवर्ष अस्पतालों में निःशुल्क दवा, सर्जिकल उपकरण आदि के उपलब्ध होने से आउटडोर एवं इनडोर में मरीजों की संख्या में काफी वृद्धि होने लगी। वर्ष 2011 में इस योजना का बजट 190 करोड़ था जिसे आज बढ़ाकर 965 करोड़ रुपये तक किया जा चुका है।

वर्तमान राज्य सरकार द्वारा कोरोनाकाल में भी मरीजों के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कोरोना से ग्रसित रोगियों को महंगी दवाएं और

कि सी भी समृद्ध राष्ट्र की समृद्धि के निर्माणकारी तत्व वहां के स्वस्थ नागरिक ही होते हैं तथा विकसित राष्ट्र में स्वास्थ्य का अधिकार उस राष्ट्र की जनता का बुनियादी अधिकार होता है। इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने गहन चिंतन-विमर्श कर मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना की नींव रखी और इसका आगाज भी उस समय में वर्तमान मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा 2 अक्टूबर 2011 को किया गया जो कि राज्य की जनता के लिए वरदान साबित हुई।

मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना एवं निःशुल्क जांच योजना द्वारा लाभान्वितों की संख्या से प्रेरित होकर इस योजना के सुदृढीकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के माध्यम से राज्य के 17 हजार 550 चिकित्सा संस्थानों में निःशुल्क दवाइयों उपलब्ध करवायी जा रही हैं। इस योजना में यह भी निर्णित किया गया कि आउटडोर रोगियों हेतु दवा वितरण केन्द्र ओ.पी.डी. के समयानुसार तथा इनडोर एवं आपातकालीन मरीजों के लिए दवा की उपलब्धता 24 घण्टे सुनिश्चित की जा सके।



MNDY & MNJY योजना के लाभ

उच्च गुणवत्ता व कम लागत की चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने की दिशा में ऐतिहासिक और संवेदनशील प्रयास, जिसके अन्तर्गत-

- राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के सामान्य उपयोग में आने वाली आवश्यक दवाइयों का निःशुल्क वितरण किया जा रहा है।
- आमजन के दवा पर होने वाले खर्च में कटौती हो रही है।
- धन की कमी के कारण चिकित्सा सेवाओं से वंचित वर्ग के लोगों का इलाज सम्भव हुआ है।
- दवाइयों व इन्जेक्शन आदि के साथ-साथ सामान्यतया उपयोग में आने वाले सर्जिकल उपकरणों जैसे- नीडल, डिस्पोजेबल सिरिंज आईवीए ब्लड ट्रांसफ्यूजन सेट व टांको हेतु सूचर्स आदि भी निःशुल्क उपलब्ध करवाये जा रहे हैं।
- सामान्यतः रोगी को तीन दिन की निःशुल्क दवा उपलब्ध कराई जाती है। अति आवश्यक होने पर या विशेष परिस्थितियों में कारण इंगित करते हुये 7 दिन तक की दवा उपलब्ध करवायी जा रही है।



छाया: राजेन्द्र शर्मा

जीवनरक्षक इंजेक्शन निःशुल्क उपलब्ध करवाये गये। इसी का परिणाम रहा कि केन्द्र सरकार की ओर से दवा की मांग के अनुरूप उपलब्धता, उच्च तकनीक, संख्या इत्यादि जैसे मापदण्डों के आधार पर कोरोना प्रबंधन में राजस्थान प्रदेश का नाम अप्रैल, 2019 में देशभर में हुई रैंकिंग में प्रथम स्थान पर रहा।

निःशुल्क दवा योजना में सर्वाधिक दवाएं मुफ्त देने और लगभग 100 प्रकार की मुफ्त जांचों के लिए राजस्थान ने देशभर में अलग पहचान बनायी है। साथ ही राजस्थान ने निःशुल्क दवा वितरण योजना में सर्वाधिक 712 प्रकार की विभिन्न दवाइयां निःशुल्क उपलब्ध करवाकर देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है।

मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना

प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने 1 मई 2021 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना प्रारंभ की थी। पहले इस योजना का दायरा 5 लाख रुपये था जिसे बढ़ाकर बाद में 10 लाख रुपये एवं हाल में बचत, राहत और बढ़त की थीम पर पारित किए गए बजट में प्रति परिवार 25 लाख रुपये प्रतिवर्ष कर दिया गया है। अब प्रदेश के निजी अस्पतालों में भी चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत राजस्थान का कोई भी परिवार 25 लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त में करा सकेगा। इसके लिए परिवार के मुखिया को इस बीमा योजना में पंजीकरण कराना होता है। पंजीकरण शुल्क भी राज्य सरकार वहन करती है अर्थात् यह भी निःशुल्क है। केवल इस बीमा योजना के प्रीमियम की राशि सालाना लगभग 850 रुपये बीमित परिवार को जमा करानी होगी। राजस्थान के लगभग 1 करोड़ 33 लाख परिवार चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ ले रहे हैं। इस योजना के तहत प्रदेश के 700 निजी अस्पतालों में इलाज किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग अनवरत रूप से प्रयासरत है कि प्रत्येक अस्पताल में ई.सी.जी. टेक्नीशियन नियुक्त किये जाएं। एन.एच.एम. में कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के पदों को भरा जाये। बजट में राज्य सरकार द्वारा यह भी घोषणा की जा चुकी है कि इस बीमा योजना में लाभान्वित होने वाले पात्र परिवारों की प्रीमियम राशि भी राज्य सरकार स्वयं वहन

करेगी।

स्वास्थ्य सेवाओं के सुदृढीकरण के राज्य सरकार के इन अनूठे, अनुकरणीय और सराहनीय प्रयासों से अब आम जनता के मन में स्वास्थ्य को लेकर काफी हद तक जागरूकता भी उत्पन्न हो गई है जिससे अस्पतालों की ओ.पी.डी. की संख्या में इजाफा हुआ है।

इन समन्वित प्रयासों का ही नतीजा है कि राजस्थान राज्य अब बीमारू राज्य से बाहर निकलने में सक्षम हो पाया है। साथ ही राज्य सरकार के कोरोना प्रबंधन की सराहना स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा की जा चुकी है।

निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि इन सभी प्रयासों को देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जाना चाहिए जिससे देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती मिल सके, भारत जैसे युवा देश में हमारे नागरिक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें और स्वस्थ मानव संसाधन किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी होती है। विकसित और समृद्ध राष्ट्र की परिकल्पना को संजोने और उसे साकार करने की दृष्टि से यह कदम एक महत्त्वपूर्ण अनुष्ठान साबित हो सकता है। ●





Rajasthan Government's Comprehensive Approach to Women Empowerment

The Rajasthan government has always addressed the issues faced by women and promoted gender equality. One of the most notable initiatives taken by the government is the launch of the Indira Mahila Shakti Nidhi in year 2019, under which Indira Mahila Shakti Fund of Rs. 1,000 crores was allocated to different schemes for women in Rajasthan. It is aimed at empowering women by providing them with training, skill development, and employment opportunities. Indira Mahila Shakti Nidhi was also formed to provide support to women in accessing various government schemes and programmes in terms of health and education.

Promotion of Female Education in Rajasthan

The State government has always been proactive in promoting women's education. For that matter, Chief Minister Shri Ashok Gehlot has proposed many schemes such as Indira Mahila Shakti Prashikshan Evam Kaushal Samvardhan Yojana, Shiksha Setu Yojana and Kaushal Samarthyta Yojana.

To attain the goal of achieving gender parity in education in Rajasthan 2,56,655 women and girls have been trained with basic computer skills. Apart from that 10,808 women benefitted through Kaushal Samarthyta Yojana.

The state government has also set up women's colleges in several districts of Rajasthan, providing opportunities for women to pursue higher education. Chief Minister Shri Gehlot has opened 211 colleges in the last four years from which 94 colleges are for girls.

The government has also provided scholarships such as Rajasthan Post Matric Scholarship Yojana to meritorious girl

Tarushi Agrawal

students. Shri Ashok Gehlot announced in the recent budget that

girl students will be distributed 30,000 scooters under Kalibai Bheel Medhavi Chhatra Scooty Yojana and Devnarayan Chhatra Scooty Vitran Yojana for excellence in education.

Rajasthan's Efforts in Promoting Female Employment

The Rajasthan government has taken several initiatives for women of the state especially in rural areas who face multiple challenges such as lack of education, traditional patriarchal attitudes and limited job opportunities. State government launched Indira Mahila Shakti Udyam Protsahan Yojana to provide subsidized loans through banks to women or women self-help groups for establishment of enterprises and diversification of employment opportunities for women. Under the scheme, Rs. 93.48 crore worth loans were provided to 1,694 women and women self-help groups.

Another scheme launched by Shri Ashok Gehlot is Jagriti : Back to Work from home job scheme. The scheme is aimed to employ women who want to work from home so that they can empower themselves without affecting their domestic life. For this scheme, 21,636 registrations have been received till now and 13,983 job offers have been provided by 51 employers for which 1,182 offer letters have been issued.

For extensive employment opportunities for women entrepreneurs and self-help groups, exhibitions such as Amrita



Haat Bazar are organized in the state.

Improvement in women's health in Rajasthan

Continuous efforts are being made to improve women's health in Rajasthan by the state government including initiatives to increase access to maternal healthcare, improve nutrition and expand access to menstrual health services. To raise awareness and break the stigma around menstruation in the state, the state government has launched I M Shakti Udaan Yojana for the distribution of free sanitary pads to women and girls of the state. 12 sanitary pads per month are distributed and campaigns are organized on a regular basis to make women and young girls aware about menstrual hygiene. In the first phase of the scheme, about 29 lakh women and girls benefitted. In the ongoing second phase, 1 crore 51 lakh women and girls are being benefitted under the scheme. Rs 584 crores will be spent further on the scheme according to the budget of 2023-24.

Apart from that, Indira Gandhi Matritva Poshan Yojana was launched by Shri Ashok Gehlot on the 103rd Birth anniversary of former Prime Minister Smt. Indira Gandhi. This scheme is aimed at providing assistance and nutritional benefits to women delivering for the second time with the financial help of Rs 6,000 for a baby boy and Rs 8,000 for a baby girl.

Initiatives for Women's Safety and Security

To ensure women's safety, Chief Minister Shri Ashok Gehlot

has made valiant efforts to make Rajasthan a safe state for women. Self-defense training programmes are conducted in schools for girls on a regular basis. With the initiative of helping victims of sexual violence, Suraksha Sakhi Yojana was launched in Rajasthan. The scheme provides training to women on self-defense, legal rights, and life skills. The scheme is implemented through a network of trained volunteers and service providers called as Suraksha Sakhi.

The Nirbhaya Squad is a special task force in Rajasthan that was created to ensure the safety and security of women in the state. The Nirbhaya Squad comprises female police officers who are specially trained to handle cases of violence against women. The squad responds promptly to complaints of violence, and ensures that the perpetrators are brought to justice.

The state government has taken several significant steps to empower women and promote gender equality in the state. The initiatives taken by the government have helped to improve the lives of women and ensure their safety, education, and employment opportunities. The citizens must acknowledge the efforts of the Rajasthan government and continue to work towards a society where women have equal rights and opportunities. ●



छाया: बृजेश कुमार निगम

साहित्य, कला और संगीत का संगम

उच्छब साहित्य रौ



सूर्य नगरी जोधपुर के जनाना बाग (उम्मेद गार्डन) में 25 से 27 मार्च को आयोजित राजस्थान साहित्य उत्सव, साहित्य कुम्भ, उच्छब साहित्य रौ या राजस्थान लिटरेचर फेस्टिवल-2023 अनूठा और अप्रत्याशित रहा। इसमें 80 प्रतिभागियों (लगभग सभी राजस्थान मूल के) को आमंत्रित किया गया और उन्हें 13 विभिन्न संवाद सत्रों में अपने विषय पर चर्चा का अवसर दिया गया। राज्य की विभिन्न साहित्य, कला, राजस्थानी, संस्कृत और उर्दू अकादमियों ने एकजुटता का परिचय देकर साहित्यकारों, कलाकारों और नई पीढ़ी के युवा दर्शकों के लिए एक साझा मंच प्रस्तुत किया। सत्रों का लाइव कवरेज भी दूर घरों में बैठे साहित्य प्रेमियों के लिये आकर्षण का केंद्र रहा। इस विधा में यह पहला आयोजन था। इस उत्सव में साहित्य के समसामयिक मुद्दों को मंच ने पुरजोर तरीके से सबके सामने रखा। साहित्यिक गतिविधियों के साथ ही इस उत्सव ने सांस्कृतिक गतिविधियों की रंग-बिरंगी छटा भी देखी। सुरीले साजों की जुगलबंदी ने श्रोताओं का दिल जीता। 13 तेरह संवाद-सत्रों के अलावा कवि सम्मेलन, मुशायरा, और काव्य सत्रों में 12 हिंदी कवि, 15 राजस्थानी कवि और 19 शायर की भागीदारी रही। श्रोताओं और विशेष अतिथियों से खचाखच भरे मीरा सभागृह में साहित्य, संस्कृति और कला की बानगी देखने और सुनने को मिली। कला मेला, हस्तशिल्प मेला, कोमल कोठारी कला शिविर में भी प्रतिभागियों और दर्शकों ने अपनी अच्छी-खासी रुचि दिखाई। पुस्तक मेला और राजस्थान के अनूठे फूड स्टॉल भी आकर्षण के केंद्र रहे।

डॉ. यश गोयल
वरिष्ठ पत्रकार

उद्घाटन सत्र

उद्घाटन सत्र में सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती अरुणा राय और प्रख्यात शायर और आलोचक श्री शीन काफ निजाम, प्रमुख शासन सचिव-कला एवं संस्कृति विभाग श्रीमती गायत्री राठी, जवाहर कला केंद्र की अतिरिक्ति महानिदेशक प्रियंका जोधावत और संस्कृत अकादमी के निदेशक और कवि संजय झाला की उपस्थिति उल्लेखनीय रही।

साहित्यकारों का सम्मान

विभिन्न अकादमियों की ओर से उल्लेखनीय कृतित्व तथा उत्कृष्ट योगदान के लिए 10 मनीषी विद्वानों/साहित्यकारों को विभिन्न पुरस्कारों से विभूषित किया गया। इनमें राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर की ओर से प्रमोद कुमार शर्मा को अखिल भारतीय माघ पुरस्कार तथा प्रो. वैद्य बनवारी लाल गौड़ को अम्बिकादत्त व्यास पुरस्कार प्रदान किया गया। राजस्थान उर्दू अकादमी, जयपुर की ओर से डॉ. अशरद अब्दुल हमीद को प्रो. महमूद शिरानी अवॉर्ड और आदिल रजा मंसूरी को



अख्तर शिरानी अवॉर्ड से नवाजा गया। वहीं डॉ. दिविक रमेश, डॉ. प्रबोध कुमार गोविल, चांद मोहम्मद घोषी को पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी जयपुर के बाल साहित्य मनीषी अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। पद्मश्री से सम्मानित चंद्र प्रकाश देवल को राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर की ओर से पं. जनार्दन राय नागर पुरस्कार से अलंकृत किया गया। हबीब कैफी व शिवराज छंगाणी को राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर की ओर से वर्ष 2022-23 के विशिष्ट साहित्यकार सम्मान से पुरस्कृत किया गया।

संवाद सत्र

गांधी-नेहरू दर्शन की सार्वकालिकता विषय पर चर्चा में प्रो. सतीश राय ने इंटरनेट और सोशल मीडिया में भी महात्मा गांधी की प्रासंगिकता और उनके विचारों के महत्व के बारे में बात की।

'वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मीडिया का बदलता स्वरूप' विषय पर आयोजित संवाद सत्र में वरिष्ठ पत्रकार और साहित्यकार श्री ओम थानवी, डॉ यश गोयल, शिक्षाविद प्रो. सुधि राजीव, पूर्व सूचना आयुक्त नारायण बारेठ, साहित्यकार अमित वाजपेयी, और मनोज वाष्ण्ये ने गत 40 वर्षों में सभी तरह के मीडिया में आए बदलाव पर गहन चर्चा की।

'समकालीन लेखन के अभिनव प्रयोग' विषय पर डॉ. बृजरत्न जोशी और डॉ. दुर्गा प्रसाद अग्रवाल ने भाषा में किए जा रहे बदलावों की गंभीरता पर अपने विचार रखे।

'साहित्यिक और सांस्कृतिक चुनौतियां' विषय पर संवाद सत्र की अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार और राजस्थान साहित्य अकादमी के पूर्व अध्यक्ष वेद व्यास ने की। उनके साथ डॉ. गजेसिंह राजपुरोहित और राजस्थान साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉ. दुलाराम सहाय ने इस विषय पर प्रकाश डाला।

नंद किशोर आचार्य ने कविता में संवेदना और विवेक के महत्व को उजागर किया। उन्होंने संस्कृति की प्रकृति, प्रक्रिया और तात्पर्य के बारे में बात की।

केसी मालू ने साहित्य व संस्कृति के संबंध के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि हजारों वर्षों से जो लिखा गया है वही हमारी संस्कृति है, जो उसमें अच्छा होता है, वही संस्कृति के रूप में अपना लिया जाता है।

'साहित्य में सर्वधर्म समभाव' की आवश्यकता में शास्त्री कोसलेन्द्र दास ने बताया कि विश्व में वेदों से प्राचीन कोई साहित्य नहीं है, कोई भी साहित्य पुरातन होने में वेदों की बराबरी नहीं कर सकता है। श्री भरत ओला ने बताया कि लोक हमेशा ही सर्वधर्म समभाव की बात करता। साहित्यकार, संस्कृतिकर्मी और कला समीक्षक डॉ. राजेश कुमार व्यास शब्दों के प्रयोग और उनकी व्याख्या में बरती जाने वाली सावधानी के बारे में बताया। उनके मुताबिक साहित्य में मैत्री भाव ही समभाव होता है, लेकिन इन सब का मूल धर्म समभाव होता है।

काव्य सत्र में कवयित्री दीपा सैनी ने अपनी कविता 'तेरे नूर के आगे मैं जुगनू, जुगनू की बिसात क्या, मैं तेरी दहलीज का दीपक और मेरी औकात क्या', पेश कर शौहरत बटोरी। किशन दाधीच ने कविता के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा जब भी इतिहास पर खतरा आया है तब या तो ऋषि या कवि ने उसे बचाया है।

राजस्थान की संत परंपरा और साहित्य सृजन' विषय पर प्रो. कल्याण सिंह



शेखावत ने बताया कि संत उसे कहा जाता है जो पहले सभी गुण खुद धारण करे और फिर समाज को एक रास्ता दिखाए। उन्होंने यह भी बताया कि साहित्य और ग्रंथ भक्ति मानव का राष्ट्र के प्रति कर्तव्य निर्वहन के साधन हैं। हजारों ग्रंथ हैं पर पढ़ने वाला कोई नहीं है। लोगों में साहित्यिक चेतना में गिरावट आई है। सिर्फ डिग्रियों से नहीं संस्कृति से ज्ञान से मिलता है। चंद्र प्रकाश देवल ने कहा कि सत्य को धारण करने वाला ही संत है। उनके मुताबिक सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा संदेश कबीर जैसे संतों के पास ही होता है। राजस्थानी साहित्य में संत, सती, वीर और लोक साहित्य सब मिलता है। संत अनंत हैं और संत साहित्य भी अनंत रहेगा।

'राजस्थान के लोक नाट्य एवं आधुनिक रंगमंच' विषय रमेश बोराणा ने बताया कि रंगमंच बंधन से मुक्त करता है। उनका मत है कि परफॉर्मिंग आर्ट को सरल—सहज बनाया जाना चाहिए जिससे इसका प्रभावी संप्रेषण हो सके।

डॉ. गौरीशंकर प्रजापत ने कहा कि राजस्थान लोकनाट्यों की धरती है, यहां तमाशा जैसे अन्य राज्यों के लोक नाट्य को भी पूरा सम्मान दिया गया है।

प्रवासी राजस्थानी एवं उनका रचना संसार विषय पर गजेंद्र कविया ने कहा कि प्रवासी राजस्थानी भले ही बाहर रहते हैं, लेकिन वे 'देश में चालो नीं ढोला मन भटकै, काकड़िया मतीरा खास्यां खूब डटकै' गीत गाकर राजस्थान को खूब याद करते हैं। इसी सत्र में डॉ. सुरेंद्र पोखरना ने देश के दूसरे हिस्सों में एक दो राजस्थानी मिलते हैं तो उन्हें यहां की भाषा में ही बात करनी चाहिए। डॉ. जयप्रकाश सेठिया ने कहा कि हम जहां भी रहें हमें अपनी भाषा को जीवित रखना जरूरी है।

साहित्य, कला और संगीत का संगम

साहित्य कुंभ में प्रदेशवासियों के साथ-साथ विदेशी पर्यटकों ने भी बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया। साहित्यकारों को मंच प्रदान करने और युवाओं को साहित्य के प्रति रुचि पैदा करने के उद्देश्य से आयोजित उत्सव में साहित्य, कला और संगीत का संगम दिखाई दिया। पद्मश्री अनवर खां मांगणियार की लोक गायन प्रस्तुति ने श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। सीताराम लालस पुस्तक मेले में पुस्तक प्रेमियों की चहलकदमी रही। कोमल कोठारी कला शिविर में दृश्य कला व अन्य कारीगरी से आगंतुक रू-ब-रू हुए। हस्तशिल्प मेले में दस्तकारों का हुनर देखने को मिला तो फूड स्टॉल पर लोग विभिन्न व्यंजनों का स्वाद लेते नजर आए।

तीन दिवसीय राजस्थान साहित्य उत्सव का 27 मार्च की रात रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ समापन हो गया। शब्दों की प्रतिध्वनि, सुनहरे बिंबों की चमक-दमक, साहित्य से जुड़ी बहुरंगी संवाद शृंखलाओं की गूंज, तालियों की गड़गड़ाहट और साहित्य के लिए व्यापक प्रयासों में जुटते हुए राजस्थान के साहित्य जगत को और अधिक उत्कर्ष पर लाने के लिए उत्तरोत्तर सहभागिता विस्तार के संकल्पों के साथ यह यादगार आयोजन आशातीत सफलताओं के साथ पूर्ण हुआ। ●

राजस्थान साहित्य उत्सव



अनुभव, भाव और विचारों की अभिव्यक्ति

राजस्थान साहित्य उत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य राज्य की समृद्ध साहित्यिक परंपरा को नई पीढ़ी से अवगत कराने के साथ ही राजस्थान के साहित्यिक अवदान को वैश्विक पटल पर स्थापित करने वाले साहित्यकारों पर एक सार्थक चर्चा और विमर्श के साथ नये और युवा साहित्यकारों को एक प्रभावी और सशक्त मंच उपलब्ध कराना था।

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की बजट घोषणा के क्रियान्वयन के आलोक में राजस्थान साहित्य उत्सव (साहित्य कुंभ-2023) का आयोजन जनाना बाग, जोधपुर में 25 से 27 मार्च, 2023 को किया गया।

राज्य सरकार के इस पहले आधिकारिक साहित्य उत्सव को अन्य उत्सवों से पृथक् एवं महत्वपूर्ण बनाये जाने की दृष्टि से साहित्य की सभी विधाओं, शैलियों, घटकों को समावेशित करते हुए विभिन्न साहित्यिक एवं लोक साहित्यिक परंपराओं के साथ नए और अनछुये तथा वर्तमान दृष्टि से प्रासंगिक विषयों पर सार्थक और पर्याप्त विचार-विमर्श हुआ।

कला एवं संस्कृति विभाग, राजस्थान तथा जवाहर कला केंद्र, जयपुर के संयुक्त तत्वावधान एवं संयोजन में आयोजित इस साहित्यिक कुंभ के

प्रियंका जोधावत
अति. महानिदेशक, जवाहर कला केंद्र

आयोजन स्थल जनाना बाग की साज-सज्जा एवं परिष्करण में जिला प्रशासन, जोधपुर, जोधपुर विकास प्राधिकरण और जयपुर विरासत फाउंडेशन के संयुक्त रचनात्मक प्रयास रेखांकित किए जाने योग्य हैं।

राज्य सरकार के इस पहले आधिकारिक साहित्य उत्सव का उद्घाटन सत्र 25 मार्च, 2023 को मुख्यमंत्री के सारगर्भित संदेश वाचन के साथ शुरू हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कला एवं संस्कृति मंत्री डॉ. बी.डी.कल्ला कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री रमेश बोराणा, उपाध्यक्ष, राज्य मेला प्राधिकरण, विशिष्ट वक्ताओं में श्रीमती अरुणा रॉय, श्री शीन काफ निजाम के साथ कला एवं संस्कृति विभाग में प्रमुख शासन सचिव श्रीमती गायत्री राठौड़ एवं अकादमियों के अध्यक्ष उपस्थित थे।

राजस्थान संस्कृत अकादमी की अध्यक्ष डॉ. सरोज कोचर, पंडित जवाहरलाल नेहरू बाल साहित्य अकादमी के चेयरमैन श्री इकराम राजस्थानी, राजस्थान साहित्य अकादमी के चेयरमैन डॉ. दुलाराम सारण,

राजस्थान ललित कला अकादमी के चेयरमैन श्री लक्ष्मण व्यास, उर्दू अकादमी चेयरमैन डॉ. हुसैन रजा खान, संगीत नाटक अकादमी की चेयरमैन श्रीमती बिनाका जैश मालू आदि के स्वागत सत्कार के साथ विभिन्न अकादमियों द्वारा साहित्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान हेतु प्रो. प्रमोद कुमार शर्मा, प्रो. वैद्य बनवारी लाल गौड़, डॉ. अशरद अब्दुल हमीद, श्री आदिल रजा मंसूरी, डॉ. दिविक रमेश, डॉ. प्रबोध कुमार गोविल, श्री चांद मोहम्मद घोसी और डॉ. चंद्रप्रकाश देवल को संबंधित अकादमियों द्वारा अपने विशिष्ट पुरस्कार-सम्मान से सम्मानित किया गया।

इस दौरान मीरा सभागार में आयोजित राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में डॉ. कुमार विश्वास, डॉ. प्रभा ठाकुर, श्री संपत सरल, डॉ. आईदान सिंह भाटी, श्री दुर्गादान सिंह, श्री जगदीश सोलंकी ने वर्तमान-भूतकाल और सुनहरे भविष्य की परिकल्पना पर आधारित हास्य व्यंग्य की कविताओं पर लाजवाब प्रस्तुति दी।

दूसरे दिन विजयदान देथा एवं कन्हैया लाल सेठिया सभागार में आयोजित संवाद सत्रों में गांधी-नेहरू दर्शन की सार्वकालिकता, साहित्य और समाज के सरोकार, महिला लेखन कल आज और कल, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मीडिया का बदलता स्वरूप, समकालीन लेखन में अभिनव प्रयोग, साहित्यिक और सांस्कृतिक चुनौतियां, साहित्य में सर्वधर्म समभाव, राजस्थान का समसामयिक कला परिदृश्य एवं संभावनाएं जैसे विषयों पर ज्ञानवर्धक वार्ताओं में साहित्य प्रेमियों, छात्रों, बुजुर्ग, युवाओं ने तार्किक ज्ञान अर्जन किया।

उसके बाद राजस्थान उर्दू अकादमी के संयोजन में आयोजित अखिल भारतीय मुशायरे में प्रख्यात शायर श्री वसीम बरेलवी, श्री शीन काफ निजाम, श्री शकील आजमी, श्री लोकेश कुमार सिंह साहिल, श्रीमती अंजुम रहबर, श्री मदन मोहन दानिश, श्री एम. तुराज सहित देश के प्रसिद्ध शायरों ने भाग लिया। इनकी तमाम पेशकश मोहब्बत, अमन, सौहार्द की भावनाओं पर आधारित थीं।

साहित्य कुंभ में देश के विभिन्न प्रकाशनों द्वारा अनेक विषयों एवं भाषाओं में लिखी हुई पुस्तकों का समावेश श्री सीताराम 'लालस' पुस्तक मेले में रहा। जोधपुर की जनता एवं बाहर से इस साहित्य सम्मेलन में पथारे साहित्य प्रेमियों के लिए यह सुखद अनुभव रहा। राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कला

शिविर में प्रबुद्ध कला साधकों द्वारा कला सृजन के साथ कला प्रदर्शनी, राजस्थानी संस्कृति को दर्शाता सेल्फी प्वाइंट, हस्तशिल्प मेला, मृण कला व खानपान की स्टॉल्स भी आकर्षण का केंद्र रहे।

साहित्य महाकुंभ के तीसरे दिन राजस्थान की संत परंपरा और साहित्य सृजन, राजस्थान के लोक नाट्य एवं आधुनिक रंगमंच, प्रवासी राजस्थानी एवं उनका रचना संसार, बाल साहित्य सृजन की चुनौतियां और संभावनाएं, दलित एवं आदिवासी साहित्य सृजन के नव आयाम, राजस्थान का सांगीतिक एवं फिल्म परिदृश्य जैसे विषयों पर वार्ता हुई, जिसमें प्रबुद्ध श्रोताओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया।

प्रातःकालीन बेला में लोक गायिका श्रीमती भंवरी देवी के सुरीले गीतों से वातावरण संगीतमय हो गया। राजस्थानी कवि सम्मेलन में श्री कैलाश मंडेला, श्री शिवराज छंगाणी, डॉ. आईदान सिंह भाटी, श्री मुकुट मणिराज सहित प्रदेश के प्रसिद्ध कवियों ने प्रदेश की लोक भाषाओं में अपने अस्तित्व की पहचान और गौरवशाली धरा का गुणगान किया, जो अपणायत की महक से लबरेज रहा। समापन समारोह में राजस्थान संगीत नाटक अकादमी के संयोजन में हुये बेस्ट ऑफ राजस्थान की संगीतमय प्रस्तुतियों से समूचा पंडाल गूंज उठा।

तीन दिवसीय इस साहित्य उत्सव में देशभर के साहित्य एवं कला प्रेमी एकत्रित हुए जिन्होंने अपनी लेखनी, विचार, अपने विशिष्ट प्रयासों से राज्य सरकार द्वारा आयोजित इस प्रथम साहित्यिक उत्सव को सदैव के लिए मानस पटल पर अविस्मरणीय कर दिया जिसकी गूंज संपूर्ण देश के अंतर्जाल आधारित लोकप्रिय सामाजिक माध्यमों में गुंजायमान है, और अंत में...

**जिसका कण-कण अंतःकरण का करता है स्पर्श
जोतन-मन और इस जीवन में भरे सुंगठित हर्ष
पुलकित रोम-रोम नवरस का पाकर के संस्पर्श
अक्षर ब्रह्म का आराधन है, साहित्यिक उत्कर्ष**



मरुस्थल में गूंजा पानी का पैगाम



छाया: आकांक्षा पालावत

मरुस्थल में गांव-शहरों से लेकर दूरदराज की ढाणियों तक पानी पहुंचाकर जल समस्या का समाधान करने की दिशा में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के निरंतर जारी भगीरथी प्रयास लोक कल्याण और बुनियादी सुविधाओं की दृष्टि से ऐतिहासिक उपलब्धियों भरे नए स्वर्णिम आयामों से रू-ब-रू करा रहे हैं। पहले पश्चिमी राजस्थान सूखा और अकाल का पर्याय माना जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री के प्रयासों से इस क्षेत्र का कायापलट हो चुका है। यह सब मुख्यमंत्री की दूरदर्शिता का परिचायक है।

दूरदर्शी एवं सार्थक प्रयासों का सुफल

मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तृतीय चरण की वृहद परियोजना के कार्यों की शुरुआत कर लाखों कठों की प्यास बुझाने के संकल्पों को साकार करते हुए लोक जीवन में खुशहाली के साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में विकास के सुनहरे आयामों का दिग्दर्शन कराने की दिशा में प्रदेश सरकार के प्रयासों की सार्थकता सिद्ध की है। राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के पूर्ववर्ती दो चरणों से लेकर तृतीय चरण तक के सफर को मूर्त रूप प्रदान करने में मुख्यमंत्री की समर्पित भूमिका नया इतिहास रच रही है।

पश्चिमी राजस्थान के विभिन्न जिलों में 30 वर्ष तक पेयजल की कमी नहीं

मुख्यमंत्री ने फरवरी माह में जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जोधपुर में आयोजित भव्य समारोह में जनसमूह से भरे उम्मेद स्टेडियम में तालियों की गूंज के बीच 1,799 करोड़ रुपये लागत की राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तृतीय चरण की आधारशिला रखी। श्री गहलोत ने रिमोट का बटन दबाकर राजीव गांधी लिफ्ट

आकांक्षा पालावत जनसंपर्क अधिकारी

कैनाल के तृतीय चरण का शिलान्यास किया और कहा कि राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल के तृतीय चरण को पूरा करने में वित्तीय कमी नहीं आने दी जाएगी। यह परियोजना वर्ष 2054 तक की पेयजल आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। वर्ष 2025 तक परियोजना का कार्य पूर्ण कर लिया जाएगा। इससे जोधपुर, पाली, बाड़मेर में अगले 30 वर्ष तक पानी की कमी नहीं आएगी।

शुरुआत से लेकर अब तक लगातार विस्तार

वर्षों पूर्व जोधपुर शहर की पेयजल मांग के दीर्घकालिक समाधान के लिए वर्ष 1995 में इंदिरा गांधी मुख्य नहर के जोधपुर से सटे जिले जैसलमेर के मदासर गांव स्थित बुर्जी संख्या 1,109 से जोधपुर में कायलाना झील की हाथी नहर के मध्य 175 किलोमीटर खुली नहर व 30 किलोमीटर लंबाई की पाइपलाइन अर्थात कुल 205 किलोमीटर लंबाई एवं 8 पंपगृह निर्मित कर राजीव गांधी लिफ्ट नहर प्रथम चरण पूर्ण किया गया था। इससे जोधपुर शहर एवं जिले के 158 गांवों को हिमालय का नीर प्राप्त हुआ। कालांतर में द्वितीय चरण के अंतर्गत वर्ष 2005 में पूर्व से निर्मित आठों पंपगृहों पर अतिरिक्त पंपों की स्थापना एवं 30 किलोमीटर लंबाई में अतिरिक्त पाइपलाइन बिछाई गई, जिसके फलस्वरूप राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल की पेयजल आपूर्ति की क्षमता 160 क्यूसेक से बढ़कर 240 क्यूसेक हो गई। इससे जोधपुर शहर तथा 3 कस्बों फलौदी, बिलाड़ा व समदड़ी के साथ ही जोधपुर एवं बाड़मेर जिले के 934 गांवों के लिए पेयजल व्यवस्था सुनिश्चित हो गई।

क्षमता संवर्धन के क्रमिक प्रयास

पुनर्गठित शहरी जल प्रदाय परियोजना जोधपुर शहर के अंतर्गत फ्रॉन्सीसी वित्त सहायता से वर्ष 2016 में द्वितीय चरण के अंतर्गत निर्मित प्रणाली की क्षमता का संवर्धन कर इंदिरा गांधी नहर से 295 क्यूसेक जल आहरण करने की क्षमता विकसित की गई। वर्तमान में दोनों चरणों की पूरी व्यवस्था के तहत हिमालय के पानी को इंदिरा गांधी नहर से 8 पंपगृहों में लगे उच्च क्षमता के पंपों द्वारा कायलाना झील तक लाया जा रहा है। इस नहर से रास्ते में पड़ने वाली सभी डिग्गियों में जल भंडारण किया जा रहा है। नहर के समानांतर फलीदी शहर के पास स्थित पंच तालाब में पानी लेकर जलप्रदाय योजना बावड़ीकल्लां, खारा-जालोड़ा के 80 गांवों के साथ फलीदी शहर को जल वितरण किया जा रहा है। गांव देवानिया के पास डिग्गी में पानी लेकर देवानिया-नाथड़ा के 332 गांवों को हिमालय का मीठा पानी दिया जा रहा है। इसी तरह गांव गगाड़ी के पास की डिग्गी में पानी लेकर पांचला-घेवड़ा-चिराई के 107 गांवों को जल आपूर्ति की जा रही है। तिवरी गांव के पास इनटेक वैल में पंप डालकर तिवरी-मथानियां-ओसियां-बावड़ी-भोपालगढ़ के 169 गांवों को जल वितरण किया जा रहा है। यह नहर जोधपुर जिले की जीवन रेखा साबित हो रही है।

सुनहरी तस्वीर दर्शाएगा तृतीय चरण

इन सबके उपरांत जनसंख्या वृद्धि के कारण पेयजल मांग बढ़ने तथा औद्योगिकरण व शहरीकरण होने के कारण पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिये 2016 में तृतीय चरण योजना की परिकल्पना की गई, जिसमें मुख्य नहर के समानांतर संपूर्ण लंबाई में पाइपलाइन व चार पंपगृहों की योजना को पूर्ण करने के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने अपनी संकल्पना को पूर्ण करने के लिए वर्ष 2019-20, 2020-21 एवं 2021-22 की बजट घोषणा में इसे सम्मिलित किया तथा राज्य मद से राशि आवंटन करते हुए 1799 करोड़ की संशोधित स्वीकृति जारी की।

कुल 1799 करोड़ की विशाल योजना

इस योजना के कार्यों के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न संस्थाओं की साझा लागत होगी। इनमें राज्य की हिस्सा राशि 1275.83 करोड़, जल जीवन मिशन (शहरी)/अमृत 2.0 से 425.27 करोड़, रीको की 96.90 करोड़, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडोर की 1 करोड़ की हिस्सा राशि को मिलाकर कुल 1,799 करोड़ की लागत से इस चरण का कार्य आगामी 3 वर्ष में अर्थात् 20 मई 2025 तक पूर्ण किया जाना है। राजीव गांधी लिफ्ट नहर तृतीय चरण परियोजना के लिए इंदिरा गांधी नहर विभाग द्वारा बुर्जी संख्या 1,121 के समीप 2,000 एम.सी.एफ.टी. क्षमता के विशालकाय रॉ-वॉटर डिग्गी का निर्माण करवाया जा रहा है।

सुदृढ़ होगा पेयजल प्रबंधन एवं वितरण तंत्र

परियोजना के अंतर्गत मुख्य रूप से प्रस्तावित रिजरवॉयर से जोधपुर की कायलाना झील तक 2,000 व 1,800 एम.एम. व्यास की बड़ी एम.एस. पाइपलाइन 213 किलोमीटर लंबाई में, वर्तमान राजीव गांधी लिफ्ट नहर के समानांतर बिछाए जाने का कार्य तथा चार उच्च क्षमता के पंपिंग स्टेशनों के निर्माण का कार्य किया जाना है। इस योजना का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। योजना के लिये पाइप शीघ्र उपलब्ध हों, इसके लिए फलीदी के निकट खीरवा गांव में 15 एकड़



भूमि में एम.एस. पाइपलाइन के निर्माण हेतु फैक्ट्री स्थापित की गई है। फलीदी एवं जोधपुर के समीप पाइप बिछाने का कार्य तीव्र गति से चल रहा है। मई, 2025 में इस परियोजना का कार्य पूर्ण हो जाने पर वर्तमान राजीव गांधी लिफ्ट नहर व प्रस्तावित पाइपलाइन द्वारा सम्मिलित रूप से कुल 1030 एम.एल.डी. पेयजल की आपूर्ति की जा सकेगी, जिससे जोधपुर शहर, फलीदी, पीपाड़, बिलाड़ा, भोपालगढ़ व समदड़ी कस्बे तथा जोधपुर जिले के 1 हजार 830 ग्राम, बाड़मेर के 211 ग्राम और पाली के 126 ग्रामों को मिलाकर कुल 2 हजार 167 ग्रामों की वर्ष 2054 की लगभग 80 लाख अभिकल्पित जनसंख्या को लाभान्वित किया जा सकेगा। इससे 69.79 करोड़ लीटर से अधिक प्रतिदिन की शुद्ध पेयजल मांग पूरी की जाएगी।

इसके पूर्ण होने पर इंदिरा गांधी नहर से जल आहरण क्षमता बढ़कर 420 क्यूसेक हो जाएगी। योजना के अंतर्गत राजीव गांधी लिफ्ट नहर के समानांतर जैसलमेर जिले के मदासर गांव के समीप इंदिरा गांधी नहर की बुर्जी संख्या 1,121 पर निर्माणाधीन एस्केप रिजरवॉयर से जोधपुर की कायलाना झील की हाथी नहर तक 213 किलोमीटर लंबी स्टील पाइपलाइन डालने एवं मदासर, घाटोर, फलीदी शहर व चामू के समीप 4 पंपगृहों का निर्माण कार्य प्रस्तावित है।

इसके लिए सर्वे कार्य पूर्ण कर लिया गया है। स्टील पाइप का निर्माण प्रारंभ कर दिया गया है। पाइप निर्माण के लिए राजीव गांधी लिफ्ट कैनाल की बुर्जी संख्या 58 के समीप पाइप यार्ड स्थापित कर दिया गया है, जिसमें पाइपों की भीतरी सतह पर सीमेंट मोर्टार लाइनिंग एवं बाहरी सतह पर गनाइटिंग का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में 23.20 किलोमीटर के पाइपों की सप्लाय प्राप्त कर ली गई है एवं 22.50 किलोमीटर लाइनिंग का कार्य कर लिया गया है। वर्तमान में हाथी नहर, जोधपुर एवं फलीदी में पाइपलाइन डालने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। इस परियोजना पर अब तक 88.98 करोड़ की धनराशि के कार्य हो चुके हैं। राजीव गांधी लिफ्ट नहर की तृतीय चरण की योजना से व्यापक स्तर पर पेयजल सुविधाओं का विस्तार होगा।

इन्हें भी मुहैया होगा पर्याप्त पेयजल

इसके साथ ही जोधपुर जिले के अंतर्गत संस्थागत एवं व्यापारिक क्षेत्र की पेयजल मांग 4.93 करोड़ लीटर प्रतिदिन, रक्षा विभाग के लिए 3.72 करोड़ लीटर प्रतिदिन, औद्योगिक (रीको) क्षेत्र के लिए 4.30 करोड़ लीटर प्रतिदिन तथा रोहट में विकसित हो रहे दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को भी 6 करोड़ लीटर पेयजल रोजाना प्राप्त हो सकेगा। ●



आधुनिक भारत के शिल्पकार भारत रत्न डॉ. भीमराव अंबेडकर

अभय सिंह

सहायक जनसंपर्क अधिकारी

“ डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म श्रीराम और श्रीमती भीमाबाई के घर 14 अप्रैल 1891 को महू छावनी मध्य प्रदेश में हुआ। उन्होंने एल्फिंस्टन कॉलेज, मुंबई से स्नातक की पढ़ाई पूर्ण की, उसके बाद 1913 में बड़ौदा राज्य के शासक सयाजी राव गायकवाड़ ने उन्हें उच्च अध्ययन के लिए छात्रवृत्ति प्रदान की। 1915 में श्री अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि हासिल की। 'ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास' शोध प्रबंध के लिए उन्हें कोलंबिया विश्वविद्यालय ने पीएचडी की उपाधि दी। डॉ. अंबेडकर ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 1921 में डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। साथ ही 1923 में ग्रेज इन लंदन से बैरिस्टर की डिग्री हासिल की। ”

14 अप्रैल को बीसवीं सदी के महानायक डॉ. भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई गई। उन्होंने देश को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षणिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, औद्योगिक, संवैधानिक जैसे सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अतुलनीय योगदान दिया। डॉ. अंबेडकर ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को एक नई दिशा दी। उन्होंने दलित और वंचित वर्गों को राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय रूप से जोड़ा।

दलितोद्धार के प्रणेता

डॉ. अंबेडकर ने दलित वर्ग में चेतना के प्रचार प्रसार के लिए बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1928 में डिप्रेसड क्लासेस एजुकेशन सोसायटी के गठन द्वारा छात्रवास स्थापित किए। 1945 में पीपुल्स एजुकेशन सोसायटी की स्थापना की जिसके तहत मुंबई में बुद्ध भवन एवं आनंद भवन कॉलेजों का निर्माण कराया और औरंगाबाद में उच्च शिक्षा के लिए मिलिंद कॉलेज की स्थापना की।

राजनीतिक सशक्तीकरण की दिशा में स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन कर 1937 के मुंबई प्रेसिडेंसी चुनाव में 17 में से 15 सीटों पर विजय प्राप्त की। दलितों के मानवाधिकार सुनिश्चित करने के लिए आंदोलनों की लंबी श्रृंखला चलाई, जिसमें महार सत्याग्रह, नासिक सत्याग्रह और एथेवला की गर्जना उल्लेखनीय हैं। इन सभी आंदोलनों का मूल उद्देश्य छुआछूत का प्रतिरोध, सार्वजनिक पेयजल स्रोतों का

उपयोग और जाति व्यवस्था का विरोध करना था। उन्होंने लंदन में आयोजित तीनों गोलमेज सम्मेलन में दलित वर्ग के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया। 1932 में पूना समझौते द्वारा दलित वर्ग के लिए प्रांतीय विधानसभा में अधिकाधिक दलित प्रतिनिधियों का चुनाव सुनिश्चित करवाया।

भारतीय संविधान में दलित हितों की सुरक्षा के लिए शैक्षणिक संस्थानों, राजकीय सेवाओं और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए आरक्षण का प्रावधान करके इन समुदायों की स्थिति को सुरक्षित किया।

राष्ट्र की आर्थिक उन्नति के नेतृत्वकर्ता

अर्थशास्त्री के रूप में डॉ. अंबेडकर का योगदान उनके द्वारा लिखे गए शोध ग्रंथ 'दी प्रोब्लम ऑफ रूपी' से परिलक्षित होता है। इस शोध ग्रंथ का यंग हिल्टन के नेतृत्व में रॉयल कमीशन ने अध्ययन किया, इसकी संस्तुति पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई। उनके "ब्रिटिश भारत में प्रांतीय वित्त का विकास" शोध प्रबंध के आधार पर वित्त आयोग की स्थापना हुई। उन्होंने औद्योगिक विकास, सतत एवं सहकारी कृषि, भूमि सुधार, संसाधनों के अनुकूलतम उपयोग, बहुउद्देशीय परियोजनाओं की व्यवहार्यता, तकनीकी विकास जैसे प्रमुख विषयों पर गहन एवं समग्र विचार प्रस्तुत किए। उनके आर्थिक विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं, जितने स्वतंत्रता से पूर्व थे।



भारत के पहले विधि और न्याय मंत्री के रूप में शपथ

श्रमिक कल्याण के नायक

वायसराय की परिषद में श्रम मंत्री रहते हुए डॉ. अंबेडकर ने श्रमिक कल्याण की दिशा में अनेक कार्य किए। समान कार्य के लिए समान वेतन, प्रसूति अवकाश, कर्मचारी राज्य बीमा योजना, स्वास्थ्य सुरक्षा, कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952, कर्मचारियों को दैनिक भत्ता, अनियमित कर्मचारियों को अवकाश की सुविधा, कर्मचारियों के वेतन श्रेणी की समीक्षा, खदान मजदूरों की सुरक्षा के लिए कानून निर्माण आदि कार्य उन्हें मजदूर हितों के संरक्षक के रूप में पहचान देते हैं।

नारी अधिकारों के पैरोकार

डॉ. अंबेडकर के अनुसार किसी भी देश की आधी आबादी महिलाएं होती हैं और कोई भी देश तभी तरक्की कर सकता है जब उस देश में महिलाओं को प्रगति के समान अवसर मिलें। उन्होंने अपने लेख 'नारी और प्रतिक्रान्ति' में नारी गरिमा और समानता के विरुद्ध जो भी अमानवीय मान्यताएं प्रचलित थी उनका खंडन किया। भारतीय संविधान निर्माण में महिला अधिकारों की सुरक्षा के लिए अनेक प्रावधान किए।

पत्रकारिता से जन-जागरण

डॉ. अंबेडकर ने वंचित वर्गों के उत्थान और जन जागरूकता के लिए मूक

नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत आदि पत्र—पत्रिकाओं का संपादन किया। उनके लेखन से दलित वर्ग राष्ट्रीय आंदोलन एवं मुख्यधारा की राजनीति से जुड़ पाया और समाज के वंचित वर्ग में अधिकार बोध की चेतना जागृत हुई।

संविधान निर्माता बाबा साहेब

डॉ. अंबेडकर ने भारत के पहले विधि मंत्री और संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। उन्हें हम संविधानशिल्पी के रूप में जानते हैं, उन्होंने अपने विधिक कौशल की अनूठी मिसाल संविधानरूपी अनुपम कृति से संपूर्ण विश्व के सामने रखी। नव स्वतंत्र लोकतांत्रिक राष्ट्र के स्थायित्व के लिए सशक्त विधिग्रंथ की आवश्यकता थी, जिसमें सभी वर्गों के हितों को सुरक्षित किया जा सके। डॉ. अंबेडकर ने विश्व के 60 से अधिक संविधानों के अध्ययन के बाद भारत के भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वैविध्य को दृष्टिगत रखते हुए, एक मौलिक संविधान का निर्माण किया। इस विस्तृत दस्तावेज में मानवाधिकार, नागरिक अधिकार, शासन का स्वरूप, राज्य के कर्तव्य, स्वतंत्र संवैधानिक संस्थाओं का गठन, वंचित वर्गों के लिए शैक्षणिक और राजनीतिक आरक्षण जैसे सभी तत्वों का उचित एवं प्रभावी समावेश किया गया।

जाति व्यवस्था राष्ट्रीय एकता में बाधक

डॉ. अंबेडकर ने अपने पहले लेख 'भारत में जातिप्रथा संरचना, उत्पत्ति और विकास' और एक अन्य लेख 'शूद्राज एंड दी काउंटर रिवोल्यूशन' में शोषणकारी व्यवस्था की कठोर शब्दों में आलोचना की।

उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों से परिपूर्ण राष्ट्र निर्माण का स्वप्न देखा था, जिसके आधारस्तंभ स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुता हैं। उन्होंने राष्ट्रीय एकता, अखंडता, सामाजिक समरसता में जाति व्यवस्था को सबसे बड़ा बाधक तत्व बताया। जाति व्यवस्था का सबसे बड़ा दोष छुआछूत है, जहां किसी के जन्म के आधार पर उसके मानवीय अधिकारों एवं संवेदनाओं को कुचल दिया जाता है। उन्होंने उसकी कड़ी आलोचना की और युवा पीढ़ी से अंतर्जातीय क्रियाकलापों को बढ़ावा देने की अपील की। ●



फरवरी 1934 में राजगृह में अपने परिवार के सदस्यों के साथ



छाया: राजेंद्र शर्मा

होलिया में उड़े रे गुलाल

होली और वसंत की मस्ती का समाजशास्त्र

डॉ. गोरधन लाल शर्मा
राजस्थान प्रशासनिक सेवा

होली वसंत ऋतु में मनाया जाने वाला भारतीय उपमहाद्वीप का एक महत्वपूर्ण त्योहार है। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। होली रंगों का तथा हंसी-खुशी का त्योहार है, जो आज पूरे विश्व में मनाया जाने लगा है। रंगों का त्योहार कहा जाने वाला यह पर्व पारंपरिक रूप से दो दिन मनाया जाता है। पहले दिन होलिका जलायी जाती है, जिसे होलिका दहन भी कहते हैं। दूसरे दिन को प्रमुखतः धुलंडी कहते हैं और धुरड्डी, धुरखेल या धूलिवंदन इसके अन्य नाम हैं। इस दिन लोग एक दूसरे पर रंग, अबीर-गुलाल आदि लगाते हैं। ढोल बजा कर होली के गीत गाए जाते हैं और घर-घर जाकर लोगों को रंग लगाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी कटुता को भूलकर गले मिलते हैं और फिर से दोस्त बन जाते हैं। एक दूसरे को रंगने और गाने-बजाने का दौर दोपहर तक चलता है। इसके बाद स्नान व विश्राम के बाद नए कपड़े पहनते हैं।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

होली भारत का अत्यंत प्राचीन पर्व है जो होली, होलिका या होलाका नाम से व्यापक रूप से मनाया जाता था। वसंत की ऋतु में हर्षोल्लास के साथ मनाए जाने के कारण इसे वसंतोत्सव भी कहा गया है। प्राचीन काल में लोग चंदन और गुलाल से ही होली खेलते थे। समय के साथ इनमें भी बदलाव देखने को मिला है। कई लोगों द्वारा प्राकृतिक रंगों का भी उपयोग किया जा रहा है, जिससे त्वचा या आंखों पर किसी भी प्रकार का कुप्रभाव न पड़े।

इस पर्व का वर्णन अनेक पुरातन ग्रंथों में मिलता है। जैमिनी के पूर्व मीमांसा-सूत्र और कथा गृह्य-सूत्र, नारद पुराण और भविष्य पुराण जैसे पुराणों की प्राचीन हस्तलिपियों में भी इस पर्व का उल्लेख मिलता है। विंध्य क्षेत्र के रामगढ़ स्थान पर स्थित ईसा से 300 वर्ष पुराने एक अभिलेख में भी इसका उल्लेख किया गया है।

संस्कृत साहित्य में वसंत ऋतु और वसंतोत्सव अनेक कवियों के प्रिय विषय रहे हैं। सुप्रसिद्ध मुस्लिम पर्यटक अलबरूनी ने भी अपने ऐतिहासिक यात्रा संस्मरण में होलिकोत्सव का वर्णन किया है। भारत के अनेक मुस्लिम कवियों ने अपनी रचनाओं में इस बात का उल्लेख किया है कि होलिकोत्सव केवल हिंदू ही नहीं मुसलमान भी मनाते हैं। इतिहास में वर्णन है कि शाहजहां के जमाने में होली को ईद-ए-गुलाबी या आब-ए-पाशी (रंगों की बौछार) कहा जाता था। मध्ययुगीन हिंदी साहित्य में दर्शित कृष्ण की लीलाओं में भी होली का विस्तृत वर्णन मिलता है।

राजस्थान की बहुरंगी होली

राजस्थान के विभिन्न इलाकों में होली मनाने का अलग और खास अंदाज है।

- पत्थरमार होली - बाड़मेर व डूंगरपुर
- लट्टुमार होली - ब्रज क्षेत्र (करौली व भरतपुर)
- कोड़ामार होली - भिनाय (अजमेर) एवं गंगानगर
- फूलों की होली - गोविंद देवजी मंदिर, जयपुर
- रम्मत और तणी काटना - बीकानेर
- चरकुला नृत्य - भरतपुर
- गेर नृत्य - बाड़मेर, पाली व मेवाड़
- चंग व गींदड़ नृत्य - शेखावाटी
- रोने-बिलखने वाली होली - जोधपुर
- गोबर के कंडों की होली - गलियाकोट (डूंगरपुर)
- राइ रमण की होली - भिलुड़ा ग्राम (डूंगरपुर)

- डेगची या बाल्टी मार होली - बीकानेर
- दूध व दही की होली - नाथद्वारा (राजसमंद)
- बादशाह की होली - नाथद्वारा (राजसमंद)
- अंगारों की होली - केकड़ी (अजमेर)
- देवर-भाभी की होली - ब्यावर (अजमेर)
- न्हाण की होली - सांगोद (कोटा)
- मुर्दे की सवारी - भीलवाड़ा
- कंकड़मार होली - जैसलमेर
- भाटा गेर - जालौर
- गोटा गेर - भीनमाल।

लट्टुमार होली - ब्रजांचल का फागोत्सव

भरतपुर एवं करौली के ब्रजांचल में फाल्गुन का आगमन कोई साधारण बात नहीं है। यहां की वनिताएं इसके आते ही गा उठती हैं: "सखी री भागन ते फागुन आयी, मैं तो खेलूंगी श्याम संग फाग।" ब्रज के लोकगायन के लिए कवि ने कहा है "कंकड़ हूँ जहां कांकुरी है रहे, संकर हूँ कि लगे जहं तारी, झूठे लगे जहं वेद-पुराण और भीठे लगे रसिया रसगारी।" यह रसिया ब्रज की धरोहर है, जिनमें नायक ब्रजराज कृष्ण और नायिका ब्रजेश्वरी राधा को लेकर मन के अंतरतम की भावना और उसके तार छेड़े जाते हैं।

गांव की चौपालों पर ब्रजवासी ग्रामीण अपने लोकवाद्य बम के साथ अपने ढप, ढोल और झांझ बजाते हुए रसिया गाते हैं। यहां की ग्रामीण महिलाएं अपने सिर पर भारी भरकम चरकुला रखकर उस पर जलते दीपकों के साथ नृत्य करती हैं। संपूर्ण ब्रज में इस तरह आनंद की अमृत वर्षा होती है। यह परंपरा ब्रज की धरोहर है।

गेर नृत्य

पाली के ग्रामीण इलाकों में फाल्गुन लगते ही गेर नृत्य शुरू हो जाता है। वहीं यह नृत्य डंका पंचमी से भी शुरू होता है। फाल्गुन के पूरे महीने रात में चौहटों पर ढोल और चंग की थाप पर गेर नृत्य किया जाता है। मारवाड़-गोडवाड़ इलाके में डांडी गेर नृत्य बहुत होता है और यह नृत्य इस इलाके में खासा लोकप्रिय है। यहां फाग गीत के साथ गालियां भी गाई जाती हैं।

चंग-गीदड़

फाल्गुन शुरू होते ही शेखावाटी में होली का हुड़दंग शुरू हो जाता है। हर मोहल्ले में चंग पार्टी होती है। होली के एक पखवाड़े पहले गीदड़ शुरू हो जाता है।



छाया: राजू रैनी



छाया: पिकी फुलवारिया

जगह- जगह भांग घुटती है। हालांकि अब ये नजारे कम ही देखने को मिलते हैं, जबकि शेखावाटी में ढूँढ का चलन अभी है।

रम्मत मंचन एवं तणी काटना

बीकानेर क्षेत्र में भी होली मनाने का खास अंदाज है। यहां रम्मतें, अनूठे फागणियां, फुटबॉल मैच, तणी काटने और पानी डोलची का खेल होली के दिन के खास आयोजन हैं। रम्मतों में खुले मंच पर विभिन्न कथानकों और किरदारों का अभिनय होता है। रम्मतों में हास्य, अभिनय, होली-ठिठोली, मौजमस्ती और साथ ही एक संदेश शामिल होता है।

कोड़े वाली होली

श्रीगंगानगर में भी होली मनाने का खास अंदाज है। यहां देवर-भाभी के बीच कोड़े वाली होली काफी चर्चित रही है। होली पर देवर भाभी को रंगने का प्रयास करता है और भाभी देवर की पीठ पर कोड़े मारती है। इस मौके पर देवर- भाभी से नेग भी मांगते हैं।

डेगची या बाल्टी मार होली

परंपरागत रूप से बीकानेर में डोलचीमार होली का आयोजन किया जाता है। वैसे तो बीकानेर में होली से आठ दिन पहले होलाष्टक के साथ ही होली के आयोजनों की शुरुआत हो जाती है, लेकिन होली से चार दिन पहले डोलचीमार होली का यह खेल काफी प्रसिद्ध है। इसे देखने के लिए दूर-दूर से लोग आते हैं और होली की इस मस्ती का आनंद उठाते हैं।

आदिवासी बहुल डूंगरपुर जिले की अनोखे रीति-रिवाजों की होली

सागवाड़ा के डेंडोरवाड़ा में टमाटर की होली (राड़) खेला जाती है, वहीं भीलुड़ा में पत्थरों की राड़, तो कोकापुर में जलते अंगारों पर चलने की परंपरा है। टमाटर राड़ में सागवाड़ा के डेंडोरवाड़ा में 12 फलों के आदिवासी समाज के युवा इकट्ठे होकर संगीत की धुन पर खूब डांस करते हुए गुटों में बंटकर टमाटर फेंकते हैं। परंपरागत रूप से 100 साल से भी ज्यादा समय से इस राड़ को खेला जाता है।

भगवान नृसिंह द्वारा हिरण्यकश्यप का वध

होली के पर्व से अनेक कहानियां जुड़ी हुई हैं। इनमें से सबसे प्रसिद्ध कहानी है प्रह्लाद की। माना जाता है कि प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक अत्यंत बलशाली असुर था। अपने बल के अहंकार में वह स्वयं को ही ईश्वर मानने लगा था।



छाया: पद्म सेनी

उसने अपने राज्य में ईश्वर का नाम लेने पर ही पाबंदी लगा दी थी। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रह्लाद ईश्वर भक्त था। प्रह्लाद की ईश्वर भक्ति से क्रुद्ध होकर हिरण्यकश्यप ने उसे अनेक कठोर दंड दिए, परंतु उसने ईश्वर की भक्ति का मार्ग न छोड़ा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह आग में भस्म नहीं हो सकती। हिरण्यकश्यप ने आदेश दिया कि होलिका प्रह्लाद को गोद में लेकर आग में बैठे लेकिन आग में बैठने पर होलिका तो जल गई, पर प्रह्लाद बच गया। ईश्वर भक्त प्रह्लाद की याद में इस दिन होली जलाई जाती है। प्रतीक रूप से यह भी माना जाता है कि प्रह्लाद का अर्थ आनंद होता है। वैर और उत्पीड़न की प्रतीक होलिका जलती है और प्रेम तथा उल्लास का प्रतीक प्रह्लाद (आनंद) अक्षुण्ण रहता है।

देश के विभिन्न भागों में होली

भारत में होली का उत्सव अलग-अलग प्रदेशों में भिन्नता के साथ मनाया जाता है -

- ब्रज क्षेत्र में बरसाने की लट्टमार होली
- कुमाऊं की गीत बैठकी संगीतमय होली
- बंगाल की दोल जात्रा (चैतन्य महाप्रभु के जन्मदिन पर)
- महाराष्ट्र का रंग पंचमी में सूखा गुलाल खेला
- तमिलनाडु की कमन पोडिगई वसंतोत्सव
- मणिपुर के याओसांग : पूर्णिमा के दिन सरोवर के तट पर होली
- छत्तीसगढ़ की लोक गीतों की होरी परंपरा
- मध्यप्रदेश के मालवा अंचल के आदिवासी इलाकों में भगोरिया होली
- बिहार का मौज-मस्ती युक्त फगुआ।

विदेशों में होली जैसे पर्व

न्यूजीलैंड का वानाका उत्सव : न्यूजीलैंड के अलग-अलग शहरों में हर वर्ष रंगीला त्योहार मनाया जाता है। इस दिन एक पार्क में शहर के बच्चे, बूढ़े और जवान इकट्ठे होते हैं। सभी अपने शरीर या दूसरों के शरीर पर पेंटिंग करते हैं। इस दौरान वे आपस में मस्ती भी करते हैं। जहां बच्चों के लिए यह दिन धमा-चौकड़ी मनाने का होता है, वहीं बुजुर्ग लोगों को उत्सव में बढ़-चढ़कर धमाल करने के लिए उत्साहित करते हैं।

थाईलैंड का सोंगकरन रंग पर्व : सोंगकरन थाई नववर्ष का पर्व है। इसमें पानी में

खूब मस्ती होती है। त्योहार के दौरान सभी लोग एक तालाब के पास एकत्र होते हैं और एक-दूसरे पर पानी फेंकते हैं। दो-चार लोग मिलकर एक व्यक्ति को तालाब में उछालते हैं और उसे डुबकी दिलाते हैं। इस त्योहार में बच्चे, बुजुर्ग, स्त्री और पुरुष सभी एक रंग में रंग जाते हैं। दिनभर गाने और डांस की धूम मची रहती है।

जापान का चेरी ब्लॉसम सीजन फेस्टिवल : जापान में मनाए जाने वाला यह उत्सव भी अपने अनूठेपन के लिए प्रसिद्ध है। उत्सव मार्च और अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, क्योंकि इस दौरान चेरी के पेड़ में फूल आते हैं। लोग अपने परिवार के साथ चेरी के बगीचे में बैठते हैं और एक-दूसरे को बधाई देते हैं। वे पेड़ से झाड़ती फूलों की पंखुडियों से होली खेलकर सबका स्वागत करते हैं। दिनभर चलने वाले इस त्योहार पर विशेष भोजन और संगीत-नृत्य के कार्यक्रम आयोजित होते हैं।

पेरू का इनकान उत्सव : पेरू में पांच दिन चलने वाले इस त्योहार के दौरान लोग रंगीन परिवेश में पूरे शहर में घूमते हैं। इस दौरान वे टोलियों में होते हैं। हर टोली की एक थीम होती है। ये लोग ड्रम की थाप पर नृत्य करते हैं और अपने आपको दूसरे से बेहतर साबित करने की कोशिश करते हैं। रात में कुजको महल के सामने सभी एकत्र होते हैं और एक-दूसरे को उत्सव की शुभकामना देते हैं।

पापुआ न्यू गिनी का गोरिका उत्सव : पापुआ न्यू गिनी में इस त्योहार के दौरान लोग माउंट हेगन की तलहटी में एकत्र होते हैं और पारंपरिक आदिवासी नृत्य करते हैं। वे अपने शरीर पर पंखियों के पर (पंख) और ऐसे ही कई पारंपरिक शृंगार किए होते हैं। मस्ती और उल्लास के त्योहार पर मजेदार भोजन आयोजित होते हैं।

चीन का बुद्ध का स्नान - पानी होली का उत्सव : चीन के युवान प्रांत में मार्च-अप्रैल में पानी फेंकने का उत्सव मनाया जाता है। यह दार्ढ़ लोगों के महत्वपूर्ण उत्सवों में से एक है। इस त्योहार को बुद्ध स्नान के नाम से भी जाना जाता है। त्योहार के दौरान सभी लोग एक-दूसरे पर पानी फेंकते हैं और एक-दूसरे को बधाई देते हैं।

गामारीजी - तिब्बत का स्नान पर्व : जुलाई माह के पहले दस दिन में तिब्बतियों का स्नान पर्व मनाया जाता है। इस पर्व को गामारीजी नाम से जाना जाता है। तिब्बतियों की मान्यता है कि इस दौरान नदी या तालाब का पानी मीठा, ठंडा, मृदुल, हल्का, साफ और हानिरहित होता है, जो गले के लिए अच्छा होता है, तिब्बती लोग इस दौरान नदी और झील के किनारे टेंट डालते हैं और स्नान को पर्व के रूप में मनाते हैं। ●



छाया: उत्तम जोशी, राजू सेनी

शेखावाटी में होली पर आयोजित होने वाले गींदड़ एवं चंग लोक नृत्यों की लोकप्रियता जगजाहिर है। शाम ढलते ही गींदड़ नृत्य के मंडपों में चहल-पहल शुरू हो जाती है। नृत्य स्थल पर पानी का छिड़काव हो जाने के बाद बालू रेत कुछ घंटों के लिए जम जाती है। इसके बाद नगाड़े की आवाज से लय मिलते हुए गींदड़ नृत्य शुरू होता है। इस नृत्य के कलाकारों के हाथों में लकड़ी के डंडे होते हैं और ये कलाकार गोलाकार घेरा बनाते हुए तथा नगाड़ा वादन की निश्चित लय पर परस्पर डंडे टकराते हुए इस नृत्य को परवान चढ़ाते हैं। नृत्य की लय और ताल "धलै गींदड़ चढ़े डंका" के वाक्य पर केंद्रित रहती है। इस वाक्य के सांकेतिक स्वर को प्रकट करते हुए नगाड़े पर आठ ठेके लगते हैं और इन आठ ठेकों पर कलाकार दो बार अपने डंडे क्रमशः आगे व पीछे वाले नर्तक के डंडों से टकराता है।

मंडप के बीच नगाड़ा वादक बैठा है और उसके इर्द-गिर्द लोक गीतों के गवैयों व बांसुरी वादकों का समूह रहता है। नगाड़ा व बांसुरी वादन, लोकगीतों के स्वर, नर्तकों का नृत्य, डंडों की टकराहट, घुंघरुओं की छन-छन आदि की समन्वित स्वर लहरियां रात के सन्नाटे को चीरते हुए दूर-दूर तक गूंजती रहती हैं और नृत्य प्रेमियों को खींच लाती हैं। गींदड़ नृत्य करने वाले कलाकार विविध स्वांगों में सजकर आते हैं। महिला पोशाक पहनकर आने वाले कलाकारों को महरी कहा जाता है। यह नृत्य शेखावाटी के कस्बों और गांवों में रात्रि के तीसरे पहर तक चलता रहता है।

इसी प्रकार शेखावाटी में चंग लोकनृत्य की भी स्वस्थ परंपरा है जिसमें नर्तक समूह बनाकर धमाल और लोकगीतों के साथ चंग बजाते हुए नृत्य करते हैं। इस समूह में एक या दो बांसुरी वादक और मंजीरे बजाने वाले भी होते हैं। धमाल व लोकगीतों में भक्ति, करुणा, विरह और श्रृंगार रसों की प्रधानता रहती है। कुछ लोग शेखावाटी के कलाकारों को कोलकाता, मुंबई, सूरत, चेन्नई व अन्य स्थानों पर आमंत्रित कर वहां इन लोक नृत्यों का आयोजन राजस्थानी प्रवासियों के लिए कराते हैं।

गींदड़ और चंग नृत्य स्थलों को झंडियों, पताकाओं और बंदनवारों से सजाया जाता है। मोहल्ला व ग्राम कमेटियां अपने-अपने स्थानों पर इन नृत्यों का व्यवस्थित आयोजन कराती हैं। सीकर, झुंझुनूं और चूरू जिलों के कस्बाई व ग्रामीण क्षेत्र में वहां के सांस्कृतिक संगठन इन लोकनृत्यों को जीवित रखने के

राजकुमार पारीक
सेवानिवृत्त सहायक निदेशक, जनसंपर्क



लिए इनकी प्रतियोगिताएं आयोजित कर कलाकारों को पुरस्कृत करते हैं। एक मुख्य बात यह है कि इन नृत्यों के आयोजन पर ज्यादा धन खर्च करने के बजाय उमंगों की संचित पूंजी अधिक व्यय करनी पड़ती है। वास्तव में ये दोनों लोकनृत्य शेखावाटी की लोक संस्कृति की आत्मा हैं।

इन लोक नृत्यों का एक मुख्य शृंगार इसके साथ गाये जाने वाले लोक गीत भी हैं जिनमें प्रायः हर रस की झलक मिलती है। पीपली, कुरजां, चिरमी, पोदीना, मूमल आदि सभी परंपरागत राजस्थानी लोक गीत गाये जाते हैं जिनके साथ न केवल गवैये और नर्तक बल्कि दर्शक भी झूम उठते हैं। इन गीतों में नायिका के विरह, देवर-भाभी की ठिठोली, नायिका का प्रणय निवेदन, सरहद पर बैठे फौजी भाइयों के देश-प्रेम के किस्से, बेमेल विवाह की चुटकियां, नारी के शृंगार व सौंदर्य, राजा-महाराजाओं के दरबार की होली, पारस्परिक छेड़-छाड़ व तानों आदि का मनमोहक वर्णन होता है।

वास्तव में शेखावाटी अंचल के गींदड़ और चंग लोकनृत्य यहां की समृद्ध लोक-संस्कृति के परिचायक हैं। यह बात अलग है कि आज शेखावाटी की वे बगीचियां वीरान हैं, जहां बैठ कर फाल्गुन के रसिये गोठ-घुघरी जीमते थे। जनपद के वे पनघट समाप्त हो गए जहां पानी भरती महिलाएं गींदड़ और चंग नृत्य के आयोजन की बेबाक समीक्षा किया करती थीं। क्षेत्र की चौपाल व चबूतरे अब सूने हैं जो फाल्गुनी माहौल के वर्षों तक सजीव गवाह रहे हैं। गांवों और कस्बों के घरों की वे देहरियां अब नीरस लगती हैं जहां बैठकर महिलाएं लोक गीतों की पिचकारियां छोड़ा करती थीं।

विशेष आयोजन

शेखावाटी के कुछ कस्बों में होली पर विशेष आयोजन भी होते रहे हैं जिनकी एक अलग पहचान है। इस क्रम में मंडावा कस्बे की आदर्श होली का आयोजन कदाचित अपने ढंग का एक अनूठा स्वरूप है। वैसे होली के त्योहार का आदर्शवाद से दूर-दूर तक संबंध नहीं है, लेकिन मंडावा की होली को देखकर यह धारणा बदल जाती है। सबसे मुख्य बात यह है कि इस आदर्श होली के कार्यक्रम को देखने के लिए कस्बे व आस-पास के गांवों की महिलाएं बड़ी संख्या में सड़कों पर आ जाती हैं, जबकि अमूमन होली के आयोजनों में महिलाओं की उपस्थिति नगण्य रहती है, खासकर तब जब होली के रसियाओं का जुलूस निकल रहा हो।

मंडावा में धुलंडी के दिन निकलने वाले जुलूस में होली के रसियों द्वारा बजाये जाने वाले चंग, लोक गवैयों द्वारा गाये जाने वाले गीत व धमाल तथा नर्तकों के थिरकते अंगों में मस्ती व मधुरता तो भरपूर होती है, पर फूहड़पन जरा भी नहीं होता। इस अवसर पर कोई किसी पर पक्का रंग नहीं डालता बल्कि रंग-बिरंगी गुलाल का प्रयोग होता है। लगभग 9 दशक पूर्व मंडावा को होली की फूहड़ता से मुक्त कराने के लिए इस साफ-सुथरे आयोजन की शुरुआत की गई थी जो अब एक स्थाई वार्षिक आयोजन बन चुका है।

धुलंडी के रोज धर्म-ध्वज की भव्य सवारी के साथ जुलूस निकलता है जिसमें चंग वादन के साथ नर्तकों के दल नाचते गाते चलते हैं। परस्पर गुलाल लगाकर मित्रों से गले मिलने और बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करने की भी स्वस्थ परंपरा है। जिस रास्ते से यह जुलूस निकलता है उस मोहल्ले का दल भी इसमें



छाया: राजू सेनी

शामिल हो जाता है। इस दौरान घरों के चबूतरे व छत तथा जुलूस के रास्ते महिला और बाल दर्शकों से अटे रहते हैं। दिनभर चलने वाला यह जुलूस शाम को गढ़ परिसर में पहुंचता है जहां चंग और धमाल का आकर्षक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाता है। इस अवसर पर कलाकारों के मान-सम्मान एवं पुरस्कार वितरण का आयोजन भी होता है। विदेशी सैलानी भी इस आदर्श होली का भरपूर आनंद उठाते हैं।

शेखावाटी के लक्ष्मणगढ़ कस्बे की होली का स्वरूप भी निराला है। इस कस्बे में होली के दिन दोपहर बाद सदाबहार मोहल्ला गींदड़ नृत्य स्थल पर करीब दो मन दूध की ठंडाई तैयार की जाती है जिसे छोटे-बड़े सभी प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। इसके बाद करीब आधे घंटे तक गींदड़ नृत्य का आयोजन होता है। उसके बाद इन कलाकारों और लोगों का एक जुलूस प्रारंभ होता है जो कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ सूर्यास्त के समय वापस लौट कर विसर्जित होता है। इस जुलूस को घुघरी नाम से जाना जाता है। घुघरी में शामिल सैकड़ों कलाकार चंगों पर नाचते व धमाल एवं लोक गीत गाते हुए चलते हैं। प्रमुख चौराहों पर ये कलाकार गींदड़ नृत्य की प्रस्तुतियां भी देते हैं। महिलाएं अपने घरों की छतों पर बैठकर इस जुलूस को देखती हैं।

होली पर फूहड़ता की पराकाष्ठा का जब जिक्र होता है तो झुंझुनूं शहर की 'होली की हद' जुबां पर आ जाती है। यद्यपि अब यह आयोजन बंद हो गया है तथापि चार-पांच दशक पूर्व तक इस आयोजन की अलग ही धाक थी। आयोजन के समय बच्चे और महिलाएं ही नहीं बल्कि सामान्य पुरुष भी घरों में दुबक जाते थे। इस आयोजन में रंग, कीचड़, नृत्य, गायन और हरकतों का विकृत स्वरूप उजागर होता था। अच्छी बात यह थी कि इस फूहड़ता के बावजूद लोगों में प्रेम और मिलाप बना रहता था। आमजन में इस आयोजन का आकर्षण भी था, इसीलिए घरों में दुबके लोग लुक-छिप कर इसे देखा करते थे। झुंझुनूं का यह आयोजन अब अतीत के पन्नों में समाहित हो गया है।

वस्तुतः शेखावाटी के चंग और गींदड़ लोकनृत्य न केवल समृद्ध लोक संस्कृति प्रतिबिंब हैं, अपितु इनमें सामाजिक समरसता का भाव भी विद्यमान है। संचार क्रांति के दौर में आज भले ही ये लोकनृत्य सिमटते से लग रहे हों, किंतु जहां इनका सजीव आयोजन होता है, वहां आज भी लोगों में इनके प्रति उमंग और उत्साह की पराकाष्ठा देखी जा सकती है। शेखावाटी में जब भी कोई बड़ा मेला अथवा फेस्टिवल आयोजित होता है तो उसके उद्घाटन और समापन समारोहों में चंग और गींदड़ नृत्य की प्रस्तुति अवश्य दी जाती है। ●



होळी रा दो ठिकाणा, अेक ब्रज दूजा बीकाणा

होली मौज-मस्ती, उल्लास और उमंग का त्योहार है। यह आपसी प्रेम और सद्भाव को बढ़ाता है। वैसे तो ब्रज की होली पूरे देश में प्रसिद्ध है, लेकिन बीकानेर की होली भी अपनी विशेष पहचान रखती है। सदियों पुरानी परंपराओं का निर्वहन और यहां के लोगों की अपनायत, जिंदादिली और अलहड़पन का कोई सानी नहीं है। तभी तो इसके बारे में कहा जाता है, 'होळी रा दो ठिकाणा, अेक ब्रज दूजा बीकाणा'।

बीकानेर में होली का रंग लगभग एक महीने पूर्व वसंत पंचमी से ही चढ़ना शुरू हो जाता है। यहां पारंपरिक रूप से होने वाली रम्मतों का पूर्वभ्यास, चंग पर धमाल और मंदिरों में फागोत्सव की शुरुआत इसी दिन से हो जाती है। सरस्वती के पूजन के साथ वासंती बयार के बीच होली का रंग चढ़ना शुरू होता है, जो धीरे-धीरे परवान पर पहुंच जाता है।

होलाटक की शुरुआत के साथ मानो पूरा शहर होली के रंग में रंग जाता है। खेलनी सप्तमी को शहर के ऐतिहासिक नागणेचीजी मंदिर में गुलाल उड़ाने की परंपरा के साथ फाग उत्सव शुरू हो जाता है। शाकद्वीपीय समाज की ओर से 'हंस चढ़ी मां आई भवानी-सहाय करे सब देश री' की टेर के साथ यह उत्सव मनाया जाता है।

इसी दिन शाकद्वीपीय समाज द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में होलाटक की पहली गेर निकाली जाती है। होली की मस्ती शहरी क्षेत्र में थम्भ पूजन के साथ शुरू हो जाती है। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ थम्भ पूजन करते हुए विश्व शांति, सुख और अच्छे जमाने की कामना के साथ थम्भ रोपण किया जाता है। ये थम्भ शहर के प्रमुख मोहल्लों जैसे लालाणी व्यासों का चौक, कीकाणी व्यासों का चौक, सुनारों की गुवाड़ और चौथाणी ओझाओं का चौक आदि में रोपित किए जाते हैं।

हरि शंकर आचार्य
सहायक निदेशक, जनसंपर्क

बीकानेर की रम्मत परंपरा देश भर में विशेष

होलाटक के दौरान लोक नाट्य परंपरा के तहत बीकानेर के परकोटा क्षेत्र में खेली जाने वाली रम्मतें देशभर के लिए आकर्षण का विशेष केंद्र होती हैं। देर रात शुरू होने वाली ये रम्मतें शहर के माहौल को सतरंगी कर देती हैं और यह मस्ती सुबह तक चलती है। ये रम्मतें भक्ति, वीर और शृंगार रस की त्रिवेणी लिए होती हैं, वहीं सामाजिक विद्रूपताओं और समसामयिक स्थिति पर बेहतर तरीके से कटाक्ष भी होता है।

रम्मतों का यह सिलसिला नलथूसर गेट के अंदर 'फक्कड़ दाता की रम्मत' से होता है। इसमें बोहरा-बोहरी, जाट-जाटणी और खाखी अच्छा शगुन मनाते हैं और रम्मत के अन्य कलाकार लावणी, चौमासा और ख्याल गायन से दर्शकों को बांधे रखते हैं। दशकों पुरानी यह रम्मत, आजादी से पूर्व भी अभिव्यक्ति की आजादी की प्रतिनिधि है। इस रम्मत के माध्यम से सामाजिक विद्रूपताओं के अलावा तात्कालिक राजतंत्र और शासन-प्रशासन को आवश्यक सलाह-सुझाव भी दिए जाते रहे हैं।

इसी शृंखला में भट्टड़ों के चौक और बारह गुवाड़ की स्वांग मेहरी की रम्मत, बारह गुवाड़ की ही भक्ति रस आधारित भक्त पूरणमल की रम्मत, बिस्मों के चौक की शहजादी नौटंकी की रम्मत, चौथाणी ओझाओं द्वारा कीकाणी व्यासों के चौक में होने वाली जमना दास कल्ला की रम्मत, आचार्यों के चौक की वीररस प्रधान अमर सिंह राठौड़ की रम्मत, मरुनायक चौक की शृंगार रस आधारित हड़ाउ मेहरी की रम्मत खास हैं।



अमर सिंह राठी रम्मत

बीकानेर की यह रम्मत परंपरा सवा सौ से डेढ़ सौ वर्ष पुरानी है। प्रत्येक रम्मत, अपने उस्ताद की अगुवाई में पूर्ण पारंपरिक तरीके से रात-रात भर खेली जाती है। इन रम्मतों में पात्रों के साथ बोल दोहराने वाले 'टेरियों' की भूमिका भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। इन रम्मतों में तीन-तीन पीढ़ियों के लोग एक साथ भागीदारी निभाते हैं। प्रत्येक रम्मत का अपना कथानक होता है। इन पर ये रम्मतें आगे बढ़ती हैं और आमजन का मनोरंजन करती हैं। इन रम्मतों का पूर्वाभ्यास वसंत पंचमी से प्रारंभ हो जाता है।

साढ़े तीन सौ साल से खेल रहे डोलची मार खेल

होलाष्टक के दौरान पुष्करणा ब्राह्मण समाज के हर्ष और व्यास गोत्र के लोगों के बीच पानी का डोलची मार खेल लगभग साढ़े तीन सौ वर्षों से चला आ रहा है। किवदंती के अनुसार उस समय मृत्युभोज से जुड़े एक ताने के कारण दोनों जातियों में एक विवाद हो गया। इस विवाद को दूर करने के लिए यह खेल प्रारंभ किया गया। इस खेल के दौरान ऊंट के चमड़े से बनी 'डोलची' में पानी भरकर एक-दूसरे पर पानी डालते हैं। खेल के दौरान रखी जाने वाली स्पर्धा के बाद दोनों पक्ष गुलाल उड़ाकर खुशियां मनाते हैं और एक-दूसरे का मुंह मीठा करवाते हैं। वैसे तो हर्षो-व्यासों का डोलची मार खेल सबसे पुराना और लोकप्रिय है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से पुष्करणा ब्राह्मण समाज की ओझा-छंगाणी और जोशी-भादाणी गोत्रों के बीच भी डोलची मार खेल हो रहे हैं।

बिना दुल्हन लौटता है सजा-धजा दूल्हा

होली के दौरान ही हर्ष जाति के दूल्हे की बारात निकालने की परंपरा है। धुलंडी के दिन हर्ष गोन का दूल्हा, मांगलिक गीतों की सुमधुर लहरियों के बीच सभी आवश्यक रस्में निभाता, निर्धारित स्थान पर पहुंचता है। यह दूल्हा, पुष्करणा ब्राह्मण समाज की परंपरा के अनुसार खिड़किया पाग धारण किए होता है। ललाट पर पेवड़ी, कुमकुम, अक्षत, बनियान व पितांबर पहनकर निकलता है, लेकिन बिना दुल्हन लिए लौटता है।

इसके अलावा होली के अवसर पर विभिन्न जातियों द्वारा निकाली जाने वाली गेर भी महत्वपूर्ण होती हैं। इन गेरों का रूट निर्धारित होता है तथा तीन पीढ़ियों के लोग इन गेरों में एक साथ भागीदारी निभाते हैं। इसी प्रकार चोवटिया जोशी परिवार द्वारा धुलंडी के दिन तणी तोड़ने की परंपरा का निर्वहन किया जाता है।



तणी परंपरा

हजारों लोगों की मौजूदगी में उड़ती गुलाल के बीच चोवटिया जोशी परिवार का युवक बिना धार की तलवार से मोटी मूंझ से बनी 'तणी' को तोड़ता है।

साले की होली में होता है सबसे बड़ा होलिका दहन

होलिका दहन देशभर में निर्वहन होने वाली एक समान परंपरा है, लेकिन बीकानेर में यह भी खास होती है। शहरी परकोटे में सबसे बड़ा होलिका दहन जिस स्थान पर होता है उसका नाम ही साले की होली है। रियासत काल से चली आ रही परंपरा के तहत आज भी यहां सालो जी राठी के वंशजों की मौजूदगी में होलिका



दहन किया जा रहा है। वहीं शहर के दम्माणी चौक, आचार्यों का चौक और बारहगुवाड़ पर होलिका दहन के दौरान अपार भीड़ होती है।

इन सभी के अलावा पिछले लगभग तीन दशकों से फागणिया फुटबॉल भी होली के दौरान आयोजित होने वाला महत्वपूर्ण कार्यक्रम बन गया है। फागणिया फुटबॉल आयोजन समिति द्वारा पहले पुष्करणा स्टेडियम और अब थरणीथर ग्राउंड में इसका आयोजन किया जा रहा है। इसके सभी पात्र देवी-देवताओं, नेताओं, उद्यमियों और अतिविशिष्ट व्यक्तियों के स्वांग का रूप धारण कर फुटबॉल खेलते हैं। वहीं खेलणी सप्तमी से धुलंडी तक शहर के प्रमुख मंदिरों और मोहल्लों में फागोत्सव की धूम रहती है। स्वांग का रूप धरे शहरवासी देर रात तक सड़कों पर घूमते हैं। होलिका दहन के बाद इष्ट आराधना की परंपरा का निर्वहन भी किया जाता है। वहीं पूरे सप्ताह गोठ (सामूहिक भोज) का दौर चलता है। विभिन्न गेरों का समाज की अन्य जातियों द्वारा भाव-भीना अभिनंदन किया जाता है। मोहता चौक में होने वाली हड़ाउ मेहरी की रम्मत के दौरान यहां की तीन सदियों पुरानी परम्परा का निर्वहन करते हुए यहां डांडिया का खेल होता है।

कुल मिलाकर होली से पूर्व के सात दिन बीकानेर के लिए बेहद खास होते हैं। ये समय पूरी मस्ती, उल्लास और उमंग के साथ बिताते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि 'जीवै जका खेले फाग, मरग्या जका लेखे लाग'। ●



गोबर का उपयोग प्राचीन काल से ही हमारी संस्कृति का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। गोबर निर्मित पदार्थों का न केवल हमारी संस्कृति में पवित्र स्थान है बल्कि पर्यावरण संरक्षण एवं पारिस्थितिकी तंत्र के लिए भी ऐसे उत्पाद बेहद उपयोगी माने जाते हैं।

राज्य सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी दिशा में जलवायु के अनुकूल विकास पथ एवं नवाचार को प्राथमिकता देते हुए राज्य में गौशालाओं के संरक्षण एवं संवर्धन के लिए गोपालन विभाग के माध्यम से 9 माह का अनुदान दिया जा रहा है। अनुदान के अंतर्गत गौशालाओं को छोटे व बड़े गौवंश के लिए क्रमशः 20 रुपये व 40 रुपये प्रतिदिन राशि दी जा रही है। अब तक राज्य में कुल 2 हजार 317 गौशालाओं में लगभग 11.50 लाख गौवंश को लाभान्वित किया जा चुका है। साथ ही अनुदानित गौशालाओं को निराश्रित गौवंश को रखने के लिए बाध्य करने हेतु निर्देश भी जारी किये गए हैं। वहीं गौशालाओं में आधुनिक उपकरण एवं पशु चिकित्सकों की सहायता से बेहतर गौशाला प्रबंधन प्रदेश में देखा जा सकता है।

गौशालाओं में नवाचारों को दिया जा रहा प्रोत्साहन

राज्य सरकार न केवल गौवंश के संरक्षण के लिए लगातार प्रयासरत है, बल्कि पशुपालकों के आर्थिक एवं सामाजिक संवर्धन के लिए भी संकल्पित है। राज्य में गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा नित नए नवाचारों को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। राज्य में गौशालाओं द्वारा गोबर और गोमूत्र का उपयोग कर विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने का कार्य किया जा रहा है। राज्य में गौशालाओं द्वारा गोबर एवं गोमूत्र का उपयोग आयुर्वेदिक दवाइयां बनाने के साथ विभिन्न प्रकार के सजावटी एवं उपयोगी उत्पाद बनाने में भी किया जा रहा है जिससे गौशालाएं आत्मनिर्भर बनने के साथ रोजगार के साधन सृजित करने वाली संस्थाओं के रूप में उभर कर सामने आ रही हैं। राज्य में गोबर से बने उत्पादों के उत्पादन एवं विपणन के लिए स्टार्टअप भी खुलने लगे हैं। चूंकि राजस्थान गौवंश की दृष्टि से समृद्ध राज्य है ऐसे में यहां गोबर एवं गोमूत्र से बने उत्पादों के लिए अनुकूल माहौल होने के साथ अपार संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं। ऐसी ही संभावनाओं को मद्देनजर रखते हुए शिक्षित युवा भी राज्य में गोबर उत्पादों के स्टार्टअप के जरिए आय एवं रोजगार के संसाधन विकसित कर रहे हैं। ऐसे में गोबर से बने उत्पाद भारतीय अर्थव्यवस्था में एक नया अध्याय बन कर उभर रहे हैं। देश-विदेशों में ऐसे उत्पादों की काफी सराहना की जा रही है, वहीं बाजार में भी अब ऐसे उत्पादों की विशेष मांग देखी जा सकती है।

गोबर से उत्पाद बनाकर गौशालाएं बन रही आत्मनिर्भर

डॉ. अमृता कटारा

सहायक जनसंपर्क अधिकारी

गोबर उत्पाद पर आधारित स्टार्टअप के रूप में उभर रहा राजस्थान

पारंपरिक तौर पर गोबर को खाद एवं घरेलू ऊर्जा (कंडे) के रूप में उपयोग किया जाता है। कृषि वैज्ञानिकों की मानें तो गोबर से बनी जैविक खाद का खेती में उपयोग करने से फसल के उत्पादन के साथ उत्पादों से कई गंभीर बीमारियों से भी निजात मिल सकती है। जैविक उत्पादों के प्रति अब देश-विदेश में भी आमजन में जागरूकता के साथ विशेष रुचि देखी जा सकती है। वर्तमान में जैविक कृषि उत्पादों ने आर्थिक बाजार में एक विशेष पहचान स्थापित कर रोजगार के साधन सृजित करने में अहम भूमिका अदा की है, वहीं आधुनिकीकरण एवं वर्तमान परिप्रेक्ष्य की मांग एवं जरूरत को ध्यान में रखते हुए राज्य की गौशालाओं में गोबर एवं गोमूत्र के उपयोग से थूपबत्ती, अंगरबत्ती, सौंदर्य प्रसाधन एवं आयुर्वेदिक दवाइयां तैयार की जा रही हैं। राज्य में स्टार्टअप गोबर, गोमूत्र एवं कॉटन को मिलाकर कागज का उत्पादन कर रहे हैं। ऐसे कागज से डायरी, कॉपी, किताब एवं सजावटी उत्पाद तैयार किये जा रहे हैं। उसी कागज में दैनिक जीवन में उपयोगी पेड़-पौधों का बीज भी डाला जाता है, जिससे कागज के उपयोग के बाद उसे मिट्टी में डालकर पौधे रोपे जा सकते हैं। इसी के साथ गोबर से त्योहारों के अवसर पर राखी, लक्ष्मी-गणेश, गोवर्धन एवं अन्य देवी देवताओं की प्रतिमाएं बनाने के साथ होली के रंग भी तैयार किये जा रहे हैं जिनके उपयोग के बाद पानी में अपघटन कर खाद के रूप में काम में लिया जा सकता है। ऐसे स्टार्टअप राज्य की गौशालाओं से गोबर खरीद कर उन्हें आर्थिक सम्बल प्रदान करने के साथ रोजगार के नित नए साधन उपलब्ध करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं।

गोबर से बने उत्पाद न केवल पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने के साथ पर्यावरण संरक्षण एवं पौधारोपण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं बल्कि पशुपालकों को आर्थिक एवं सामाजिक संबल भी प्रदान करने का कार्य करते हैं, जिससे पशुपालकों के लिए पशु बोझ न बनकर आय एवं रोजगार का साधन बन जाता है। वहीं गौशालाओं से गोबर एवं गोमूत्र के रूप में निकलने वाले अपशिष्ट भी आर्थिक मूल्य में परिवर्तित हो जाते हैं। ●





भरतपुर का 290वां स्थापना दिवस

लोहागढ़ के रूप में विख्यात भरतपुर के गौरवशाली इतिहास एवं समृद्ध विरासत को सहेजने और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के चहुंमुखी विकास के आह्वान पर एकजुटता से आगे बढ़ने के संकल्प के साथ ऐतिहासिक भरतपुर का 290वां स्थापना दिवस समारोह 13 फरवरी, 2023 को विविध कार्यक्रमों सहित सम्पन्न हुआ।

जिला प्रशासन, नगर निगम एवं लोहागढ़ विकास परिषद के तत्वावधान में आयोजित सात दिवसीय कार्यक्रम में पहले दिन किशोरी महल एवं यातायात चौराहा स्थित महाराजा सूरजमल की 316वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा पर उनके वंशज पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह, मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग तथा अन्य नागरिकों ने श्रद्धासुमन अर्पित किए। नगर निगम आयुक्त सुभाष गोयल की देखरेख में 13 से 18 फरवरी तक वार्डों के अनुसार विशेष सफाई अभियान चलाया गया। शिक्षा विभाग पुरातत्व एवं वन विभाग के सहयोग से आयोजित हैरिटेज एवं नेचुरल वॉक तथा आयुर्वेद विभाग के सहयोग से योग कार्यक्रम हुआ। मास्टर आदित्येन्द्र स्मृति भाषण प्रतियोगिता तथा शिक्षाविद डॉ. दारूदयाल गुप्ता स्मृति चित्रकला प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने उत्साह से भाग लिया। राजस्थान ब्रजभाषा अकादमी एवं लोहागढ़ विकास परिषद के तत्वावधान में श्री हिन्दी साहित्य समिति के सभागार में ब्रजभाषा कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। भरतपुर स्थापना की यज्ञस्थली फुलबाड़ी से कलश यात्रा में महिलाओं ने भाग लिया। स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर लोहागढ़ दुर्ग स्थित शहीद स्मारक, बिहारी जी मंदिर, गंगा मंदिर सहित अन्य स्थानों पर दीपदान कार्यक्रम आयोजित किया गया। महिलाओं तथा पुरुषों ने दीप प्रज्वलित किए। सरकारी भवनों, चौराहों, इत्यादि पर रोशनी सजावट से शहर जगमगा उठा।

भरतपुर के 290वें स्थापना दिवस पर शहर के पांच स्थलों से यातायात चौराहा स्थित महाराजा सूरजमल स्मारक तक छात्र-छात्राओं ने स्वाभिमान मार्च निकाला। नगर निगम द्वारा आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में प्रबुद्ध लोगों ने विचार

गुलाब बत्रा
वरिष्ठ पत्रकार

व्यक्त किए। जिला कलक्टर ने इस स्थापना दिवस को महोत्सव के रूप में मनाने तथा भावी पीढ़ी को इस दिशा में आगे बढ़ने का आह्वान किया। विश्वप्रिय शास्त्री पार्क में पर्यटन विभाग की ओर से आयोजित सांस्कृतिक संध्या में बॉलीवुड गायिका श्रद्धा पंडित के गीतों पर दर्शक झूम उठे। ●

फार्म-1 (नियम 3 देखिये)

- | | |
|--|--|
| 1. समाचार पत्रिका का नाम | : राजस्थान सुजस |
| 2. समाचार पत्रिका की भाषा | : हिन्दी |
| 3. प्रकाशन का स्थान | : सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
राजस्थान, जयपुर |
| 4. प्रकाशन की अवधि | : मासिक |
| 5. मुद्रक का नाम | : पुरुषोत्तम शर्मा |
| क्या भारतीय नागरिक है | : हां |
| (यदि विदेशी है तो मूल देश) | : नहीं |
| 6. पता प्रेस | : फ़्लिन्ड 'ओ' लैण्ड, 22 गोदाम, जयपुर
रैनबो ऑफ़सेट प्रिन्टर्स, सुदर्शनपुरा, जयपुर
प्रीमियर प्रिंटिंग प्रेस, रामनगर, जयपुर
मैक्स कृष्णा प्रिन्टर्स, सुदर्शनपुरा, जयपुर |
| 7. सम्पादक का नाम | : अलका सक्सेना |
| क्या भारतीय नागरिक है | : हां |
| (यदि विदेशी है तो मूल देश) | : नहीं |
| पता | : सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग
राजस्थान सचिवालय, जयपुर |
| 8. उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार-पत्र के स्वामी हो तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक से साझेदार या हिस्सेदार हो। | |
| मैं पुरुषोत्तम शर्मा एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार ऊपर दिया गया विवरण सत्य है। | |

पुरुषोत्तम शर्मा

पाली का ऐतिहासिक सोमनाथ शिवालय

पाली शहर में स्थित 9वीं शताब्दी का सोमनाथ शिवालय जन-जन की आस्था का केंद्र है। मंदिर का सभा मंडप, बाहरी प्राचीर और शिखर उत्कृष्ट शिल्पकला के प्रमाण हैं। वर्तमान में यह मंदिर राजस्थान सरकार के देवस्थान विभाग के अधीन है। यहां महाशिवरात्रि पर मेला भरता है। श्रावण मास में विशेष आयोजन होते हैं।

आलेख व छाया: विनय सोमपुरा सहायक जनसंपर्क अधिकारी



तस्वीर बदलाव की

तब



अब



राजस्थान सरकार के परीक्षण कार्यक्रम और अन्य योजनाओं की विस्तृत जानकारी
<https://jankalyan.rajasthan.gov.in> पर देखी जा सकती है।

@DIPRRajasthan

